



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052023-246180
CG-DL-E-31052023-246180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945

No. 130]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसजी)-03/2022

विषय- भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के अन्तर्गत कोरिया गणराज्य से “फैरो मोलीब्डेनम” के आयातों से संबंधित द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

- फा. सं. 22/03/2022-डीजीटीआर.—भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 और भारत सरकार तथा कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 2.22 को ध्यान में रखते हुए दि इंडियन फैरो अलाय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, प्रीमियर एलॉयज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बोन मेटल एंड अलॉय कार्पोरेशन और टीम फैरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड सीईपीए तथा द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के अनुसार व्यापार उपचार महानिदेशक (जिन्हें आगे ‘महानिदेशक’ या प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष कोरिया (जिसे आगे ‘कोरिया गणराज्य’ या ‘संबद्ध देश’ भी कहा गया है) से “फैरो मोलीब्डेनम” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा

गया है) के आयातों में वृद्धि से संबंधित टैरिफ रियायतों के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने और उनके निलंबन की सिफारिश करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, महानिदेशक ने नियम 4 के अन्तर्गत जांच की शुरुआत की ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या फ़ैरो मोलीब्डेनम के आयात 'बढ़े हुए आयात' हैं, क्या उनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और क्या द्विपक्षीय रक्षोपायों को लगाने की आवश्यकता है (या यदि हां, तो उसकी समयावधि)। जांच की शुरुआत करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 03/2022 के माध्यम से जारी की गई थी।
3. उसके बाद महानिदेशक ने जांच संपन्न की और केन्द्र सरकार के विचारार्थ वर्तमान जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

ख. प्रक्रिया

4. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है-

- क. महानिदेशक ने जांच की शुरुआत की एक सार्वजनिक सूचना जारी की और दिनांक 30 सितंबर, 2022 को उसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया था।
- ख. महानिदेशक ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केन्द्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के ज़रिए कोरिया गणराज्य की सरकार, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों तथा भारत में ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं और आवेदन में यथा-उल्लिखित हितवद्ध पक्षकारों को उक्त नियमावली के नियम 5(2) के अनुसार दिनांक 30 सितंबर, 2022 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी।
- ग. नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय अंश की प्रति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों में केन्द्र सरकार, भारत में कोरिया गणराज्य के दूतावास के ज़रिए कोरिया गणराज्य की सरकार और संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को भेजी गई थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर हितवद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।
- घ. महानिदेशक ने द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत संबंधी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार कोरिया गणराज्य में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थी और उन्हें विहित तरीके और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर देकर संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था:
 - i. एसईएच एमएंडएस
 - ii. कोरवन कंपनी लिमिटेड
 - iii. इनरटेक कंपनी लिमिटेड
 - iv. ह्वासंग मेटल कंपनी लिमिटेड
- ड. जारी प्रश्नावली के उत्तर में एसईएच एमएंडएस ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक इस पर विचार किया गया है।
- च. महानिदेशक ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को विहित ढंग और तरीके से आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने और 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए प्रश्नावलियां भेजी थी।
 - i. एडवेंट फाउंडरी एंड एलायड सप्लाइज प्राइवेट लिमिटेड
 - ii. एशिया मेटल्स एंड फ़ेरो अलायज
 - iii. अवतार स्टील लिमिटेड

- iv. कलकत्ता मेटल डिपो प्राइवेट लिमिटेड
 - v. चंदन स्टील लिमिटेड
 - vi. डी.एस. अलायज प्राइवेट लिमिटेड
 - vii. डालिनी मेटल्स एंड अलायज प्राइवेट लिमिटेड
 - viii. आईएसएमटी लिमिटेड
 - ix. जे पूनमचंद एंड संस प्राइवेट लिमिटेड
 - x. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
 - xi. कल्याणी स्टील्स लिमिटेड
 - xii. कोठारी मेटल्स लिमिटेड
 - xiii. केआर मेटल्स एलएलपी
 - xiv. लक्सकोन स्टील्स लिमिटेड
 - xv. एम एम सेरेमिक्स एंड फेरो अलायज
 - xvi. मेटल अलायज (इंडिया)
 - xvii. मेटेलिक कैरो एलॉयज एलएलपी
 - xviii. नमोह अलायज प्राइवेट लिमिटेड
 - xix. ओसवाल मिनरल्स लिमिटेड
 - xx. फूलचंद भगत सिंह एलएलपी
 - xxi. राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड
 - xxii. आरएसएम सुपर मेटल्स एलएलपी
 - xxiii. सारलोहा एडवांस्ड मैटिरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xxiv. संजय कमर्शियल कंपनी
 - xxv. सिंघानिया इंटरनेशनल लिमिटेड
 - xxvi. एसआरसी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xxvii. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
 - xxviii. सिनर्जी स्टील्स लिमिटेड
 - xxix. टाटा स्टील लिमिटेड
 - xxx. टीम रेमिडीज एलएलपी
 - xxxi. विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड
- छ. जारी प्रश्नावली के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है:
- i. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ('जेएसएल')
 - ii. जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड ('जेएसएचएल')
 - iii. सारलोहा एडवांस्ड मैटिरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

- v. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कं.
- ज. महानिदेशक ने विचाराधीन उत्पाद के अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों से विहित प्रपत्र और ढंग से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए और 30 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचार मांगते हुए एक प्रश्नावली भेजी थी। महानिदेशक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में किसी अन्य भारतीय उत्पादक ने जवाब नहीं दिया है। आवेदकों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
- झ. निम्नलिखित पक्षकारों ने जांच की प्रक्रिया के दौरान अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक इन पर विचार किया गया है:
- कोरिया गणराज्य की सरकार
 - सियाह एमएंडएस
 - अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ('एएसपीए')
 - जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड
 - जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड
 - जेडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
 - सारलोहा एडवांस्ड मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
- ञ. महानिदेशक ने 1 अक्तूबर, 2021 – 31 मार्च, 2022 को बिल्कुल हाल की अवधि और 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2022 को जांच अवधि माना है।
- ट. नियमावली के नियम 5(6) के अनुसार 4 जनवरी, 2023 को एक मौखिक सुनवाई हुई थी, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों और आवेदकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। मौखिक सुनवाई में विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने और खंडन अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए थे और उनसे खंडन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- ठ. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के ज़रिए एक दूसरे के साथ अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश का आदान-प्रदान करने की सलाह दी गई थी।
- ड. संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से अनुरोध किया गया था। महानिदेशक ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयात की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंड के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ढ. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर संगत समझे जाने पर इस अंतिम जांच परिणाम में महानिदेशक द्वारा ध्यान दिया गया है।
- ण. जांच की प्रक्रिया के दौरान महानिदेशक ने आवेदकों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना, जो इन अंतिम जांच परिणामों का आधार है, की सत्यता से संभव और संगत तथा आवश्यक समझी गई सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया है।
- त. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार या आवेदक ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां महानिदेशक ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

थ. वर्तमान जांच परिणाम के अगोपनीय अंश में “****” चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

द. महानिदेशक ने इस अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित शब्द-संक्षेप का प्रयोग किया है:

क्र.सं.	शब्द संक्षेप	पूर्ण विवरण
1	फेमो	फेरो मोलीब्डेनम
2	मोली	मोली ऑक्साइड
3	आवेदक	बून मेटल एंड अलॉय कापॉरेशन, प्रीमियर अलॉयज एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड एंड टीम फेरो अलायज प्राइवेट लिमिटेड
4	आवेदक संगठन	दि इंडियन फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन
5	हितबद्ध पक्षकार	आवेदक और आवेदक एसोसिएशन को छोड़कर सभी हितबद्ध पक्षकार
6	भारतीय उद्योग	आवेदक, समर्थक और फेमो के अन्य उत्पादक
7	जांच की अवधि	जांच की अवधि- अप्रैल 2018 से मार्च 2022
8	बिल्कुल हाल की अवधि	अक्तूबर 2021 से मार्च 2022
9	नियमावली	भारत-कोरिया आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली , 2017
10	सीईपीए	भारत सरकार और कोरिया सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार
11	डीजीसीआईएंडएस	वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

ग. सूचना का स्रोत

- वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच शुरुआत की सूचना में यथा-अधिसूचित विचार की गई अवधि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2022 है जबकि बिल्कुल हाल की अवधि के रूप में 1 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 पर विचार किया गया है। इसके अलावा, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह चिंता जताई है कि क्या रियायतों के कारण आयात में वृद्धि हुई है, इसलिए महानिदेशक ने 2008-09 की अवधि से जो टैरिफ रियायतों की शुरुआत से पहले की अवधि, के आयात आंकड़ों पर विचार किया है।
- संबद्ध वस्तु के आयात संबंधी ब्यौरे के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था। महानिदेशक ने अप्रैल, 2008 से दिसंबर, 2022 की अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना हेतु डीजीसीआईएंड के आंकड़ों पर भरोसा किया है। यह देखा गया है कि इस उत्पाद का सौदा मोलिब्डेनम की विभिन्न शुद्ध रूपों में किया गया है। अतः, आयातों की मात्रा नीचे जांच के अनुसार एक समतुल्य मोलिब्डेनम की मात्रा के आधार पर निर्धारित की गई है।
- व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अन्तर्गत रियायतों पर विचार करने के बाद फेमों के आयातों पर सीमाशुल्क की दर निम्नानुसार है। यह देखा गया है कि उत्पाद एमएफएन दर 2012 की अवधि तक सीईपीए में विचारित टैरिफ दर से कमतर थी। तथापि, टैरिफ रियायतों का प्रभाव 2014 से शुरू हुआ। इस उत्पाद पर 2017 से पूर्ण टैरिफ रियायत रही हैं। वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ 2009-10 और 2013-14 के बीच की अवधि को 'रियायत पूर्व अवधि' माना गया है, 2013-14 से 2015-16 के बीच की अवधि को 'रियायत अवधि के दौरान' और 2017-18 से की अवधि को 'रियायत पश्चात अवधि' के रूप में माना गया है। एमएफएन शुल्क और करार तथा संगत सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार शुल्क की दर निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	एमएफएन दरें	कोरिया गणराज्य	सीमा शुल्क अधिसूचना सं.
1	2009	5%	8.75%	152/2009 – सीमा शुल्क
2	2010	5%	7.50%	137/2010 – सीमा शुल्क
3	2011	5%	6.25%	123/2011 – सीमा शुल्क
4	2012	5%	5%	66/2012 – सीमा शुल्क
5	2013	5%	3.75%	54/2013 – सीमा शुल्क
6	2014	5%	2.50%	35/2014 – सीमा शुल्क
7	2015	5%	1.25%	60/2015 – सीमा शुल्क
8	2016	5%	0%	66/2016 – सीमा शुल्क

घ. विचाराधीन उत्पाद

घ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं -

- क. भारतीय उद्योग एक समान मोलिब्डेनक मात्रा बनाए रखने में और स्थिर आपूर्ति तथा बाजार में बिक्री पश्चात सेवा देने में असमर्थ है।
- ख. भारतीय उद्योग प्रयोक्ता उद्योग की तकनीकी और मेटलर्जिकल अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है।
- ग. कोरिया गणराज्य से आयातित उत्पाद में रोस्टेड मोलिब्डेनक का उच्चतर अनुपात है, जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादक नहीं कर सकते हैं।
- घ. भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद में अलग-अलग विनिर्माण प्रक्रिया के कारण अंतर है।
- ड. घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में सिलिकान, फास्फोरस या नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है। इस्पात उत्पादन के लिए ये कम होनी चाहिए।
- च. कोरियाई निर्यातक विचाराधीन उत्पाद की अपेक्षित मोलिब्डेनक मात्रा के संबंध में अपनी उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीयता और आपूर्ति की निरंतरता के लिए जाने जाते हैं।
- छ. वर्तमान जांच में विभिन्न प्रयोक्ताओं ने यह पुष्टि की है कि भारतीय प्रयोक्ता उच्च गुणवत्ता के लिए कोरियाई उत्पाद को पसंद करते हैं।

घ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- क. फेमो एक अलॉय है जिसे लोहा और मोली के संयोग से बनाया जाता है। यह एक ठोस कारक एजेंट है और इसे अनेक अलॉय स्टील, जो ताप उपचारित होते हैं, में पाया जाता है।
- ख. फेमो अनेक ग्रेडों में आता है, यद्यपि अधिकांशतः इसे केवल दो ग्रेडों (जिन्हें शुद्धताओं के अनुसार परिभाषित किया जाता है) में उत्पादित होता है, जिनके शुद्ध मोली की मात्रा 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच होती है।

- ग. फेमो के सर्वाधिक अनुप्रयोग फेरस अलॉय में होते हैं। मोली मात्रा की रेंज के आधार पर यह मशीन औजार और उपकरण, सैन्य हार्डवेयर, रिफायनरी ट्यूबिंग, लोड-बियरिंग पाटर्स और रोटरी ड्रिल्स के लिए उपयुक्त होता है।
- घ. इस्पात उद्योग फेमो का सबसे बड़ा प्रयोक्ता है जो विश्व भर में खनित लगभग 80 प्रतिशत फेमो की खपत करता है।
- ड. भारतीय उद्योग ने कोरिया से आयातित सभी ग्रेडों की आपूर्ति की है और इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि प्रयोक्ता उद्योग की तकनीकी और मटलर्जिकल अपेक्षाओं को भारतीय उत्पादकों द्वारा पूरा नहीं किया जाता है।
- च. घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ता उद्योग द्वारा यथा-अपेक्षित मोली मात्रा प्रदान की है। भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड अपनी संपूर्ण जरूरतों की खरीद भारत से करते हैं और यह दर्शाता है कि आपूर्ति की गई गुणवत्ता के संबंध में कोई समस्या नहीं है।
- छ. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

घ.3 महानिदेशक द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'फेरो मोलीब्डेनम' है, जिसे इस अधिसूचना में फेमो भी कहा गया है तथा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के एचएस कोड 72027000 के अन्तर्गत आता है।
11. फेमो एक अलॉय है जिसे लोहा और मोलिब्डेनम के संयोग से बनाया जाता है। फेमो एक ठोस कारक एजेंट है और इसे अनेक अलॉय स्टील, जो ताप उपचारित होते हैं, में पाया जाता है। फेमो स्टेनलेस स्टील में जंग को रोकता है और लोहे में मिलाने पर यह ऑस्टेनाइट में मजबूत और कठोर भी हो जाता है। फेमो अनेक ग्रेडों में आता है, यद्यपि अधिकांशतः इसे केवल दो ग्रेडों (जिन्हें शुद्धताओं के अनुसार परिभाषित किया जाता है) में उत्पादित होता है, जिनके शुद्ध मोली की मात्रा 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच होती है।
12. फेमो का सबसे बड़ा अनुप्रयोग फेरो अलॉयज में होता है और मोलिब्डेनम मात्रा रेंज के आधार पर यह मशीन टूल और उपकरण, सैन्य हार्डवेयर, रिफायनरी ट्यूबिंग, लोड बियरिंग पाटर्स और रोटरी ड्रिल्स के लिए उपयुक्त होता है। फेमो का प्रयोग कारों, ट्रकों, लोकोमोटिव्स और जलपोतों में भी होता है। इसके अलावा, फेमो का प्रयोग ऐसे स्टेनलेस और ताप प्रतिरोधी स्टील में होता है, जिनमें सिंथेटिक ईंधन और रासायनिक संयंत्रों, हीट एक्सचेंजर्स, पावर जनरेटर, तेल शोधन उपकरण, पम्प, टर्बाइन ट्यूबिंग, शिप प्रोपेलर्स, प्लास्टिक्स और एसिड स्टोरेज कंटेनर के भीतर, टूल स्टील में लगाया जाता है। फेमो के उच्च प्रतिशत रेंज के साथ इसे उच्च स्टील मशीन कलपुर्जों, कोल्ड वर्क टूल्स, ड्रिल बिट्स, पेचकस, ड्राई, छेनी, हैवी कास्टिंग, बाल और रोलिंग मिल्स, रोल्ल्स, सिलेंडर ब्लॉक्स, पिस्टन रिंग्स और बड़ी ड्रिल बिट्स में प्रयोग किया जाता है।
13. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि भारतीय उद्योग एक समान मोलिब्डेनम मात्रा बनाए रखने, आपूर्ति स्थिरता, बिक्री पश्चात सेवा और सिलिकॉन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन मात्रा को बनाए रखने में असमर्थता के कारण नुकसान उठाता है। महानिदेशक नोट करते हैं कि अपनी दलील के समर्थन में इन हितबद्ध पक्षकारों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह देखा गया है कि भारतीय उद्योग के पास पहले (2015-16 में) मांग में 89 प्रतिशत हिस्सा रहा था और कोरिया से आयात अत्यंत सीमित थे। अतः ऐसा नहीं लगता है कि आयातों में वर्तमान वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योग की जरूरतों के अनुसार संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता के कारण हुई है। वर्तमान क्षति अवधि में भी भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा 2019-20 में 79 प्रतिशत था। यह भी देखा गया है कि भारत में उत्पाद का एक सबसे बड़ा उपभोक्ता जिंदल स्टेनलेस ने अपनी समस्त जरूरतों की आपूर्ति घरेलू बाजार से की है और आयातों का सहारा नहीं लिया है। महानिदेशक मानते हैं कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि आयातों में अचानक वृद्धि उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति करने में भारतीय उद्योग की असमर्थता के कारण हुई थी।
14. यह तर्क दिया गया है कि कोरियाई उत्पादक 60 प्रतिशत मोली मात्रा से अधिक के उत्पाद की आपूर्ति करते हैं और भारतीय उद्योग इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस दलील के समर्थन में कोई साक्ष्य

नहीं दिया गया है। आवेदकों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उन्होंने 60 प्रतिशत मोली मात्रा से अधिक और कम दोनों वाले फेमो का उत्पादन और बिक्री की है। अतः हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

15. समान वस्तु को द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(2) में निम्नानुसार प्रावधान है:

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनका यहां प्रयोग हुआ, और परिभाषित नहीं किया गया, परंतु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) में परिभाषित है, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जैसा उनके लिए उन अधिनियमों में प्रदत्त है।

16. अतः, महानिदेशक ने सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्कों की पहचान और आकलन) नियमावली के अनुसार समान वस्तु की परिभाषा पर भरोसा किया है जिसमें समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

(ड.) "समान वस्तु" का अर्थ ऐसी कोई वस्तु है जो जांच के अधीन वस्तु से सभी तरह से समान या समरूप हो;

17. रिकॉर्ड में सूचना और साक्ष्य के आधार पर महानिदेशक मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और कोरिया गणराज्य से आयातित संबद्ध वस्तु के कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु कोरिया गणराज्य से आयातित उत्पाद से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से भी तुलनीय है। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। महानिदेशक मानते हैं कि आवेदकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध वस्तु की समान वस्तु है।

ड. घरेलू उद्योग

ड.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत उत्पादन के आंकड़ों और आवेदन में आवेदकों द्वारा भरोसा किए गए आंकड़ों के बीच असमानता है।
- ख. आवेदकों से प्रत्येक घरेलू उत्पादक की क्षमता बताने के लिए कहना चाहिए।
- ग. अन्य उत्पादकों के भाग न लेने के कारण की जांच की जानी चाहिए।
- घ. विचाराधीन उत्पाद के कुल 15 उत्पादक हैं, जिनमें से केवल 3 ने जांच में भागीदारी की है।
- ड. तीन आवेदक उत्पादक का कुल उत्पादन में 39-42 प्रतिशत हिस्सा है जो प्रमुख हिस्से से कम है।
- च. आवेदकों द्वारा भारत में सभी उत्पादकों की एक सूची नहीं दी गई है।
- छ. 1 या 2 अधिक उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त भागीदारी से भारतीय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक स्पष्ट प्रमुख हिस्सा बन गया होता।
- ज. शेष 12 घरेलू उत्पादकों के भागीदारी न करने की जांच होनी चाहिए।
- झ. आवेदक घरेलू उत्पादक तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की क्षमता के बीच अंतर से पता चलता है कि वे घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि नहीं हैं।
- ञ. भारत में प्रत्येक घरेलू उत्पादक की क्षमता या अनुमानों को प्रतिवादी के लिए स्थिति पर आगे टिप्पणी हेतु प्रदान किया जाना चाहिए।
- ट. प्रस्तुत समर्थन पत्रों के बावजूद शेष 40 प्रतिशत भारतीय उत्पादन के कार्य-निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

- ठ. यूएस – हॉट-रोल्ल्ड स्टील मामले में डब्ल्यूटीओ ने माना था कि जांचकर्ता प्राधिकारियों को या तो समग्र रूप से उद्योग की जांच करनी चाहिए या पर्याप्त स्पष्टीकरण देना चाहिए कि घरेलू उद्योग के अन्य हिस्सों की जांच करना क्यों आवश्यक नहीं है।
- ड. नियम 4 में भारतीय उद्योग द्वारा समर्थन का प्रावधान नहीं है। कुल घरेलू उत्पादन में समर्थकों का हिस्सा घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करते समय शामिल नहीं करना चाहिए।
- ढ. आवेदन का समर्थन करने वाले पांच उत्पादकों में से केवल दो एसोसिएशन के सदस्य हैं।

ड.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह आवेदन दि इंडियन फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है, जो विचाराधीन उत्पाद के लिए शीर्ष एसोसिएशन है। उत्पाद के लगभग 10 उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य हैं।
- ख. आवेदकों ने अपने सदस्यों से एकत्र आंकड़ों से एसोसिएशन के अनुमानों के आधार कुल उत्पादन ज्ञात किया है।
- ग. प्रीमियर अलॉयज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बून मेटल एंड अलॉय कार्पोरेशन और टीम फेरो अलॉज प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का 42 प्रतिशत है।
- घ. आवेदन लालवानी फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, नोरटेक फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, एस्सल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमर ट्रेडर्स लिमिटेड और रामा फेरो अलॉयज एंड फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है।
- ड. समर्थकों और आवेदकों का भारतीय मांग में 8 प्रतिशत हिस्सा है।
- च. नियमावली का नियम 2(च) 'गंभीर क्षति' को 'घरेलू उद्योग की स्थिति में अत्यधिक समग्र विकृति' के रूप में परिभाषित करता है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति की जांच अनिवार्य है। अन्य भारतीय उत्पादकों के निष्पादन की जांच करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।
- छ. अन्य घरेलू उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट पर समान वस्तु के संबंध में उनके निष्पादन के आकलन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सभी बहु-उत्पाद कंपनियां हैं।
- ज. प्रमुख हिस्से की अपेक्षा के संबंध में भारत-लोहा और इस्पात उत्पादों के आयातों पर कतिपय उपाय मामले में पैनल की रिपोर्ट पर ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह माना गया था कि मात्रात्मक तत्वों के अलावा उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की गुणवत्ता को भी देखना अपेक्षित है।
- झ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़े आवेदकों द्वारा दावा की गई स्थिति से अलग भारतीय उद्योग की स्थिति कैसे दर्शाते हैं।

ड.3 महानिदेशक द्वारा जांच

20. नियम 2(ख) द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली, 2017 के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"घरेलू उद्योग" का अभिप्राय उत्पादक -

- (i) भारत के सीमा क्षेत्र में प्रचालित होने वाले समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के समग्र रूप से उत्पादक; अथवा
- (ii) वे उत्पादक जिनका समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी सामानों के सामूहिक उत्पादन में उन सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात हो;

21. जांच शुरुआत अधिसूचना का आवेदन दि इंडियन फेरो अलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित उत्पादकों के साथ किया था:-

- क. बून मेटल एंड अलॉय कापरेरेशन
ख. प्रीमियर अलॉय एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग. टीम फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
22. जांच शुरुआत के अनुपालन में निम्नलिखित अन्य उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है। इसके अलावा, इन उत्पादकों ने अपनी क्षमता उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना प्रदान की है:
- क. अमर ट्रेडर्स लिमिटेड
ख. एस्सल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग. लालवानी फेरो अलायज प्राइवेट लिमिटेड
घ. नॉरटेक फेरो अलायज प्राइवेट लिमिटेड
ड. रामा फेरो अलॉयज एंड फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड
23. आवेदकों ने बताया है कि उद्योग की प्रकृति को देखते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन से संबंधित कोई प्रकाशित सूचना नहीं है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सकल घरेलू उत्पादन से संबंधित घरेलू उद्योग के दावे पर प्रश्न उठाते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त सूचना स्थिति तालिका में विचारित सूचना से अलग है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि वह अपने सदस्यों के उत्पादन या बिक्री का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और उसने यह सूचना केवल अनुमानों के आधार पर तथा एसोसिएशन में प्रमुख कार्यकारियों के अनुभव के आधार पर दी है। एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि इन उत्पादकों का उत्पादन लगभग 6000 एमटी है। यह जांच करने के लिए कि क्या आवेदक स्थिति संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं, महानिदेशक ने आवेदकों तथा एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त भारतीय उत्पादन पर विचार किया है।
24. यह देखा गया है कि 3 उत्पादकों ने आवेदन दायर किया है और 5 उत्पादकों ने आवेदन के समर्थक के रूप में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
25. हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताया है कि 15 उत्पादकों में से केवल 3 उत्पादक भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। महानिदेशक ने अन्य उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र की जांच की है और यह देखा गया है कि भारतीय उत्पादकों की क्षमता कम से कम 250 एमटी से अधिक से अधिक 2000 एमटी की रेंज में है। यह देखा गया है कि आवेदक कंपनियां भारत में सबसे बड़ी उत्पादक हैं। यद्यपि 3 आवेदकों का संचयी उत्पादन भारतीय उत्पादन का 40 प्रतिशत बनता है, तथापि 5 समर्थक उत्पादकों का संचयी उत्पादन 20 प्रतिशत बनता है, जबकि गैर-भागीदार शेष उत्पादकों का संचयी उत्पादन 40 प्रतिशत बनता है। 6 अन्य उत्पादकों ने भी महानिदेशक को समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है। तथापि, ये समर्थन पत्र खंडन अनुरोध के बाद और काफी देरी से प्राप्त हुए थे। इस निर्धारण के लिए इन समर्थन पत्रों पर विचार नहीं किया गया है। यह भी नोट किया गया है कि वर्तमान उत्पाद में घरेलू उत्पादक एमएसएमई कंपनियां हैं।
26. आवेदकों द्वारा अनुमानित उत्पादन पर कुल भारतीय उत्पादन ज्ञात करने हेतु विचार किया गया है। महानिदेशक ने अलग-अलग कंपनियों द्वारा सूचित उत्पादन पर विचार किया है। उन घरेलू उत्पादकों का उत्पादन जो महानिदेशक के समक्ष नहीं आए हैं, पर एसोसिएशन द्वारा आकलित उत्पादन के आधार पर विचार किया गया है। कंपनी-वार उत्पादन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल से सितंबर 21	अक्तूबर 21 से मार्च 22
क	आवेदक	2,572	2,183	2,376	1,397	1,107
1	टीम फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	***

2	प्रीमियर अलॉयज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	***
3	बूम मेटल एंड अलॉय कारपोरेशन	***	***	***	***	***
ख	समर्थक	1898	1266	1180	682	572
4	लालवानी फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	***
5	नॉरटेक फेरो अलायज प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	***
6	एस्सल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***	***
7	अमर ट्रेडर्स लिमिटेड	***	***	***	***	***
8	रामा फेरो अलायज एंड फाइनैस प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***	***
ग	अन्य उत्पादक	1,719	2,344	2,383	1,112	1,119
घ	भारतीय उत्पादन	6,189	5,793	5,939	3,191	2,798
ड.	आवेदकों का हिस्सा	42%	38%	40%	44%	40%
च	समर्थकों का हिस्सा	31%	22%	20%	21%	20%

27. भारतीय उत्पादन में 2021-22 की अवधि में आवेदकों का हिस्सा 40 प्रतिशत है जबकि समर्थकों का हिस्सा 20 प्रतिशत है।
28. आवेदकों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा डब्ल्यूटीओ के अनेक निर्णय प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें पाटनरोधी उपायों में 'प्रमुख हिस्से', के अर्थ की जांच की गई है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4 में निम्नानुसार प्रावधान है:
- 4.1 इस करार के प्रयोजनार्थ 'घरेलू उद्योग' शब्द की व्याख्या समान उत्पादों के समग्र घरेलू उत्पादकों के रूप में या ऐसे उत्पादकों के रूप में की जाएगी जिनका उत्पाद का समग्र उत्पादन उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, इसके अपवाद है कि
29. महानिदेशक नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार और द्विपक्षीय रक्षोपाय नियम, दोनों ने 'एक प्रमुख हिस्सा' शब्दों के ज़रिए घरेलू उद्योग को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, ऐसा कोई डब्ल्यूटीओ निर्णय नहीं है जो रक्षोपाय जांच के मामले में असंगठित उद्योगों के लिए 'प्रमुख हिस्सा' के अर्थ से संबंधित हो। अतः, महानिदेशक ने डब्ल्यूटीओ द्वारा 'प्रमुख हिस्से' के मुद्दे की जांच करने के लिए पाटनरोधी उपायों के मामले में डब्ल्यूटीओ निर्णयों का संदर्भ दिया है।
30. अर्जेन्टीना – ब्राजील से पोल्ट्री पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के मामले में डब्ल्यूटीओ का निर्णय निम्नानुसार है:-

7.341 तीन अलग-अलग डिक्शनरी परिभाषाओं पर विचार करने पर हम नोट करते हैं कि 'प्रमुख' शब्द को 'महत्वपूर्ण, गंभीर या अत्यधिक' के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तदनुसार, कोई व्याख्या जो घरेलू उद्योग को कुल घरेलू उत्पादन के महत्वपूर्ण, गंभीर या अत्यधिक हिस्से के घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित करती है, वह अनुमति योग्य है। वास्तव में, यह नीति अनुच्छेद 4.1 के स्पेनिश संस्करण से पूर्णतः संगत है जो घरेलू उत्पादन के 'उना प्रोपोरसियन इम्पोरटंटे' का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादकों का उल्लेख करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 4.1 कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख हिस्से के उत्पादकों के रूप में 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित नहीं करता है। इसके बजाए अनुच्छेद 4.1 कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख

हिस्से के उत्पादकों का उल्लेख करता है। यदि अनुच्छेद 4.1 में प्रमुख हिस्सा संदर्भित था तो 'घरेलू उद्योग' को कुल घरेलू उत्पादन के 50+ प्रतिशत हिस्से के उत्पादकों के रूप में परिभाषित करने की स्पष्ट अपेक्षा होगी। तथापि, प्रमुख हिस्से का संदर्भ यह संकेत करता है कि 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ एक से अधिक 'प्रमुख हिस्से' हो सकते हैं। अनेक 'प्रमुख हिस्सों' की स्थिति में यह समझना मुश्किल है कि प्रत्येक अलग 'प्रमुख हिस्सा' 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है – या होना चाहिए। अतः यह हमारे इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि कुल घरेलू उत्पादन के महत्वपूर्ण, गंभीर या काफी अधिक हिस्से के घरेलू उत्पादकों के अनुसार 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करने की अनुमति है। इन कारणों से हम पाते हैं कि एडी करार के अनुच्छेद 4.1 में सदस्यों के लिए कुल घरेलू उत्पादन के अधिकांश या 50+ प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले घरेलू उत्पादकों के रूप में 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करना अपेक्षित नहीं है।

7.342 रिकॉर्ड में ऐसा संकेत करने वाला कुछ भी नहीं है कि इस मामले की परिस्थितियों में कुल घरेलू उत्पादन का 46 प्रतिशत कुल घरेलू उत्पादन का एक महत्वपूर्ण गंभीर या काफी अधिक हिस्सा नहीं है। तदनुसार, हम ब्राजील के इस दावे को अस्वीकार करते हैं कि अर्जेन्टीना ने कुल घरेलू उत्पादन के 46 प्रतिशत हिस्से वाले घरेलू उत्पादकों के रूप में 'घरेलू उद्योग' को परिभाषित करके एडी करार के अनुच्छेद 4.1 का उल्लंघन किया है।

31. यूरोपीय समुदाय – चीन से कतिपय आयरन या स्टील फास्टर पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय के मामले में डब्ल्यूटीओ का निर्णय निम्नानुसार है:

415. हम मानते हैं कि घरेलू उत्पादकों संबंधी जानकारी लेना विशेष रूप से विशिष्ट बाजार स्थितियों जैसे अनेक उत्पादकों वाले असंगठित उद्योग के मामले में कठिन है। ऐसे विशिष्ट मामलों में अनुच्छेद 4.1 के अर्थ के भीतर 'प्रमुख हिस्से' के प्रयोग से जांचकर्ता प्राधिकारी को तर्कसंगत और व्यावहारिक रूप से संभव स्थिति के आलोक में घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के लिए कुछ लोचशीलता मिल जाती है। घरेलू उत्पादकों के संबंध में सूचना प्राप्त करने की प्राधिकारी की क्षमता पर व्यावहारिक बाधा का अर्थ यह हो सकता है कि ऐसे विशिष्ट मामले में 'कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा' क्या हो सकता है, वह हिस्सा कम असंगठित बाजार में सामान्यतः अनुमति प्राप्त हिस्से से कमतर हो सकता है।

417. अन्ततः, हम यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तुत व्याख्या की जांच करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.4 में उस करार के अनुच्छेद 4.1 में 'प्रमुख हिस्से' शब्दों की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण संदर्भित मार्गदर्शन किया गया है। अनुच्छेद 5.4 जो किसी जांच की शुरुआत के लिए स्थिति संबंधी अपेक्षा से संबंधित है, यह मूल्यांकन करने के लिए कतिपय संख्यात्मक बेंचमार्क प्रदान करता है कि क्या पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए कोई शिकायत घरेलू उत्पादकों द्वारा पर्याप्त समर्थन पर आधारित है। विशिष्ट रूप से अनुच्छेद 5.4 में कहा गया है कि कोई जांच तब तक "शुरु नहीं की जाएगी" जब तक आवेदन "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से न किया गया हो" तत्पश्चात इसमें व्यवस्था है कि "आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया तभी माना जाएगा यदि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो, जिनका संचयी उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से, जो आवेदन का समर्थन या विरोध कर रहा हो, द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता हो।" "इसके अलावा कोई जांच शुरु नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 25 प्रतिशत से कम हिस्सा बनता हो।"

32. भारत – लोहा और इस्पात उत्पादों के आयातों पर कतिपय उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ का निर्णय निम्नानुसार है:-

7.167. हम अपीलिय निकाय के इन सावधान करने वाले शब्दों को नोट करते हैं कि जब घरेलू उद्योग को ऐसे घरेलू उत्पादकों जिनका उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, यदि हिस्सा पर्याप्त अधिक न हो तो गुणात्मक तत्व यह सिद्ध करने में निर्णायक होता है कि क्या घरेलू उद्योग समुचित रूप से परिभाषित किया गया है के रूप में परिभाषित हो। यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण के लिए अनेक उत्पादकों वाले असंगठित उद्योग के मामले में जब सूचना प्राप्त करने की महानिदेशक की

क्षमता व्यावहारिक रूप से सीमित हो और इसलिए “प्रमुख हिस्सा” उस स्तर से कमतर हो जो कम असंगठित उद्योग में सामान्यतः अनुमति प्राप्त होता है। वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है, जैसा ऊपर नोट किया गया है भारतीय सक्षम प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के ऐसे हिस्से को घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल किया है जो इतना पर्याप्त था कि वह कुल घरेलू उत्पादन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर सकता था। तदनुसार, घरेलू उद्योग की परिभाषा द्वारा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1(ग) में परिभाषा के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तत्वों को पूरा करने की काफी संभावना होगी। जापान यह दर्शाने में विफल रहा है कि ऐसे अधिक हिस्से के बावजूद भारतीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-परिभाषित घरेलू उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधि नहीं था।

33. महानिदेशक यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी नियमावली में 25 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा निर्धारित है, तथापि, द्विपक्षीय रक्षोपाय निमावली के मामले में ऐसी कोई अपेक्षा निर्धारित नहीं है। डब्ल्यूटीओ निर्णयों और नियमावली के आधार पर कुल भारतीय उत्पादन में 25 प्रतिशत हिस्से को असंगठित उद्योग के मामले में “प्रमुख हिस्सा” माना जा सकता है। तथापि, डब्ल्यूटीओ का निर्णय महानिदेशक पर यह सुनिश्चित करने की अतिरिक्त अपेक्षा डालता है कि भागीदार उत्पादकों द्वारा प्रदत्त आंकड़े विकृत स्थिति न दर्शाते हों। अतः, आवेदकों के निष्पादन की तुलना समर्थकों और अन्य उत्पादकों के निष्पादन के साथ की गई है।

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल से सितंबर 21	अक्तूबर से मार्च 22
1	क्षमता					
	आवेदक	6,216	6,216	6,216	3,108	3,108
	समर्थक	3514	3514	3514	1757	1757
2	उत्पादन					
	उत्पादक	2,572	2,183	2,376	1,397	1,107
	समर्थक	1,898	1,266	1,180	682	572
3	क्षमता उपयोग					
	आवेदक	41%	35%	38%	45%	35%
	समर्थक	54%	36%	34%	39%	33%
4	बिक्री					
	आवेदक	2,516	2,304	2,354	1,404	1,255
	समर्थक	1,917	1,281	1,154	692	569

34. यह दलील दी गई है कि अन्य उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार उनके निष्पादन में सुधार हुआ है। महानिदेशक नोट करते हैं कि उन्होंने अन्य उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट की जांच की है और यह देखा गया है कि वे बहु-उत्पाद कंपनियां हैं और वार्षिक रिपोर्ट समग्र रूप से कंपनी के निष्पादन को दर्शाती है और आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के लिए विशिष्ट नहीं हैं और इसलिए इस दलील पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
35. नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों या ऐसे घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित करता है, जिनका संचयी उत्पादन सकल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो। नियमावली में प्रमुख हिस्से के संबंध में कोई गणितीय आंकड़ा नहीं दिया गया है। अतः, महानिदेशक ने यह माना है कि भारतीय उत्पादन में कोई ऐसा हिस्सा जो महत्वपूर्ण हो, प्रमुख हिस्सा माना जाना चाहिए। भागीदार आवेदक कंपनियों का

उत्पादन भारतीय उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, समर्थक उत्पादकों का उत्पादन भारत में उत्पादन का 20 प्रतिशत है। आवेदक कंपनियों और समर्थकों का मिलाकर भारत के उत्पादन में 60 प्रतिशत हिस्सा है।

36. नियमावली, मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड में साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक मानते हैं कि आवेदन नियमावली के अन्तर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और यह कि आवेदक कंपनियां घरेलू उद्योग हैं।

च. विविध

च.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. आवेदक ने संपूर्ण समायोजन योजना के गोपनीय होने का दावा किया है।
- ख. अनिवार्य अपेक्षा होने के बावजूद समायोजन योजना दायर आवेदन में नहीं दी गई थी।
- ग. यद्यपि समायोजन योजना लागत में कटौती पर केन्द्रित थी, तथापि उत्पाद में कम मूल्यवर्धन के कारण लागत कटौती के लिए सीमित गुंजाइश है। समायोजन योजना अवास्तविक है।
- घ. आवेदन के अनुसार आयात आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के डेटा-बेस से मेल नहीं खाते हैं।
- ङ. आवेदकों ने भारत में उत्पादकों की पूर्ण सूची उपलब्ध नहीं कराई है।
- च. सीईपीए की मूल अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि आवेदक शुल्क में कटौती और आयातों में वृद्धि के बीच संबंध दर्शाने में विफल रहे हैं।
- छ. जांच शुरुआत अधिसूचना में आयातों में वृद्धि करने वाली शुल्क कटौती के बारे में प्रथमदृष्टया विचार का उल्लेख भी नहीं है और ऐसी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।
- ज. 2017 में शुल्क हटाया गया था और आवेदकों ने इतनी देरी से आवेदन दायर किया है।
- झ. जांच अवधि के रूप में ऐसे विशेष छह महीनों की अवधि को चुनने का कोई कानूनी या वास्तविक औचित्य नहीं है।
- ञ. क्षति मामूली प्रकृति और अवास्तविक समायोजन योजना के कारण रक्षोपायों की 2 वर्ष के लिए आवश्यकता नहीं है।
- ट. आवेदकों ने मोलीब्डेनम की मात्रा पर कोई विचार किए बिना केवल आयात मात्राओं और कीमतों को प्रस्तुत किया है।
- ठ. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना में अब आयातित किए जा रहे कम मोलीब्डेनम मात्रा वाले उत्पादों की बिक्री की भारी मात्रा के आयात मिश्रण के परिवर्तन के कारण बढ़े हुए आयातों की संभावना पर विचार करते हुए सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
- ड. द्विपक्षीय रक्षोपाय असाधारण प्रकृति के हैं और उद्योग के कवच के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं।
- ढ. आवेदकों की यह दलील कि भारत में निर्यात कीमत से शेष विश्व के लिए निर्यात कीमत की तुलना में कम है, गलत है क्योंकि भारत को निर्यात लगभग 59-61 प्रतिशत मोली मात्रा के हैं जबकि अन्य देशों को 65-67 प्रतिशत मोली मात्रा के निर्यात होते हैं।
- ण. यदि आवेदक भारत और अन्य देशों के बीच कोरियाई निर्यातों की कीमत से व्यथित हैं तो द्विपक्षीय रक्षोपाय कीमत निर्धारण से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु उचित उपचार नहीं है।
- त. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि मोली मात्रा के लिए आवश्यक समायोजन के बाद आयात कीमत और मात्रा पर विचार किया जाए। आवेदकों ने आवेदन में ऐसा कोई समायोजन नहीं किया है और इस मुद्दे को देरी से उठाया है।

- थ. आवेदकों द्वारा हान्वा सॉल्युशंस कारपोरेशन का उल्लेख संबद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में किया गया है जबकि वह उत्पादक नहीं है।
- द. आवेदकों की प्रस्तावित समायोजन योजना अव्यावहारिक है और उसमें 2 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु आवश्यक अल्पावधिक योजना नहीं है।
- ध. अंतिम उत्पाद का फार्मूला आधारित कीमत निर्धारण और कच्ची सामग्री की फार्मूला आधारित खरीद दीर्घावधि के दौरान संभव हो सकती है।
- न. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वे कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नई मशीनरी और क्रेशर की स्थापना करेंगे परंतु पिछले 10 वर्षों में जब कोरिया गणराज्य से आयात धीरे-धीरे बढ़ रहे थे तब वे इन कदमों को नहीं उठा सके थे।
- प. आवेदकों ने कोरिया गणराज्य से निर्यातों के संबंध में अपने अनुरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- फ. चार वर्षों के लिए रक्षोपाय हेतु अनुरोध अभूतपूर्व है क्योंकि उन्हें केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए लगाया जा सकता है।

च.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

38. आवेदकों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग की समायोजन योजना एक अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज है क्योंकि उसमें उस व्यवसाय रणनीति की रूपरेखा है जिसे संबद्ध आयातों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु उद्योग द्वारा अपनाया जाएगा।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु जरूरी मूल कच्ची सामग्री मोली ऑक्साइड है (जिसे रोस्टेड मोलीब्डेनम अयस्क और सान्द्रण के रूप में भी जाना जाता है) जो अपेक्षाकृत एक दुर्लभ संसाधन है। भारत और कोरिया गणराज्य के पास मोलीब्डेनम का कोई संसाधन नहीं है और वे रोस्टेड मोलीब्डेनम अयस्क और सान्द्रण के आयातों पर पूर्णतः निर्भर हैं।
- ग. कच्ची सामग्री के आयात पर 2.5 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क लगता है। वर्तमान कच्ची सामग्री की कीमत 2000 रु. प्रति किलोग्राम से अधिक है और 2.5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाने से यह 50,000 रु. प्रति टन से अधिक हो जाएगी।
- घ. रियायती सीमा शुल्क चिली और थाइलैंड से कच्ची सामग्री के आयातों के मामले में लागू होता है। भारतीय उद्योग चिली और थाइलैंड से अपनी जरूरत का लगभग 62 प्रतिशत आयात कर रहा है जबकि 38 प्रतिशत जरूरत को अब भी शेष विश्व से पूरा किया जा रहा है। तथापि, क्योंकि चिली और थाइलैंड विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और इस उत्पाद के आपूर्तिकर्ता नहीं हैं और इन उत्पादकों के पास सीमित मात्रा है, इसलिए भारतीय उद्योग चिली और थाइलैंड के संबंध में उन्हें उपलब्ध सीमा शुल्क रियायतों का लाभ लेने में समर्थ नहीं है।
- ड. कोरियाई सरकार ने कच्ची सामग्री के लिए शुल्क में पूरी रियायत प्रदान की है। यह कोरियाई उत्पादकों को उपलब्ध स्वाभाविक लाभ नहीं है बल्कि भारतीय उद्योग के समक्ष आ रहा एक कृत्रिम अनुचित लाभ है जिससे कोरियाई आयातों में भारी वृद्धि हुई है।
- च. विचाराधीन उत्पाद एक उच्च कीमत वाला उत्पाद है (जिसकी बिक्री 15 लाख रु. से 20 लाख रु. प्रति एमटी की रेंज में होती है)। विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री से मूल्यवर्धन समग्र रूप से पर्याप्त तर्कसंगत है, यद्यपि प्रतिशत रूप में कम है। कोरियाई और भारतीय उत्पादकों के बीच वर्तमान सीमा शुल्क के अंतर से कोरियाई उत्पादकों के पक्ष में एक अनुचित लाभ सृजित हुआ है और इससे आयातों में ऐसी वृद्धि हुई है जो भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचा रही है।

- छ. कोरिया में उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं जिनके पास भारतीय उद्योग की संयुक्त क्षमता से अधिक काफी विशाल क्षमता मौजूद है। एसईएच एमएंडएस के पास प्रति वर्ष 20,000 एमटी की क्षमता है जो भारतीय उद्योग की कुल क्षमता से अधिक है। इसके अलावा, मौजूदा अधिशेष क्षमता, जैसाकि कोरियाई सरकार ने बताया है, के बावजूद कोरियाई उत्पादकों ने क्षमताओं में और अधिक वृद्धि की है, यह स्पष्ट है कि क्षमताओं में यह वृद्धि भारतीय और वैश्विक बाजार अवसरों पर विचार करते हुए की गई है और इसकी कीमत भारतीय उद्योग को चुकानी पड़ेगी। भारतीय उद्योग, जो पहले से एमएसएमई है, समाप्त हो जाएगा।
- ज. आयात विवरण में फेमो और मोली मात्रा का सकल और निवल भार दर्शाया गया है। यद्यपि कतिपय सौदों को सकल भार के साथ सूचित किया गया है, तथापि अन्य सौदों को फेमो के निवल भार के साथ सूचित किया गया है। इस प्रकार, आयातकों ने आयात मात्राओं की सूचना का असंगत तरीका अपनाया है। तथापि, डीजीसीआईएंडएस ने आयातकों द्वारा यथा-सूचित मात्रा को समेकित किया है। ऐसे मामले में संपूर्ण आयात मात्रा को एक संगत स्तर पर लाना अनिवार्य था। अतः, जहां भी सकल भार की सूचना दी गई है, आवेदकों ने उस पर विचार किया है। तथापि जहां निवल भार बताया गया है, वहां आवेदकों ने आयात विवरण में उल्लिखित मोली मात्रा का प्रयोग करते हुए, उसे सकल भार में परिवर्तित किया है।
- झ. हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि जांच शुरुआत अधिसूचना में बड़े हुए आयातों और क्षति के संबंध में महानिदेश का प्रथमदृष्टया विचार नहीं दिया गया है, गलत है क्योंकि पैरा 5,6 और 7 में प्रथमदृष्टया विचार का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

च.3 महा निदेशक द्वारा जांच

39. वर्तमान जांच आवेदकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों और सूचना के आधार पर, इस प्रथमदृष्टया संतुष्टि की घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बड़े हुए आयातों के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, पर पहुंचने के बाद महानिदेशक द्वारा शुरु की गई थी। इसके अलावा, जांच शुरुआत के बाद सभी पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी।
40. नियमावली का नियम 6 सूचना की गोपनीयता से संबंधित है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी, संतुष्ट होने पर महानिदेशक ने, जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। महानिदेशक ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था।
41. यह दलील दी गई है कि शुल्क 2017 में समाप्त हो गया था और आवेदन काफी देरी से दायर किया गया है। सीईपीए के अनुच्छेद 2.21 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“ संक्रमण अवधि का अर्थ इस करार के लागू होने की तारीख से किसी वस्तु के लिए टैरिफ समाप्ति पूरी होने की तारीख से दस वर्ष तक की अवधि या टैरिफ कटौती पूरी होने की अवधि, प्रत्येक वस्तु के लिए, जैसा भी मामला हो, है....”

42. इसके अलावा, सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“केवल संक्रमण अवधि के दौरान यदि इस करार के अन्तर्गत किसी सीमा शुल्क में कटौती या समाप्ति के परिणामस्वरूप दूसरे पक्षकार के उद्गम वाली वस्तु को समग्र रूप से या घरेलू उत्पादन के संबंध में और ऐसी दशाओं में ऐसी बड़ी हुई मात्रा में किसी पक्षकार के क्षेत्र में आयातित किया जा रहा हो, जहां केवल दूसरे पक्षकार से ऐसी वस्तु के आयात समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति या उसके खतरे का पर्याप्त कारण बनते हों, वहां पक्षकार निम्नलिखित कर सकता है:

3.....ऐसी कटौती या समाप्ति के आरंभ या अंत के बीच की समयावधि बीतने पर और आयात में वृद्धि से इस फुटनोट में उल्लिखित निर्धारण करने में उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। यदि आयातों में वृद्धि ऐसी कटौती या समाप्ति से स्पष्ट रूप से असंबंधित है तो इस फुटनोट में उल्लिखित निर्धारण किया जाएगा।”

43. अतः यह देखा गया है कि आयातों में वर्तमान वृद्धि और तत्संबंधी प्रदत्त रियायत के बीच केवल समय का अंतर किसी आवेदक को नियमावली और सीईपीए के अन्तर्गत उपचार की मांग करने से नहीं रोकता है। संक्रमण अवधि प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि उसमें यह माना जाए कि कार्यवाही केवल रियायत प्रदान करने के तुरंत बाद आयातों में वृद्धि पर की जा सकती है। इसके अलावा, सीईपीए में स्पष्ट रूप से माना गया है कि समय बीतने से आवेदक द्वारा आयातों में वृद्धि के विरुद्ध उपचार की मांग करने पर रोक नहीं लगेगी। यह भी देखा गया है कि इस उत्पाद के आयात वास्तव में रियायत शुरू होने के तुरंत बाद बढ़ना शुरू हो गए थे और सीमा शुल्क पूर्णतः समाप्त हो गया था। इसके अलावा, यद्यपि आयातों में पहली वृद्धि 2017-18 की अवधि के दौरान हुई थी, तथापि 2020-21 और उसके बाद बिल्कुल हाल की अवधि में आयातों में और अधिक वृद्धि हुई। आयातों में बिल्कुल हाल की अवधि के बाद काफी अधिक वृद्धि हुई थी। अतः, यह माना गया है कि आवेदन को सीईपीए और भारतीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दायर किया गया है।
44. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आयातों और क्षति की जांच के लिए जांच अवधि छह महीने की विशेष अवधि के रूप में चयनित करने का कोई औचित्य नहीं है। महानिदेशक नोट करते हैं कि अक्तूबर-21 से मार्च 22 की केवल छह महीने की अवधि पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विचार नहीं किया गया है। आयात की मात्रा पर रियायत-पूर्व अवधि, रियायत के दौरान, रियायत पश्चात और बिल्कुल हाल की अवधि में विचार किया गया है ताकि आयातों के रूझान की जांच की जा सके। इसके अलावा, 2018-19 से चार वर्षों के लिए आर्थिक मापदंडों की जांच भी की गई है।
45. आवेदन में सूचित आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के बीच आयात आंकड़ों में अंतर से संबंधित अनुरोध के बारे में आवेदकों ने अपने लिखित अनुरोध में बताया था कि डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सूचित भार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि कतिपय आयात आकड़े फेमो के सकल भार को दर्शाते हैं जबकि अन्य सौदे निवल भार की सूचना देते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदकों द्वारा प्रदत्त पद्धति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा, चूंकि किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई पद्धति उपलब्ध नहीं कराई है, इसलिए महानिदेशक ने प्राप्त सौदावार आंकड़ों की जांच की है और उनके आधार पर वर्तमान निर्धारण तक पहुंचे हैं। वास्तव में, आयात आंकड़ों का विश्लेषण आयात मात्राओं की सूचना देने में विभिन्न आयातकों द्वारा अपनाई गई अलग-अलग नीति दर्शाता है।
46. सितंबर 2021 के महीने में कोरिया से आयातों के कुछ स्पष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि सकल स्तर पर मात्राओं की सूचना कैसे दी गई है। महानिदेशक ने वर्तमान जांच के लिए संशोधित मात्रा पर विचार किया है।

बीई सं.	विवरण	सूचित मात्रा एमटी में	सूचित मूल्य	सूचित मात्रा के अनुसार कीमत	विचार की गई मात्रा एमटी में	संशोधित मात्रा के अनुसार कीमत
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***

47. इस प्रकार यह देखा गया है कि आयातकों ने ही आयात मात्राओं की सूचना देने के लिए असंगत पद्धति का प्रयोग किया है। यद्यपि कुछ सौदों को मोलीबडेनम की मात्रा के सकल भार के रूप में सूचित किया गया है, तथापि अन्य को मोली मात्रा के निवल भार के रूप में सूचित किया गया है। घरेलू उद्योग ने एकरूपता

सुनिश्चित करने के लिए समतुल्य मोलीबडेनम भार में विभिन्न सौदों को परिवर्तित किया है। महानिदेशक ने आयात की मात्रा ज्ञात करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पद्धति को अपनाया है:

- क. जहां कहीं भी सकल भार सूचित किया गया है, वहां उसे यथा रूप में अपनाया गया है और आयातित सामग्री के भार के रूप में स्वीकार किया गया है।
- ख. जहां आयात मात्रा के रूप में निवल भार की सूचना दी गई है, महानिदेशक ने मोलीबडेनम प्रतिशत की मात्रा विभाजित करके उसे सकल भार में परिवर्तित किया है। इसे आयातित सामग्री के सकल भार के रूप में माना गया है।

48. इस तर्क के संबंध में कि भारत और शेष विश्व को निर्यात कीमत के बीच तुलना गलत है, महानिदेशक नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि भारत और शेष विश्व को निर्यात अलग-अलग मोली मात्रा वाले हैं। तथापि, चूंकि वर्तमान जांच एक रक्षोपाय जांच है, इसलिए भारत और शेष विश्व को निर्यात कीमतों के बीच तुलना अंतिम निर्धारण के लिए संगत नहीं है।

छ. कोरिया गणराज्य से बढ़े हुए आयात

छ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

49. बढ़े हुए आयातों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. सीईपीए की मूल अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है क्योंकि आवेदक शुल्क में कटौती और आयात में वृद्धि के बीच संबंध दर्शाने में विफल रहे हैं।
- ख. कोरियाई आयातों में कोई अचानक और हाल की वृद्धि नहीं हुई है। डब्ल्यूटीओ ने अर्जेन्टीना फुटवियर और यूएस-इस्पात रक्षोपाय मामले में यह निर्णय दिया था कि आयात में वृद्धि हाल की, अचानक, तीव्र और काफी अधिक होनी चाहिए।
- ग. आरंभ में और जांच अवधि के अंत में आयातों के स्तर की तुलना करना पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल हाल की अवधि को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
- घ. टैरिफ कटौती और आयातों में वृद्धि के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ङ. आयातों में हाल की वृद्धि 2010 से 2017 तक सीमा शुल्क में कटौती के कारण नहीं हुई है।
- च. केवल एक तिमाही के आयात आंकड़ों पर आयातों में वृद्धि के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि भारत – लोहा और इस्पात उत्पादों के आयातों पर कतिपय उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट ने माना था।
- छ. 2021-22 की तीसरी तिमाही में आयात में वृद्धि कोविड के कारण आस्थगित आयातों की वजह से हुई थी। 2020-21 की तुलना में 2021-22 में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- ज. 2021-22 की चौथी तिमाही समग्र रूप से तथा घरेलू उत्पादन की दृष्टि से आयातों में गिरावट दर्शाती है। एक तिमाही (2021-22 की तीसरी तिमाही) में आयात में वृद्धि अपर्याप्त है।
- झ. महानिदेशक को आयातों में वृद्धि और टैरिफ कटौती/समाप्ति के बीच संबंध की मौजूदगी की जांच करनी चाहिए। टैरिफों में कटौती और आयात मात्राओं के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- ञ. महानिदेशक को आयातों का मूल्यांकन करते समय आवेदकों द्वारा किए गए आयातों को बाहर रखना चाहिए। याचिका में यह नहीं बताया गया है कि क्या ऐसे कोई आयात किए गए थे।
- ट. आयात मात्राओं में अस्थिरता यह स्पष्ट करती है कि आयातों में वृद्धि न तो 'अचानक' और न ही 'हाल की' है। पिछली तिमाही में आयातों में गिरावट आई है और केवल एक तिमाही में वृद्धि अपर्याप्त है।

- ठ. अर्जेन्टीना – फुटवियर मामले में अपीलीय निकाय ने माना था कि आयातों में वृद्धि स्वतः यह नहीं दर्शाती है कि उत्पाद को ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या उसका खतरा है।
- ड. 2021-22 की तीसरी और चौथी तिमाही में आयातों में वृद्धि का आवेदक का दावा अद्यतन तिमाही-वार आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं है। वास्तव में चौथी तिमाही में आयातों में गिरावट आई है।
- ढ. 2021-22 की तीसरी तिमाही में आयात में वृद्धि कोविड के कारण आस्थगित आयातों की वजह से हुई थी। 2020-21 की तुलना में 2021-22 में आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- ण. 2010 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष शुल्क में कटौती के बावजूद 2010 से 2017 तक आयात मात्रा में वृद्धि नहीं हुई थी।
- त. आयातों में वृद्धि भारत में इस्पात की मांग में बढ़ोतरी के कारण हुई है और किसी टैरिफ रियायत के कारण नहीं।
- थ. भारत में इस्पात संयंत्र या तो गैर-प्रचालनरत हैं या 2021-22 की पहली तिमाही में आंशिक रूप से प्रचालन कर रहे हैं। फेमों के आयातों को इस तिमाही के दौरान आस्थगित रखा गया था और 2021-22 की तीसरी तिमाही में आयातों में वृद्धि हुई थी।
- द. 2016-17 में आयात टैरिफ 0 प्रतिशत हो गया था परंतु कोरिया गणराज्य से आयात मात्रा में कोई संगत वृद्धि नहीं हुई थी।
- ध. आयात मात्राएं निरंतर घरेलू बिक्रियों से कम रही हैं, जो दर्शाता है कि आयातों में वृद्धि अचानक, तीव्र और अत्यधिक नहीं है।
- न. आवेदकों द्वारा जांच के बाद की अवधि में बढ़े आयातों के उनके दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- प. भारत और शेष विश्व के लिए कोरिया गणराज्य से निर्यातों का हिस्सा वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ निरर्थक है।
- फ. 11 वर्षों की अवधि में आयातों में वृद्धि को सामान्य और धीमी वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में अलाय इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- ब. 'बढ़े हुए आयातों' का अर्थ 'आयातों में कोई वृद्धि' नहीं है बल्कि यह अर्जेन्टीना – फुटवियर (ईसी) मामले में अपीलीय निकाय की निम्नलिखित रिपोर्ट पर आधारित 'बिल्कुल हाल की अवधि' होनी चाहिए।
- भ. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड द्वारा अपनी संपूर्ण जरूरत को भारतीय उद्योग से खरीदे जाने के बावजूद वे उपायों का विरोध कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं के खरीद संबंधी निर्णय टैरिफ रियायतों से प्रभावित नहीं होते हैं।
- म. रियायतें क्षति का कारण नहीं हो सकती हैं क्योंकि 2010 से 2017 की अवधि के दौरान सीमा शुल्क में निरंतर कटौती के बावजूद आयातों की मात्रा समान रही है।
- य. आयातों की मात्रा में कोई गैर-रेखीय गतिविधि नहीं है जो दर्शाता है कि आयातों में वृद्धि कोरिया – भारत सीईपीए के अन्तर्गत टैरिफ रियायतों के कारण नहीं बल्कि अन्य गैर-कीमत कारकों की वजह से हुई है।
- कक. आयातों में इस्पात उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार के कारण वृद्धि हुई है।

छ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

50. बढ़े हुए आयातों के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. महानिदेशक यह पता लगाने के लिए कि क्या आयातों में वृद्धि हुई है और क्या आयातों में यह वृद्धि टैरिफ रियायतों की वजह से हुई है, टैरिफ रियायतों के पहले और उनके बाद आयातों में वृद्धि की जांच कर सकते हैं।
- ख. जब टैरिफ रियायतें सबसे पहले प्रदान की गईं तो आयातों की मात्रा नगण्य थी। जैसे जैसे रियायतों में वृद्धि हुई, संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई।
- ग. आयातों में पहली बार वृद्धि 2017-18 में हुई, जब सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया और उसके बाद बिल्कुल हाल की अवधि में वृद्धि हुई। आयातों में जांच की वर्तमान अवधि के बाद चालू वर्ष में पुनः वृद्धि हुई है।
- घ. भारत में उत्पाद की पर्याप्त से अधिक क्षमताओं के बावजूद उत्पाद को देश में उत्पाद की मांग की लगभग एक तिहाई मात्रा तक कोरिया गणराज्य से आयात किया जा रहा है।
- ङ. इसका हिस्सा रियायत-पूर्व अवधि में लगभग शून्य प्रतिशत से बढ़ा है। कोरियाई आयातों का बाजार हिस्सा शुल्क घटाकर शून्य प्रतिशत किए जाने के समय 16 प्रतिशत और अब उनके पास मांग में 36 प्रतिशत हिस्सा है। कोरियाई आयातों का बाजार हिस्सा पिछले चार वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।
- च. कोरिया गणराज्य से आयात रियायत दिए जाने के समय भारतीय उत्पादन का केवल 16 प्रतिशत थे, पर अब यह 60 प्रतिशत से अधिक है।
- छ. रियायत दिए जाने से पहले भारतीय बाजार में 98 प्रतिशत आयात आवश्यकता को कोरिया से इतर देशों द्वारा पूरा किया जाता था। अब कोरिया के पास भारतीय आयातों का 94 प्रतिशत हिस्सा है और इस प्रकार इसने व्यावहारिक रूप से सभी अन्य देशों को हटा दिया है।
- ज. कोरिया वैश्विक रूप से संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। कोरिया गणराज्य में किसी खास खपत के बिना वह संबद्ध वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक भी नहीं है। कोरिया के पास इस उत्पाद में कोई प्राकृतिक लाभ भी नहीं है।
- झ. कोरिया गणराज्य से वैश्विक निर्यातों में इस अवधि के दौरान केवल 13 गुना अर्थात् 2009-10 में 1797 से 2021-22 में 23,287 की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत भारत को कोरिया के निर्यातों में लगभग 180 गुना की वृद्धि हुई है।
- ञ. 'बढ़ी हुई' मात्राओं में आयात होने पर द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाने के लिए भारत –कोरिया सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 में प्रावधान है। नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षा आयातों में निरंतर और लगातार वृद्धि की नहीं है। यह 'बढ़ी हुई मात्रा' में आयात है।
- ट. संयुक्त राज्य – कोरिया से सर्कुलर वेल्डेड कार्बन क्वालिटी लाइन पाइप के आयातों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय मामले में डब्ल्यूटीओ ने माना था कि यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि बिल्कुल हाल के रुझान सबसे महत्वपूर्ण रुझान हों और 'हाल का' शब्द में यह अपेक्षित होना चाहिए कि आयातों में निर्धारण की तारीख से ही वृद्धि हो रही हो।
- ठ. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आयातों में वृद्धि सीमा शुल्क में कटौती के कारण नहीं हुई है, तथापि उन्होंने बड़े हुए आयातों के अन्य कारण दर्शाने वाली कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा, सीईपीए करार का अनुच्छेद 2.22 यह स्पष्ट करता है कि सीमा शुल्क में कटौती आयातों में वृद्धि का एक मात्र कारण नहीं हो सकती है।
- ड. तीन भागीदार कंपनियों में से केवल एक कंपनी ने मामूली मात्राओं में आयात किया है। यद्यपि ऐसे आयातों को बाहर रखने की कानून के अन्तर्गत ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तथापि, यदि इन आयातों को बाहर भी रखा जाए तो भी नियमावली के अर्थ के भीतर आंकड़े अब भी 'बड़े हुए आयात' दर्शाएंगे। बड़े हुए आयात किसी एक घरेलू उत्पादक द्वारा आयात के कारण नहीं हुए हैं।

छ. 3 महानिदेशक द्वारा जांच

51. सीईपीए ने आयातों में वृद्धि को द्विपक्षीय रक्षोपाय के आवेदन हेतु मूल पूर्वापेक्षा बताया गया है। इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में रक्षोपाय लागू करने के प्रयोजनार्थ 'ऐसी मात्राओं में वृद्धि' हुई है जिसमें नियमावली में समग्र रूप से या घरेलू उत्पादन की दृष्टि से आयातों में वृद्धि का विश्लेषण अपेक्षित है। सीईपीए के अनुच्छेद 2.22 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"केवल संक्रमण अवधि के दौरान यदि इस करार के अन्तर्गत किसी सीमा शुल्क में कटौती या समाप्ति के परिणामस्वरूप दूसरे पक्षकार के उद्गम वाली वस्तु को समग्र रूप से या घरेलू उत्पादन के संबंध में और ऐसी दशाओं में ऐसी बड़ी हुई मात्रा में किसी पक्षकार के क्षेत्र में आयातित किया जा रहा हो, जहां केवल दूसरे पक्षकार से ऐसी वस्तु के आयात समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति या उसके खतरे का पर्याप्त कारण बनते हों, वहां पक्षकार निम्नलिखित कर सकता है:

- (क) इस करार के अन्तर्गत प्रदत्त वस्तु पर सीमा शुल्क की किसी दर की आगे कटौती को रोकना; या
- (ख) उस वस्तु पर सीमा शुल्क की दर में उस स्तर पर वृद्धि जो निम्न में से कमतर से अधिक न हो;
- (i) उपाय किए जाने के समय उस वस्तु पर प्रभावी सीमा शुल्क की एमएफएन लागू दर; और
- (ii) इस करार के लागू होने की तारीख से तत्काल पहले दिन को उस वस्तु पर प्रभावी सीमा शुल्क की एमएफएन लागू दर।"

52. नियमावली के नियम 2(ग) में बड़े हुए आयातों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(ग) "बड़े हुए आयातों" में कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि शामिल है, भले ही पूर्ण संदर्भ में हों अथवा घरेलू उत्पादन के संबंध में।

53. आयातों की वृद्धि की प्रकृति के संबंध में अजेन्टीना – फुटवियर (ईसी) में अपीलीय निकाय ने पैनल के विपरीत यह माना था कि आयात में वृद्धि इतनी हाल की, अचानक, तीव्र और अधिक होनी चाहिए जिससे गंभीर क्षति हुई हो या होने का खतरा हो। इसका संगत उद्धरण निम्नानुसार है:

"हम अनुच्छेद 4.2(क) की इस अपेक्षा का स्मरण करते हैं कि 'आयातों में वृद्धि की दर और राशि' का मूल्यांकन किया जाए। हमारे विचार से इसका अर्थ यह अपेक्षा है कि जांच अवधि के दौरान आयातों के मध्यवर्ती रुझानों का विश्लेषण किया जाए। हम नोट करते हैं कि 'दर' शब्द गति और दिशा दोनों दर्शाता है और इस प्रकार मध्यवर्ती रुझान (ऊपर या नीचे) पर पूर्णतः विचार किया जाना चाहिए। जहां ये रुझान जांच अवधि में मिश्रित हों वहां निर्धारण में यह बात निर्णायक होगी कि क्या अनुच्छेद 2.1 के अर्थ में आयातों में वृद्धि हुई है। व्यावहारिक रूप से हम मानते हैं कि आयातों में ऐसी किसी मिश्रित प्रवृत्ति की मात्रा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका यह मूल्यांकन करना है कि क्या आयातों में कोई गिरावट केवल अस्थायी है या कोई दीर्घावधिक प्रवृत्ति दर्शाती है।

131. [] यह निर्धारण कि क्या "ऐसी बड़ी हुई मात्रा में" आयात की अपेक्षा पूरी हुई है, केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण से पूरी नहीं होगी दूसरे शब्दों में जांच के लिए केवल यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि इस वर्ष उत्पाद के आयात पिछले वर्ष – या पांच वर्ष पहले की तुलना में अधिक हैं। इसके अलावा, और बार-बार होने पर आयातों की मात्रा में केवल वृद्धि से बात नहीं बनेगी। "ऐसी बड़ी हुई मात्राएं" अवश्य होनी चाहिए जिनसे रक्षोपाय लागू करने के लिए इस अपेक्षा को पूरा करने हेतु घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या उसका खतरा हो। और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और गैट 1994 के अनुच्छेद XIX:1(क) दोनों की भाषा में हम मानते हैं कि यह अपेक्षित है कि आयातों में वृद्धि "गंभीर क्षति" होने या उसका खतरा होने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से पर्याप्त हाल की, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त अधिक अवश्य होनी चाहिए।"

54. यूएस – व्हीट ग्लूटन संबंधी पैनल ने “ऐसी बड़ी हुई मात्रा में” वाक्य की व्याख्या निम्नानुसार की है:

“8.31 गैट 1994 के अनुच्छेद XIX:1 (क) और [रक्षोपाय करार (‘एसए’) करार के] अनुच्छेद 2.1 में केवल आयातों में वृद्धि का उल्लेख नहीं है बल्कि उसमें संबंधित उत्पाद के आयातों में ‘वृद्धि की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकृति के संबंध में विशिष्ट अपेक्षाएं दी गई हैं। गैट 1994 के अनुच्छेद XIX:1 (क) और एसए का अनुच्छेद 2.1 में अपेक्षित है कि संबंधित सदस्य के क्षेत्र में किसी उत्पाद का आयात ऐसी बड़ी हुई मात्रा (समग्र या घरेलू उत्पाद के सापेक्ष) में किया जाए जिससे गंभीर क्षति हुई हो या होने का खतरा हो। इस प्रकार, आयातों में केवल वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी बल्कि हम अर्जेन्टीना – फुटवियर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के निष्कर्ष से सहमत हैं कि यह वृद्धि पर्याप्त रूप से हाल की, अचानक, तीव्र और मात्रात्मक तथा गुणात्मक, दोनों तरह से अत्यधिक होनी चाहिए जिससे गंभीर क्षति हुई हो या होने का खतरा हो”

55. यूएस – लाइन पाइप मामले में, पैनल ने अपीलीय निकाय द्वारा समीक्षा नहीं किया गया यह विवरण पाया कि “इस निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में आयात आगे बढ़ रहे हैं बल्कि हाल की अवधि में आयात में ‘वृद्धि’ हो सकती है, परंतु यह जांच अवधि के अंत तक बढ़ते रहना आवश्यक नहीं है या निर्धारण से तुरंत पहले होना आवश्यक नहीं है”:

“यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या बड़े हुए आयातों के निष्कर्ष को 1998 के पहले सत्र से 1999 के पहले सत्र तक समग्र आयातों में गिरावट के आलोक में बनाए रखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम ‘हाल की’, के अर्थ के संबंध में अपनी चर्चा का स्मरण करते हैं और हमारा निष्कर्ष कि ‘हाल की’ का अर्थ वर्तमान का कोई विश्लेषण नहीं है। हमारा यह भी मत है कि यह तथ्य कि आयात में वृद्धि ‘हाल की’ होनी चाहिए, का यह अर्थ नहीं है कि वह जांचकर्ता प्राधिकारी के निर्धारण के तुरंत पहले की अवधि तक जारी रहनी चाहिए या जांच अवधि के बिल्कुल अंत तक जारी रहनी चाहिए। हमें अनुच्छेद 2.1 में अपने विचार का समर्थन मिलता है जिसमें उल्लेख है कि ‘ऐसा उत्पाद.....ऐसी बड़ी हुई मात्राओं में आयातित किया जा रहा है’ इस करार में ‘वृद्धिशील’ के बदले ‘बड़ी हुई’ विशेषण का प्रयोग हुआ है। ‘बड़ी हुई’ शब्द के प्रयोग से हमें पता चलता है कि ऐसी निर्धारण की कोई जरूरत नहीं है कि आयात में इस समय भी वृद्धि हो रही है। बल्कि आयातों में हाल की अवधि में ‘वृद्धि’ हो सकती है परंतु यह जांच अवधि के अंत तक वृद्धि या निर्धारण के तुरंत पहले तक होना आवश्यक नहीं है। बशर्ते कि जांच किया गया उत्पाद जांच अवधि के अंत में ऐसी बड़ी हुई मात्राओं में ‘आयातित किया जा रहा हो’, तो अनुच्छेद 2.1 की अपेक्षाएं पूरी होती हैं।”

56. विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों का विश्लेषण ऊपर उल्लिखित नियमावली और डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र के आलोक में किया गया है।
57. महानिदेशक का विचार है कि नियमों में यह विहित नहीं है कि बिल्कुल हाल की अवधि तक आयातों में निरंतर लगातार वृद्धि होनी चाहिए। यूएस – लाइन पाइप में डब्ल्यूटीओ पैनल ने पाया था कि ऐसे निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है कि आयातों में निरंतर वृद्धि हो रही है। एकमात्र जरूरत यह है कि आयातों में हाल की अवधि में वृद्धि होनी चाहिए।
58. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि आयातों की मात्रा में टैरिफ रियायतों में वृद्धि के साथ-साथ वृद्धि नहीं हुई है। अतः, महानिदेशक ने टैरिफ रियायत से पहले, टैरिफ रियायत अवधि के दौरान और टैरिफ हटाने के बाद की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की जांच की है।
59. इस तर्क के संबंध में कि आवेदकों द्वारा किए गए आयातों को भारत में आयात मात्रा ज्ञात करते समय बाहर रखा जाना चाहिए, निम्नांकित तालिका आवेदकों द्वारा किए गए आयातों की मात्रा दर्शाती है:-

क्र.सं.	वर्ष	बून मेटल एंड अलॉय कार्पोरेशन	प्रीमियर अलॉय एंड केमिकल्स	टीम फेरो अलॉय	कोरिया से आयात एमटी में
1	***	***	***	***	2,361

2	***	***	***	***	2,967
3	***	***	***	***	2,919

60. यह देखा गया है कि आवेदकों द्वारा किया गया आयात कोरिया से सकल आयातों और उत्पाद की भारतीय मांग पर विचार करते हुए बहुत कम है। नियमावली में उत्पाद का आयात करने वाले घरेलू उत्पादक को बाहर रखने या ऐसे घरेलू उत्पादक द्वारा आयातों की मात्रा को बाहर रखने का प्रावधान नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उत्पादक को बाहर रखने या ऐसे घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए आयातों की मात्रा को बाहर रखने को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। महानिदेशक ने न तो घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा है और न ही घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए ऐसे आयातों की मात्रा को बाहर रखा है।
61. महानिदेशक ने संगत अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य और अन्य देशों से आयातों पर विचार किया है। हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के मद्देनजर कि महानिदेशक को यह जांच करनी चाहिए कि क्या आयातों में टैरिफ रियायतों के परिणामस्वरूप भारी वृद्धि हुई है, महानिदेशक ने रियायतों की शुरुआत से पहले और 2009-10 से आयातों की मात्रा की जांच की है। महानिदेशक यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध आयातों में वृद्धि के लिए किसी अन्य कारण को दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, चूंकि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि आयातों में वृद्धि केवल एक तिमाही में हुई थी, इसलिए महानिदेशक ने मार्च, 2022 के बाद और दिसंबर, 2022 तक की अवधि के लिए आयातों की मात्रा की जांच की है। इन वर्षों के दौरान आयातों की मात्रा संबंधी संगत जानकारी नीचे दी गई है:

क. समग्र रूप से आयात

62. इन वर्षों के दौरान, समग्र रूप से आयातों संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष	भारत में आयात एमटी में			सीमा शुल्क
		कोरिया गणराज्य	अन्य देश	कुल आयात	कोरिया
1	2008-09	93	838	931	5%
2	2009-10	30	1,296	1,326	5%
3	2010-11	473	605	1078	5%
4	2011-12	551	768	1319	5%
5	2012-13	474	314	788	5%
6	2013-14	732	183	915	4.69%
7	2014-15	657	678	1335	3.44%
8	2015-16	728	123	851	2.19%
9	2016-17	716	89	805	0.94%
10	2017-18	1,598	83	1681	0%
11	2018-19	1,957	402	2359	0%
12	2019-20	2,361	310	2671	0%
13	2020-21	2,967	190	3157	0%

14	अप्रैल 21 – सित. 21 (वार्षिकीकृत)	1,872	280	2152	0%
15	अक्तूबर 21 – मार्च 22 (वार्षिकीकृत)	3,966	404	4370	0%
16	अप्रैल 22 – दिस. 22 (वार्षिकीकृत)	4,279	1,330	5,609	0%

63. यह देखा गया है कि:

- क. रियायत शुरू होने से पहले 2009 में आयात मात्रा केवल 26 एमटी थी। तथापि, उस अवधि के दौरान जब सीमा शुल्क लागू थे, आयातों की मात्रा 400-500 एमटी के बीच रही थी।
- ख. 2017-18 में जब सीमा शुल्क शून्य किया गया तो आयात दोगुने हो गए।
- ग. आयातों में अक्तूबर, 2021 से मार्च, 2022 की बिल्कुल हाल की अवधि में 3500 एमटी से अधिक की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।
- घ. महानिदेशक ने इसके अलावा अप्रैल से दिसंबर, 2022 (बिल्कुल हाल की अवधि के बाद की अवधि) में आयातों का विश्लेषण किया है और यह देखा गया है कि आयातों में वृद्धि होना जारी है।

64. महानिदेशक नोट करते हैं कि रियायत-पूर्व, रियायत के दौरान, रियायत के बाद, बिल्कुल हाल की अवधि और बिल्कुल हाल की अवधि के बाद की अवधि को कवर करने वाली अपेक्षाकृत लंबी अवधि के दौरान आयातों पर विचार करने से आयातों में भारी वृद्धि का पता चलता है।

ख. सापेक्ष रूप से कोरिया गणराज्य से आयात

65. इन वर्षों के दौरान सापेक्ष रूप से आयातों संबंधी सूचना नीचे दी गई है। महानिदेशक ने भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में भारत में सकल आयातों से संबंधित संबद्ध आयातों की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	कोरिया से आयात एमटी में	निम्न के संबंध में आयात		
			भारतीय मांग	भारतीय उत्पादन	कुल आयात
1	2018-19	1,957	23%	32%	83%
2	2019-20	2,361	28%	41%	88%
3	2020-21	2,967	33%	50%	94%
4	अप्रैल 21 – सित. 21 (वार्षिकीकृत)	1,872	22%	29%	87%
5	अक्तूबर 21 – मार्च 22 (वार्षिकीकृत)	3,966	39%	71%	91%

66. यह देखा गया है कि:

- क. भारतीय मांग के संबंध में आयातों में 2018-19 में 23 प्रतिशत से बिल्कुल हाल की अवधि में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ख. भारतीय उत्पादन की दृष्टि से आयातों में बिल्कुल हाल की अवधि में 32 प्रतिशत से 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ग. कुल आयातों के संबंध में हाल की अवधि में आयातों में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- घ. सीमा शुल्क हटाने के बाद कोरियाई आयातों में बाजार में अन्य आयातों का स्थान ले लिया है।

- ड. आवेदकों ने तर्क दिया है कि अपेक्षाकृत लंबी अवधि पर विचार करने पर कोरिया गणराज्य से आयातों का बाजार हिस्सा कोई रियायत नहीं होने के समय केवल 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत था, परंतु बिल्कुल हाल की अवधि में बाजार हिस्सा बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है।
- च. इसके अलावा, आवेदकों ने दलील दी है कि भारतीय मांग और उत्पादन के संबंध में आयातों में रियायत-पूर्व, रियायत के दौरान, रियायत पश्चात अवधि पर विचार करते समय काफी अधिक वृद्धि हुई है। निम्नांकित तालिका आवेदक के तर्क को दर्शाती है।

क्र.सं.	वर्ष	निम्न की दृष्टि से संबद्ध आयात		
		कुल आयात	भारतीय मांग	भारतीय उत्पादन
1	2008-09	10%	3%	5%
2	2009-10	2%	1%	1%
3	2010-11	44%	11%	15%
4	2011-12	42%	11%	14%
5	2012-13	60%	9%	10%
6	2013-14	80%	14%	17%
7	2014-15	49%	9%	11%
8	2015-16	86%	11%	13%
9	2016-17	89%	10%	11%
10	2017-18	95%	20%	24%
11	2018-19	83%	23%	32%
12	2019-20	88%	28%	41%
13	2020-21	94%	34%	50%
14	अप्रैल 21 – सित. 21 (वार्षिकीकृत)	87%	22%	29%
15	अक्तूबर 21 – मार्च 22 (वार्षिकीकृत)	91%	39%	71%

67. इस तर्क के संबंध में कि बिल्कुल हाल की अवधि में आयातों में वृद्धि कोविड के कारण पहले आस्थगित आदेशों के तहत सामग्री के पहुंचने के कारण हुई है, महानिदेशक नोट करते हैं कि आयातों में न केवल वर्तमान हाल की अवधि में वृद्धि हुई है बल्कि रियायत के शुरु में और वर्तमान वृद्धि अवधि के बाद भी वृद्धि हुई है। वास्तव में, बिल्कुल हाल की अवधि के बाद आयातों की मात्रा बिल्कुल हाल की अवधि में आयातों की मात्रा से वास्तविक रूप से काफी अधिक है। रियायत-पूर्व, रियायत के दौरान और रियायत पश्चात अवधि में आयातों पर विचार करने से आयातों में निरंतर वृद्धि का पता चलता है। उपर्युक्त के मद्देनजर, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
68. यह तर्क दिया गया है कि आयातों में 2021-22 की चौथी तिमाही में गिरावट आई है। तथापि, यह देखा गया है कि 2021-22 की चौथी तिमाही के बाद आयातों में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों में कुछ तिमाहियों में गिरावट आई है और कुछ में वृद्धि हुई है। महानिदेशक नोट करते हैं कि नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षा “बढ़ते हुए आयातों” के बजाए “बढ़े हुए आयातों” की है।

69. यह तर्क दिया गया है कि आयातों में वृद्धि इस्पात उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार की वजह से हुई है। महानिदेशक नोट करते हैं कि आयातों की जांच रियायत-पूर्व, रियायत के दौरान और रियायत पश्चात की अवधियों के लिए की गई है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है। तथापि, मांग में संपूर्ण वृद्धि को कोरियाई आयातों ने पूरा कर दिया है। यद्यपि, घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। इसके अलावा, यह दर्शाने हेतु कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रयोक्ताओं को भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या रही हो। समग्र मात्रा और मांग में बाजार हिस्से में वृद्धि की दृष्टि से लंबी अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि यह सिद्ध करती है कि आयातों में वृद्धि का हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध कारकों से कोई संबंध नहीं है।
70. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि महानिदेशक को मध्यवर्ती रुझानों की भी जांच करनी चाहिए और अपनी जांच को अवधि की शुरुआत और अंत के बीच केवल तुलना तक सीमित नहीं करना चाहिए। महानिदेशक ने 10 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा की जांच की है, जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई चिंताओं का समाधान करती है।
71. इस दलील के संबंध में कि आयातों में वृद्धि बढ़ती हुई मांग के कारण हुई है, महानिदेशक नोट करते हैं कि उन्होंने समग्र तथा सापेक्ष रूप से आयातों की जांच के लिए काफी लंबी अवधि के दौरान आयातों के रुझान की जांच की है और यह देखा है कि आयातों के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि जब आवेदकों के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आयातों में वृद्धि केवल देश में मांग में वृद्धि के कारण हुई है।
72. यह अनुरोध किया गया है कि कुछ तिमाहियों में आयातों में गिरावट आई है और कुछ में वृद्धि हुई है। महानिदेशक नोट करते हैं कि नियमावली में यह अपेक्षित नहीं है कि आयातों में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। एक लंबी अवधि पर विचार करने से यह सुनिश्चित हुआ है कि कुछ तिमाहियों में वृद्धि और कुछ तिमाहियों में गिरावट के मध्यवर्ती रुझानों का समाधान किया जा सके।
73. महानिदेशक रियायत-पूर्व, रियायत के दौरान, रियायत पश्चात और बिल्कुल हाल की अवधि में आयातों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरिया गणराज्य से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों में अप्रैल, 2018 से मार्च, 2022 की अवधि में भारतीय उत्पादन और खपत तथा कुल आयात के संबंध में भी वृद्धि हुई है। टैरिफ की पूर्ण समाप्ति के साथ कोरियाई आयातों ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों में अधिकांश हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस अवधि में बढ़ती हुई टैरिफ रियायतों के साथ आयातों में वृद्धि सीमा शुल्क समाप्ति और बढ़े आयातों के बीच सह-संबंध की मौजूदगी को दर्शाती है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संबद्ध आयातों में वृद्धि के लिए कोई अन्य कारण दर्शाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। आयातों में वृद्धि सीईपीए और नियमावली के अनुसार बढ़े हुए आयात दर्शाती है। अतः महानिदेशक का यह निष्कर्ष है कि कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि हुई है।

ज. भारतीय उद्योग की क्षति

ज.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

74. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

- क. इन वर्षों के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा और मूल्य तथा बाजार हिस्से में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।
- ख. घरेलू उत्पादक अपनी ईष्टतम क्षमता का प्रचालन नहीं कर सकते हैं और अतिरिक्त क्षमता के कारण उच्च स्तर लागत की वजह से लाभप्रदता में सुधार नहीं कर सकते हैं।
- ग. कीमत कटौती जांच अवधि में या ऋणात्मक है या मामूली है।
- घ. कच्ची सामग्री की कीमतों तथा कोरियाई आयातों की कीमत में वृद्धि को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

- ड. कोरियाई आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई कीमत ह्रास नहीं हुआ है।
- च. 2021-22 के अंतिम 6 महीनों में घाटे निष्प्रभावी हैं।
- छ. भारतीय उद्योग की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है।
- ज. 2021-22 की दूसरी तिमाही में तिमाही एक की तुलना में कच्ची सामग्री की कीमत और कोरियाई आयातों की कीमत के बीच अंतर कम होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और लाभ में वृद्धि हुई है।
- झ. बोली प्रक्रिया के जरिए उत्पाद की बिक्री होती है और कटौती के संबंध में प्रतिस्पर्धियों के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
- ञ. महानिदेशक को उद्योग को हुई क्षति का कारण जानने के लिए भारतीय उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा का आकलन करना चाहिए।
- ट. टैरिफ रियायतों के कारण कीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ है और कीमतों में उतार-चढ़ाव अन्य कारकों की वजह से हुआ है।
- ठ. कम कीमत के चीन के आयातों के कारण भारतीय उद्योग को क्षति हो गई है।
- ड. अन्य कारकों जैसे 2021-22 में कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि, कच्ची सामग्री के आयात पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि, भारतीय रुपया का मूल्यह्रास जिससे कच्ची सामग्री महंगी हो गई, के कारण क्षति हुई है।
- ढ. महानिदेशक को घरेलू उद्योग पर मौलिक डेनम की कमी के प्रभाव की भी जांच करनी चाहिए।
- ण. घरेलू उत्पादक ईष्टतम क्षमता पर कार्य नहीं कर सकते हैं और उनके पास भारी अतिरिक्त क्षमता के कारण उच्च स्तर लागतों की वजह से अपनी लाभप्रदता में सुधार नहीं कर सकते हैं।
- त. पहुंच कीमत में गिरावट 2020-21 तक घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट के अनुरूप थी। 2021-22 में पहुंच कीमत में वृद्धि की दर बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में उच्चतर रही थी।
- थ. कच्ची सामग्री में कीमतों में वृद्धि के अनुसार आयात कीमतों में वृद्धि हुई है।
- द. घरेलू उद्योग के पीवीआईटी में 2019-20 से 2020-21 तक 19 गुना वृद्धि हुई है। आवेदक घाटे से उभकर अधिक नकद लाभ की स्थिति में आ गए हैं।
- ध. विदेशी उत्पादकों ने पैमाने की अच्छी क्फायते प्राप्त कर ली हैं और उनके कुशल विनिर्माण और नियंत्रित प्रक्रियाएं लागत दक्ष हैं जिससे वे भारतीय उत्पादकों के मुकाबले बेहतर हो जाते हैं।
- न. कोरियाई उत्पादक मोली के बल्क आर्डर बुक करते हैं जिससे उन्हें भारतीय उत्पादकों के मुकाबले लाभ मिलता है।
- प. भारतीय फेमो उत्पादक कम मात्रा में फेमो का उत्पादन कर रहे हैं और उन्होंने निरंतर आपूर्ति के साथ गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन की प्रक्रिया स्थापित नहीं की है।
- फ. आवेदकों के अनुरोधों से स्पष्ट रूप से विपरीत शुल्क संरचना की मौजूदगी, कच्ची सामग्री की कमी, कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता, उत्पादन की मात्रा में कमी आदि के क्षति का कारण होने के बारे में पता चलता है।
- ब. घरेलू उद्योग अत्यधिक क्षमताओं के कारण क्षमता का ईष्टतम उपयोग करने में असमर्थ रहा है और अतिरिक्त लागतों के बोझ से दबा हुआ है।
- भ. आवेदकों ने माना है कि कच्ची सामग्री एक दुर्लभ संसाधन है और आयात पर 2.5 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क लगता है और यह आयात शुल्क का बोझ काफी अधिक है।

- म. कोरियाई निर्यातकों ने उत्पादन के लिए उच्चतर समेकन और अधिक लागत कुशल प्रक्रियाएं बना ली हैं, क्योंकि वे अनरोस्टेड मोली डेनम को प्राथमिक कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं जबकि भारतीय उच्च उद्योग रोस्टेड मोली डेनम का प्रयोग करता है।
- य. जांच अवधि के दौरान वैश्विक रूप से मोली डेनम की आपूर्ति में कमी के कारण कच्ची सामग्री की कीमत में काफी अस्थिरता रही है।
- कक. आवेदकों की कीमत पर कोई ह्रासकारी प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि घरेलू बिक्री कीमत में 2020-21 तक बिक्री लागत में गिरावट के अनुरूप गिरावट आई है और 2021-22 में जब बिक्री लागत में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग उसके अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम रहा था।
- खख. आधे वर्ष के आंकड़ों के आधार पर क्षति विश्लेषण करना भ्रामक होगा। यदि 2021-2022 के दोनों अर्धवर्ष के आंकड़े जोड़े जाते हैं तो पता चलेगा कि आवेदकों को कोई क्षति नहीं हुई है।
- गग. वर्ष 2021-22 में आवेदकों के उत्पादन और बिक्री में स्पष्ट सुधार हुआ है।
- घघ. आवेदन में प्रस्तुत लाभप्रदता सूचना और लिखित अनुरोध में दी गई सूचना में अंतर है।
- डड. आवेदकों ने तीसरी तिमाही जब आयात अधिक थे, में बेहतर निष्पादन किया है, परंतु आयातों के कम होने पर चौथी तिमाही के दौरान निष्पादन खराब हुआ है।
- चच. कोरियाई उत्पादक कच्ची सामग्री में कीमत के बदलाव के अनुसार अपनी कीमतों को समायोजित करने में सक्षम थे जबकि भारतीय उद्योग अनेक कारकों से ग्रस्त है जिसकी वजह से वह कच्ची सामग्री की कीमतों से तालमेल बैठाने में असमर्थ रहा है।
- छछ. आवेदकों ने यह नहीं बताया है कि मालभाड़ा लागत में वृद्धि से उनके निष्पादन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है।
- जज. आवेदकों को क्षति का मुख्य कारण कच्ची सामग्री के आयात पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क है।
- झझ. आयातित उत्पाद की कीमत से क्षति द्विपक्षीय रक्षोपायों के मूल्यांकन में संगत विषय नहीं है। कोरिया गणराज्य के मूल के उत्पाद की कीमत द्विपक्षीय रक्षोपाय की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक है।
- ञञ. बिक्री लागत में वृद्धि के अनुसार कीमत वृद्धि करने की आवेदकों की क्षमता से पता चलता है कि कोरिया गणराज्य से आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है।
- टट. कोरिया गणराज्य के उत्पादकों के पास काफी अधिक क्षमता है और उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ मिल सकता है और वे अपनी स्थिर लागतें नियंत्रित कर सकते हैं। कोरिया गणराज्य से उत्पादकों/निर्यातकों को उपलब्ध बड़े पैमाने के लाभ को द्विपक्षीय रक्षोपायों को लगाकर समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- ठठ. बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। जब आयातों में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ और जब आयातों में गिरावट आई तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में भी गिरावट आई।
- डड. घरेलू उद्योग की क्षमता 15,000 एमटी से बढ़कर 19,800 एमटी हो गई है और बाजार हिस्सा इस अवधि के दौरान 68 प्रतिशत या उससे अधिक रहा है। इससे पता चलता है कि उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- ढढ. आवेदकों ने आधे में विभाजित "वार्षिकीकृत" आंकड़ों का उल्लेख करके गुमराह किया है।
- णण. आवेदकों ने अधिकांश उल्लिखित आंकड़ों का स्रोत नहीं बताया है।

- तत. आवेदक 10 प्रतिशत मूल्यवर्धन करते हैं और यह कि उनकी उत्पादन लागत के 90 प्रतिशत में कच्ची सामग्री की लागत शामिल है जिसके लिए वे पूर्णतः आयातों पर कच्ची सामग्री की खरीद के लिए निर्भर हैं। अतः वे आयात प्रतिस्पर्धा से तालमेल नहीं रख सकते क्योंकि कच्ची सामग्री की लागत को ईष्टतम बनाना उनके नियंत्रण में नहीं है।
- थथ. आवेदक 2020-21 में जब कोरिया से पीयूसी की आयात मात्रा उच्चतम रही था तो लाभ में थे।
- दद. पूरे भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा अब भी 2021-22 में काफी अधिक 68 प्रतिशत है।
- धध. जरूरत यह दर्शाने की है कि कोरिया से संबद्ध वस्तु के आयात द्विपक्षीय रक्षोपायों की प्रकृति पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति का एक मात्र कारण है जो वैश्विक रक्षोपाय में निर्धारित गैर-भेदभाव के मुख्य सिद्धांत का अपवाद है।
- नन. डब्ल्यूटीओ ने गेहूं के ग्लूटेन के मामले में भी यह निर्णय दिया है कि “केवल” आयातों में वृद्धि के गंभीर क्षति के कारण की अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्राधिकारी को इस विश्लेषण में अन्य कारकों के प्रभावों को बाहर रखना होगा।
- पप. आवेदकों ने केवल 5 प्रतिशत सीमा शुल्क का अनुरोध किया है। आवेदकों की कीमतों पर आधारित सूत्र की पूरी स्कीम निष्प्रभावी हो जाएगी यदि कच्ची सामग्री की कीमत 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाए।
- फफ. आवेदकों ने यह बताते हुए करार के अनुच्छेद 2.22 के वास्तविक अर्थ या आशय की गलत व्याख्या की है कि “ बड़े हुए आयात से हुई क्षति किसी अन्य कारण से हुई क्षति के बराबर या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए”।
- बब. भारत और शेष विश्व को कोरिया गणराज्य से निर्यात कीमत अनेक कारकों जैसे पैमाने की किफायत, मोली डेनम मात्रा में अंतर, आपूर्ति समय में अंतर, स्थानीय मुद्रा का मूल्य आदि के कारण हुई है। भारत और शेष विश्व को कोरिया गणराज्य से निर्यात कीमत की विश्लेषण से वस्तुनिष्ठ रूप से यह निर्धारित नहीं होगा कि कोरियाई आयात कम कीमत पर विशेष रूप से भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाते हैं।
- भभ. निर्यात निष्पादन के कारण क्षति की जांच भी करनी चाहिए।
- मम. कोई क्षमता विस्तार नहीं करने के बावजूद आवेदकों की मूल्यहास लागत में वृद्धि हुई है।
- यय. आवेदकों ने तब भी पूर्ववर्ती वर्ष में लाभ दर्ज किया है जब आयात में वृद्धि हुई थी। इससे पता चलता है कि बड़े हुए आयात और लाभप्रदता में गिरावट के बीच कोई सहसंबंध नहीं है।
- ककक. अन्य उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि ब्याज कर और मूल्यहास से पहले उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- खखख. भारतीय उद्योग को क्षति परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण भी हो सकती है।

ज. 2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

75. क्षति के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. कोरियाई उत्पादकों ने विशेष रूप से भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाया है। भारत को निर्यातों की एफओबी कीमत तीसरे देशों को औसत निर्यात कीमत से स्पष्ट रूप से कम रही है।
- ख. बिल्कुल हाल की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर दबाव पड़ा है।
- ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग में संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के कारण गिरावट आई है।
- घ. बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जिससे घरेलू बिक्रियों में कमी हुई है।

- ड. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में तेजी से गिरावट आई है और बिल्कुल हाल की अवधि में यह न्यूनतम स्तर पर रहा था।
- च. घरेलू उद्योग को आयातों में दूसरी वृद्धि के समय से आधार वर्ष में घाटा हुआ था। अगले वर्ष में जब घरेलू उद्योग ने आयात कीमत की प्रतिस्पर्धा में कीमतें कम करके बाजार हिस्सा बढ़ाने का प्रयास किया तो घाटे में वृद्धि हुई।
- छ. वर्ष 2020-21 में लाभप्रदता में सुधार हुआ, क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा गंवा दिया। निष्पादन में 2021-22 की पहली छमाही में और सुधार हुआ क्योंकि आयातों में तेजी से गिरावट आई। तथापि, घरेलू उद्योग को पुनः आयातों में वृद्धि और बाजार हिस्से में गिरावट के कारण बिल्कुल हाल की अवधि में घाटा हुआ है।
- ज. बड़े उत्पादक से अलग एमएसएमई उत्पादक निरंतर घाटा नहीं झेल सकता है। आयात प्रतिस्पर्धा का प्रभाव अधिकांशतः बिक्री पर पड़ता है और इसलिए उसे मात्रा मापदंड में देखा जा सकता है।
- झ. यदि घाटे लंबी अवधि तक जारी रहते हैं तो उत्पादक उत्पादन रोक देगा। उत्पादक केवल तभी कोई आर्डर लेता है यदि उसमें कुछ वित्तीय व्यवहार्यता हो, अन्यथा वित्तीय घाटा उठाने के बजाय वे उत्पादन कम कर देंगे।
- ञ. यद्यपि यह कानूनी अपेक्षा महानिदेशक के लिए है कि वे समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बजाय घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करें, तथापि, भारतीय उद्योग के आंकड़े भी दर्शाते हैं कि उत्पादन में 2018-19 तक वृद्धि हुई, परंतु उसके बाद गिरावट आई है और घरेलू बिक्रियों में आयातों में वृद्धि आने से पहले वृद्धि हुई, परंतु उसके बाद गिरावट आई है।
- ट. बिल्कुल हाल की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय ऋणात्मक है। घरेलू उद्योग स्थिर खर्चों की वसूली नहीं कर पा रहा है और वस्तु की प्रत्यक्ष उत्पादन लागत की वसूली करने में असमर्थ है।
- ठ. ऋणात्मक कीमत कटौती दर्शाने वाले आंकड़ों का कारण कच्ची सामग्री की कीमत में भारी परिवर्तन और इस अवधि में उत्पाद की कीमत में परिवर्तन रहा है।
- ड. यदि कच्ची सामग्री की कीमत में परिवर्तन के कारण उत्पाद की कीमत में अस्थिरता रही भी हो तो भी तथ्य यह है कि आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई गंभीर क्षति तैयार उत्पाद पर टैरिफ रियायत के कारण हुई है और न कि कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क के कारण। विपरीत शुल्क संरचना वर्तमान शुल्क रियायतों के कारण बनी है। यदि शुल्क रियायत हटा दी जाती है तो भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।
- ण. यह तथ्य कि बिक्री, बोली प्रक्रिया के माध्यम से होती है, स्वयं दर्शाता है कि उपभोक्ता उन आपूर्तिकर्ताओं से खरीद करते हैं जिनकी कीमतें न्यूनतम हों।
- त. जब भी उद्योग ने लाभ कमाने का प्रयास किया तो उसे बाजार हिस्सा गंवाना पड़ा और जब भी उसने बाजार प्राप्त करने का प्रयास किया तो उसे घाटा हुआ।
- थ. भारत – कोरिया व्यापक भागीदारी करार के अनुच्छेद 2.22 के उक्त नोट में बताया गया है कि सीमा शुल्क में कटौती घरेलू उद्योग को क्षति का एक मात्र कारण नहीं हो सकती है।
- द. एक मात्र अपेक्षा यह है कि आयात क्षति का पर्याप्त कारण होने चाहिए। फ़ैलिक एनहाइड्राइड के आयातों से संबंधित द्विपक्षीय रक्षोपायों जांच के निष्कर्ष का भी उल्लेख किया गया है जिसमें महानिदेशक ने यही राय अपनाई थी।
- ध. कच्ची सामग्री की कीमत में कीमत अस्थिरता समान रूप से कोरियाई उत्पादकों को प्रभावित कर रही है क्योंकि वे कच्ची सामग्री का आयात करते हैं। यदि कोरिया से आयातों में कोई वृद्धि नहीं होती तो घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि होने पर अपनी कीमतें बढ़ा सकता था।

- न. क्षति के कारण के रूप में मालभाड़े में वृद्धि के संबंध में, इसने कोरियाई उत्पादकों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि वे कच्ची सामग्री का आयात करते हैं और भारत का संबद्ध वस्तु का निर्यात करते हैं।
- प. अन्य देशों से आयात कोरिया से आयातों द्वारा प्रतिस्थापित हुए हैं। चीन से आयातों में वृद्धि कम मात्रा में है और उससे क्षति नहीं हो सकती है। कुल मांग में चीन के आयातों का हिस्सा हमेशा 3 प्रतिशत या उससे कम रहा है।
- फ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातों की मात्रा नगण्य है और इसलिए निर्यात निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

ज.3 महानिदेशक द्वारा जांच

76. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दी गई सूचना और महानिदेशक द्वारा मांगी गई आयात सूचना पर वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। महानिदेशक नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने एक जैसे तर्क दिए हैं। तथापि, उनका तरीका और भाषा अलग-अलग है। महानिदेशक ने वर्तमान जांच परिणाम में अनुरोधों की जांच और समाधान किया है। गंभीर क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में नीचे की गई जांच वास्तव में आवेदकों और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों से संबंधित है।
77. नियमावली के अंतर्गत गंभीर क्षति निम्नानुसार परिभाषित है:-

(च) गंभीर क्षति से घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी अधिक समग्र गिरावट अभिप्रेत है; और

(छ) “गंभीर क्षति के खतरे” से ऐसी गंभीर क्षति अभिप्रेत है जो तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से आसन्न हो और केवल आरोप, संयोग और सुदूर संभावना पर आधारित न हो।

78. नियमावली के नियम 7 में भी निम्नानुसार व्यवस्था है:

महानिदेशक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करेंगे, अर्थात:-

(क) महानिदेशक विशेष रूप से उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों और समग्र तथा सापेक्ष रूप से मूलतः की वस्तु के आयात में वृद्धि की दर और राशि, मूलता की वस्तु के बढ़े हुए आयातों द्वारा दिए गए घरेलू बाजार के हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और घाटा तथा रोजगार के स्तरों में परिवर्तन का मूल्यांकन करेंगे; और

(ख) इस नियम के अंतर्गत निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर जांच मूलता के देश के बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति या उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी न दर्शाती हो और जब मूलता की वस्तु के बढ़े हुए आयात से इतर कारण से घरेलू उद्योग को उसी समय क्षति हो रही हो तो ऐसी क्षति के लिए मूलता की वस्तु के बढ़े हुए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

79. सीईपीए के निम्नलिखित प्रावधान घरेलू उद्योग को क्षति के विश्लेषण और जांच तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों के मूल्यांकन के लिए भी संगत है।

“केवल संक्रमण अवधि के दौरान यदि इस करार के अंतर्गत किसी सीमा शुल्क³ में कटौती या समाप्ति के परिणामस्वरूप दूसरे पक्षकार के मूलता की वस्तु ऐसी समग्र या घरेलू उत्पादन की दृष्टि से बड़ी हुई मात्राओं में किसी पक्षकार के क्षेत्र में आयातित की जा रही हो और ऐसी दशाओं में जहां केवल अन्य पक्षकार से ऐसी वस्तु के

आयात⁴ के कारण समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या उसके खतरे का मुख्य कारण हो तो पक्षकार निम्नलिखित कर सकता है:-

³कोई निर्धारण जिसमें किसी मूलता की वस्तु को इस करार के अंतर्गत प्रदत्त सीमा शुल्क में कटौती या समापन के परिणामस्वरूप आयात किया जा रहा है, केवल तभी किया जाएगा यदि ऐसी कटौती या समाप्ति वह वजह हो जिससे आयातों में भारी वृद्धि हुई हो, परंतु यह किसी अन्य कारण के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसी कटौती या समाप्ति के शुरुआत या समापन तथा आयात में वृद्धि के बीच समय बीत जाने से ही इस फुटनोट में संदर्भित निर्धारण स्वयं वर्जित नहीं हो जाएगा। यदि आयात में वृद्धि ऐसी कटौती या समाप्ति से स्पष्ट रूप से असंबंधित हो तो इस फुटनोट में संदर्भित निर्धारण नहीं किया जाएगा।

⁴निश्चितता के प्रयोजनार्थ पक्षकारों को यह समझना है कि किसी पक्षकार को गैर-पक्षकार के क्षेत्र से आयातों में वृद्धि होने पर द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने से रोका नहीं जाएगा। और अधिक निश्चितता के लिए पक्षकार यह समझें कि द्विपक्षीय रक्षोपाय केवल दूसरे पक्षकार की वस्तु पर तब लागू हो सकते हैं जब केवल उस अन्य पक्षकार से ऐसी वस्तु के आयात में हुई वृद्धि समान या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का पर्याप्त कारण बनती हो।।

80. महानिदेशक मानते हैं कि विभिन्न क्षति मापदंडों का मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों और स्थितियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। महानिदेशक ने वर्तमान मामले के तथ्यों और वर्तमान उद्योग की स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की मौजूदगी के तथ्य की जांच की है।
81. महानिदेशक ने नोट किया है कि वर्तमान मामले में भारतीय उद्योगों एमएसएमई क्षेत्र के उत्पादक शामिल हैं। यद्यपि, समग्र रूप से मूल्यवर्धन काफी अधिक है, परंतु निविष्ट कच्ची सामग्रियों की कीमत की दृष्टि से यह कम है। फेमो की कीमत सामान्यतः मोली की प्रचलित कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की जाती है।
82. हितवद्ध पक्षों ने यह भी दलील दी है कि उत्पादक की बिक्री बोली प्रक्रिया के माध्यम से होती है। घरेलू उद्योग ने भी हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क को स्वीकार किया है। महानिदेशक नोट करते हैं कि यह तथ्य की उत्पाद की बिक्री बोली प्रक्रिया के जरिए होती है। दर्शाता है कि प्रयोक्ता ऐसे आपूर्तिकर्ता से उत्पाद खरीदना पसंद करेंगे जिसकी कीमत कम से कम हो। इसके अलावा, हितवद्ध पक्षकारों ने इस बात का कोई अन्य औचित्य नहीं बताया है कि कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि क्यों हुई है। अतः यह निष्कर्ष है कि कोरिया गणराज्य से आयात में वृद्धि कोरियाई उत्पादकों के पास कीमत संबंधी लाभ की वजह से हुई है। कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि की दर, अन्य देशों से आयातों में गिरावट और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट दर्शाती है कि कोरियाई उत्पादकों ने बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कम कीमत रखी है।
83. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक के निष्पादन पर भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि की वजह से प्रभाव पड़ा है। महानिदेशक नोट करते हैं कि यदि उद्योग को इस कारण से नुकसान हुआ होता तो यह बात सभी देशों से सभी उत्पादों और विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर भी लागू होती। इसके अलावा, मुद्रा का अवमूल्यन कोरियाई उत्पादों के लिए भी समान रूप से लागू है। अतः इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
84. आवेदकों द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि बिक्री लागत का 90 प्रतिशत अधिक परिवर्तनशील लागत है और उत्पादकों पर उच्च स्थिर लागत का कोई बोझ नहीं है। अतः उत्पादक कोई आदेश सामान्यतः तभी लेंगे यदि कुछ वित्तीय लाभ होता हो। अर्थात् यदि उद्धरित आदेश उत्पादन लागत से अधिक हो। यदि कोई वित्तीय लाभ नहीं होगा तो उत्पादक सामान्यतः वित्तीय घाटा उठाने के बजाय उत्पादन में कटौती करेंगे। एमएसएमई के प्रकृति के कारण उत्पादक व्यवसाय में निवेश करना जारी नहीं रख सकते हैं। अतः आयात प्रतिस्पर्धा का प्रभाव अधिकांशतः बिक्रियों और उत्पादन मात्रा पर पड़ता है। आवेदकों ने यह दलील दी है कि भारतीय उद्योग को क्षति का प्राथमिक रूप मात्रा संबंधी मापदंडों में देखा जा सकता है।
85. इस दलील के संबंध में कि भारतीय उत्पादक कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क के कारण अंतर्निहित रूप से कम प्रतिस्पर्धी हैं, महानिदेशक नोट करते हैं कि भारत सरकार चिली और थाईलैंड से आयातित मोली पर टैरिफ

रियायत प्रदान की है और घरेलू उद्योग ने बताया है कि लगभग 70 प्रतिशत आयात इन स्रोतों से होते हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय उद्योग सीमा शुल्क के कारण कम प्रतिस्पर्धी है। कोरियाई उत्पादकों के पास कच्ची सामग्री का कोई प्राकृतिक लाभ नहीं है। वर्तमान जांच का दायरा यह है कि क्या फेमो के आयातों में वृद्धि हुई है और क्या इससे भारतीय उद्योग को क्षति हुई है और यदि हां, तो क्या रक्षोपाय लगाये जाने चाहिए।

86. इस तर्क के संबंध में कि भारत में अन्य उत्पादकों का निष्पादन सुधार दर्शाता है, महानिदेशक ने रिकार्ड में अन्य उत्पादकों की सूचना पर विचार किया है अन्य कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट से यह देखा गया है कि ये उत्पादक बहुउत्पाद कंपनियां हैं और इसलिए वार्षिक रिपोर्ट के उल्लेख पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, 5 उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग संबंधी सूचना है जो दर्शाती है कि उन्हें भी मात्रा संबंधी मापदंडों में नुकसान हुआ है।
87. इस तर्क के संबंध में कि कीमत अस्थिरता कुछ अन्य कारकों की वजह से हुई है और न कि केवल आयातों की वजह से, महानिदेशक नोट करते हैं कि मोली डेनम की कीमतों में हाल की अवधि के दौरान काफी अस्थिरता आई है और आयातों की पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री लागत की दिशा भी वही रही है।

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल से सितंबर 21	अक्टूबर से मार्च 22
1	पहुंच कीमत	1,228	1,136	955	1,783	2,079
2	बिक्रियों की लागत	***	***	***	***	***
3	बिक्री कीमत	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध					
5	पहुंच कीमत	100	93	78	145	169
6	बिक्रियों की लागत	100	88	91	135	165
7	बिक्री कीमत	100	96	91	137	166

यूओएम – रु./कि.ग्रा.

88. यह तर्क दिया गया है कि कोरियाई उत्पादक अधिक समेकित हैं क्योंकि वे अन्य रोस्टेड मोली डेनम का प्रयोग करते हैं और इसलिए भारतीय उत्पादकों की तुलना में अधिक कुशल हैं। महानिदेशक नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पूर्ववर्ती वर्ष में लाभ अर्जित कर सकता था। दर्शाता है कि वह आयातों से मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा, महानिदेशक को रोस्टेड या अनरोस्टेड मोली के कारण लागत में अंतर दर्शाने की कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है।
89. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक अधिक क्षमताओं के कारण नुकसान उठा रहे हैं। महानिदेशक मानते हैं कि पर्याप्त या अधिक क्षमताओं की स्थिति में यह स्पष्ट है कि आयातों में किसी वृद्धि से गंभीर क्षति होगी। कोरियाई उत्पादकों के पास भी उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं मौजूद हैं। यदि भारतीय उद्योग को अत्यधिक क्षमताओं के कारण नुकसान हुआ है तो वह ऐसी अत्यधिक क्षमताओं के बावजूद आयातों की वृद्धि की वजह से हुआ है। महानिदेशक ने बिक्री कीमत और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर की जांच की है जो निम्नानुसार दर्शाती है:-

क्र. सं.	विवरण	यूएम	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल से सितंबर 21	अक्टूबर से मार्च 22
1	बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	100	96	91	137	166
2	परिवर्तनशील लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***

3	अंशदान	रू./कि.ग्रा.	100	226	112	147	63
---	--------	--------------	-----	-----	-----	-----	----

90. इस तर्क के संबंध में कि भारतीय उत्पादकों पर स्थिर लागतों का बोझ है। महानिदेशक ने आवेदकों के आंकड़ों की जांच की है। यह देखा गया है कि आवेदकों की कुल लागत में स्थिर लागतों का हिस्सा मामूली है। इसके अलावा, बिल्कुल हाल की अवधि में आवेदकों का अंशदान (बिक्री कीमत और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर) आधार वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में अर्जित अंशदान से कम है। तथापि, आवेदकों ने बताया है कि उद्योग की वर्तमान प्रकृति को देखते हुए क्षति का संगत रूप मात्रा संबंधी क्षति है।
91. यह तर्क दिया गया है कि अन्य देशों (विशेष रूप से चीन) से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। महानिदेशक ने पूरी संगत अवधि में चीन से आयातों की मात्रा की जांच की है। निम्नांकित तालिका जांच अवधि के दौरान फेमो के आयातों को दर्शाती है।

क्र. सं.	देश	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल से सितंबर 21 (क)	अक्टूबर 21 से मार्च 22 (क)
1	कोरिया गणराज्य	एमटी	1,957	2,361	2,967	1,872	3,966
2	चीन जन. गण.	एमटी	20	20	-	-	320
3	सं. अरब अमीरात	एमटी	140	40	80	40	2
4	स्विटजरलैंड	एमटी	-	79	100	240	80
5	हांगकांग	एमटी	140	90	-	-	-
6	यूएसए	एमटी	40	-	-	-	-
7	सिंगापुर	एमटी	40	20	-	-	-
8	जर्मनी	एमटी	15	20	5	-	-
9	ब्राजील	एमटी	7	21	-	-	-
10	दक्षिण अफ्रीका	एमटी	-	20	-	-	-
11	कनाडा	एमटी	-	-	5	-	-
12	स्वीडन	एमटी	-	-	-	-	3
13	मलेशिया	एमटी	1	-	-	-	-
14	कुल	एमटी	2,359	2,670	3,157	2,152	4,370

92. यह देखा गया है कि पूर्व में यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से भी आयात होते थे। तथापि, अब वे आयात पूर्णतः बंद हो गए हैं। यह देखा गया है कि चीन से आयात बिल्कुल हाल की अवधि को छोड़कर पूरी क्षति अवधि में काफी कम रहे हैं। जहां तक वर्तमान अवधि का संबंध है। यह देखा गया है कि यद्यपि कोरियाई आयात 3562 एमटी थे परंतु जबकि चीन से आयात केवल 320 एमटी (वार्षिकीकृत आधार पर) रहे थे। महानिदेशक ने जांच अवधि में आयातों के रुझान की भी जांच की है और पाया कि चीन से आयातों में कोई निरंतरता नहीं है। पूरी अवधि में चीन से आयात केवल आठ माह में हुए हैं और केवल कुल 280 एमटी के हैं। अतः चीन और अन्य देशों से आयातों की मात्रा बिल्कुल हाल की अवधि में इतनी कम है कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति

नहीं हो सकती है। किसी भी तरह महानिदेशक ने पर्याप्त लंबी अवधि पर विचार किया है जो दर्शाती है कि अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से बहुत कम है।

93. हितवद्ध पक्षकारों ने यह भी बताया है कि परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हो सकती है। महानिदेशक नोट करते हैं कि उन्होंने आवेदकों और समर्थकों के निष्पादन रूझानों की जांच की है। जब आवेदकों और समर्थकों दोनों के उत्पादन और घरेलू बिक्री में आयातों में वृद्धि के साथ गिरावट आई है तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि इन मापदंडों में गिरावट केवल परस्पर प्रतिस्पर्धा से आई है।
94. यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों की मूल्यहास लागत में क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद वृद्धि हुई है। महानिदेशक ने आवेदकों द्वारा रखे गए रिकार्डों की जांच की है और यह देखा गया है कि वह लेखा पुस्तिकों में आवंटन पद्धति के अनुसार हैं। तथापि, महानिदेशक ने दावा की गई मूल्यहास लागत को स्वीकार नहीं किया है और संशोधित सूचना पर विचार किया है।
95. अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने यह भी बताया है कि आवेदकों की पूंजी पर आय में जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। महानिदेशक नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर आय वर्तमान जांच में उत्पाद की प्रकृति के कारण भारतीय उद्योग को क्षति की जांच करने का संगत कारक नहीं है। किसी भी तरह आवेदक ने बताया है कि क्षति का प्राथमिक रूप मात्रात्मक क्षति है।
96. गंभीर क्षति का विश्लेषण करने में नियमावली में उल्लिखित कारक तथा महानिदेशक की जानकारी में लाये गए और गंभीर क्षति के निर्धारण में संगत समझे गए अन्य कारक सभी कारकों पर विचार किया गया है। इस प्रकार गंभीर क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग की स्थिति उत्पाद का उच्च मूल्य और कम पूंजी नियोजित पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

97. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां संबंधी तथ्य नीचे दिये गए हैं।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल से सितंबर 21 क	अक्टूबर से मार्च 22 क
1	क्षमता	एमटी	6,216	6,216	6,216	6,216	6,216
2	उत्पादन	एमटी	2,572	2,183	2,376	2,794	2,214
3	क्षमता उपयोग	%	41%	35%	38%	45%	35%
4	घरेलू बिक्रियां	एमटी	2,516	2,304	2,354	2,809	2,509
5	मांग	एमटी	8,695	8,448	8,762	8,509	10,250
6	आयात	एमटी	1,957	2,361	2,967	1,872	3,966
7	मांग में बाजार हिस्सा	%	29%	27%	27%	33%	24%

98. यह देखा गया है कि:

- क. आवेदक कंपनियों की क्षमता पूरी क्षति अवधि में समान बनी रही है। भारतीय उद्योग की क्षमता देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2019-20 में मांग में गिरावट होने पर गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, क्योंकि मांग बढ़ी और आयात घटे हैं। तथापि, उत्पादन में वृद्धि मांग में वृद्धि पर विचार करते हुए काफी कम रही थी।

- ग. उत्पादन और क्षमता उपयोग में मांग में गिरावट के बावजूद अप्रैल से सितंबर, 2021 में वृद्धि हुई है क्योंकि आयातों में गिरावट आई है। अक्टूबर, 21 से मार्च, 22 में आयातों में वृद्धि के साथ बिल्कुल हाल की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- घ. उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 2019-20 में गिरावट आई है परंतु उसके बाद 2020-21 में वृद्धि हुई है। तथापि, यद्यपि घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है परंतु इस अवधि में आयातों में वृद्धि के कारण बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू बिक्रियों में आयातों में गिरावट के कारण अप्रैल 21 से सितंबर, 21 तक वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू बिक्रियां अक्टूबर से मार्च, 2022 में कम हुई हैं।
- ड. अप्रैल, 21 से मार्च, 22 की अवधि के दौरान मांग में संगत अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, मांग में संपूर्ण वृद्धि को कोरियाई आयातों ने खपा दिया है। यद्यपि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। उद्योग की घरेलू बिक्रियों में मांग में वृद्धि के कारण वृद्धि नहीं हुई है।
- च. अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 (सबसे हाल की अवधि) में संबद्ध वस्तुओं की मांग में अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 की तुलना में 871 एमटी (वास्तविक आधार) और 1,741 एमटी (वार्षिक आधार) की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान आयात में वृद्धि हुई है। 1,047 मीट्रिक टन (वास्तविक आधार) और 2,094 मीट्रिक टन (वार्षिक आधार)। आयात में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि से अधिक है और इसके परिणामस्वरूप आवेदकों की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
99. आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि जब पहली बार टैरिफ रियायतें शुरू हुईं तो भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा 87 प्रतिशत था। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा टैरिफ रियायत बढ़ने के साथ समान स्तर पर बना रहा और 2016-17 में पूर्ण स्तरों पर पहुंच गया। तथापि भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा इसके बाद घटना शुरू हो गया क्योंकि कोरियाई आयातों में वृद्धि हुई। इस प्रकार टैरिफ रियायतों के कारण भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। यह देखा गया है कि यद्यपि मांग में वृद्धि हुई, परंतु घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- ख. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा
100. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	निम्न का बाजार हिस्सा	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल 21 – सितंबर 21	अक्टूबर 21 – मार्च 22
1	आवेदक	%	29%	27%	27%	33%	24%
2	अन्य उत्पादक	%	44%	41%	37%	42%	33%
3	भारतीय उद्योग	%	73%	68%	64%	75%	57%
3	कोरियाई आयात	%	23%	28%	34%	22%	39%
4	अन्य देश	%	5%	4%	2%	3%	4%

101. यह देखा गया है कि:-

- क. आवेदकों के बाजार हिस्से में 2019-20 में गिरावट आई है और 2020-21 में लगभग समान स्तर पर रहा है। आवेदकों का बाजार हिस्सा अप्रैल से सितंबर, 2021 में बढ़ा है जब आयात कम हुए थे। परंतु बिल्कुल हाल की अवधि में पुनः कम हुआ है।
- ख. आधार वर्ष और पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में हाल की अवधि में आवेदकों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। नवीनतम अवधि में आवेदकों का बाजार हिस्सा पूरी जांच अवधि में सबसे कम है।

- ग. भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में भी आवेदकों के जैसा रुझान रहा है। बाजार हिस्से में 2019-20 में गिरावट आई। उसके बाद वर्ष 2020-21 में और अधिक गिरावट आई है। भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा अप्रैल से सितंबर, 2021 में बढ़ा है। परंतु बिल्कुल हाल की अवधि में इसमें पुनः गिरावट आई है।
- घ. आयातों के बाजार हिस्से में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में वृद्धि हुई है। आयातों के बाजार हिस्से में 2020-21 में पुनः वृद्धि हुई है। अप्रैल से सितंबर, 2021 में बाजार हिस्से में गिरावट आई है परंतु बिल्कुल हाल की अवधि में यह पुनः बढ़ा है। संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. मालसूची

102. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से संबंधी सूचना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल 21 – सितंबर 21	अक्टूबर 21 – मार्च 22
1	आरंभिक	एमटी	***	***	***	***	***
2	अंतिम	एमटी	***	***	***	***	***
3	औसत	एमटी	29	77	107	110	92
4	घरेलू बिक्रियां	एमटी	2,516	2,304	2,354	2,809	2,509

103. यह देखा गया है कि आवेदकों की अंतिम मालसूची में 2019-20 में वृद्धि हुई है, क्योंकि घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है। अंतिम मालसूची 2020-21 और अप्रैल 21 से सितंबर, 21 में लगभग समान स्तर पर रही हैं। परंतु अक्टूबर, 21 से मार्च, 22 में कम हुई हैं। घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में सितंबर, 2021 तक वृद्धि हुई है। यद्यपि उत्पादन में कटौती के कारण उसके बाद मालसूची में गिरावट आई है, फिर भी मालसूची का स्तर काफी अधिक रहा है।

घ. लाभ/हानि

104. लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ संबंधी तथ्य निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल 21 – सितंबर 21	अक्टूबर 21 – मार्च 22
1	बिक्रियों की लागत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	91	135	166
2	बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	91	137	166
3	लाभ/(हानि)	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	480	116	244	160

4	पीवीआईटी	रू./कि. ग्रा.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	344	108	174	118
5	नकद लाभ	रू./कि. ग्रा.	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	465	123	240	159

105. यह देखा गया है कि:-

- क. आवेदकों की लाभप्रदता में 2019-20 तक सुधार हुआ है। प्रति इकाई लाभ में 2020-21 में गिरावट आई है क्योंकि आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, अप्रैल से सितंबर, 2021 की अवधि में प्रति इकाई लाभ में सुधार हुआ है क्योंकि आयातों में गिरावट आई है।
- ख. अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 में आयातों में वृद्धि के साथ आवेदकों के प्रति इकाई लाभ में पुनः गिरावट आई है।
- ग. नकद लाभ और ब्याज और कर पूर्व लाभ में भी समान प्रवृत्ति रही है। नकद लाभ और कर तथा ब्याज पूर्व लाभ में आयातों में गिरावट के कारण सुधार हुआ है। परंतु हाल की अवधि में गिरावट आई है।
- घ. तथापि, यह भी तर्क दिया गया है कि एमएसएमई प्रकृति तथा विचाराधीन उत्पाद के मूल्य को देखते हुए वास्तविक क्षति मात्रात्मक क्षति के रूप में हुई है।

ड. रोजगार एवं उत्पादकता

106. रोजगार और उत्पादकता संबंधित तथ्य नीचे दिए गए हैं।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रैल 21 - सितंबर 21	अक्टूबर 21 - मार्च 22
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	129	130	150	141	141
2	प्रति कर्मचारी की उत्पादकता	एमटी/सं.	20	17	16	20	16
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	8	7	7	8	7

107. यह देखा गया है कि:-

- क. वर्ष 2020-21 तक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है परंतु उसके बाद गिरावट आई है।
- ख. प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2020-21 तक कम हुई है परंतु अप्रैल से सितंबर, 2021 में उत्पादन में वृद्धि के साथ इसमें वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में हाल की अवधि में पुनः गिरावट आई है।
- ग. प्रति दिन उत्पादकता में 2019-20 में गिरावट आई है परंतु उसके बाद 2020-21 और अप्रैल से सितंबर, 2021 में वृद्धि हुई है। अक्टूबर, 2021 से मार्च 2022 की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट आई है।
- घ. आवेदकों ने इन मापदंडों पर क्षति का दावा नहीं किया है।

च. कीमत कटौती

108. कीमत कटौती के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	अक्टूबर 21 – मार्च 22
1	बिक्री कीमत	रू./कि.ग्रा.	***
2	पहुंच कीमत	रू./कि.ग्रा.	2,079
3	कीमत कटौती	रू./कि.ग्रा.	***
4	कीमत कटौती	%	***
5	कीमत कटौती	प्रवृत्ति	(0-5) %

109. यह देखा गया है कि भारत औसत आधार पर कीमत कटौती ऋणात्मक है। यह दलील दी गई है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में काफी अस्थिरता रही है और इसलिए औसत कीमत कटौती संगत मापदंड नहीं हो सकता है। नीचे दी गई तालिका एक माह विशेष में कीमत का रुझान दर्शाती है।

क्र. सं.	माह	औसत कीमत	अधिकतम कीमत	न्यूनतम कीमत
1	अप्रैल – 21	1,314	1,399	1,256
2	मई – 21	1,419	2,037	1,176
3	जून – 21	1,629	2,070	1,242
4	जुलाई – 21	1,707	2,392	1,231
5	अगस्त – 21	2,070	2,468	1,647
6	सितंबर – 21	2,019	2,441	1,262
7	अक्टूबर – 21	2,048	2,317	1,663
8	नवंबर – 21	2,050	2,285	1,874
9	दिसंबर – 21	2,081	2,172	1,976
10	जनवरी- 22	2,038	2,127	1,899
11	फरवरी – 22	2,131	2,282	2,037
12	मार्च - 22	2,139	2,510	2,016

110. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत में एक विशेष महीने में भी काफी अस्थिरता रही है और इसलिए औसत आधार पर कीमत कटौती पर विचार करना संगत नहीं हो सकता है।

111. महानिदेशक यह भी नोट करते हैं कि उत्तर देने वाले निर्यातक ने कहा है कि उत्पाद की बिक्री बोली प्रक्रिया के माध्यम से होती है जिसे आवेदकों द्वारा स्वीकार किया गया है। तथ्य यह है कि उत्पाद की बिक्री बोली के माध्यम

से होती है और आयात में वृद्धि के किसी अन्य कारण को दर्शाने के लिए कोई सामग्री आगे नहीं लाई गई है, यह तर्क दिया गया है कि कोरिया से आयात इसलिए होता है क्योंकि वे कम कीमत के होते हैं।

112. यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री और उत्पादन में गिरावट के संदर्भ में आवेदकों के बिगड़ते प्रदर्शन को देखते हुए और बढ़े हुए आयातों के कारण बाजार हिस्सेदारी में कमी को देखते हुए यह इस तथ्य का विरोध है कि मूल्य क्षति बढ़े हुए आयातों के कारण प्रमुख है। टैरिफ रियायत की।

ड.6 निष्कर्ष

113. उक्त के आधार पर महानिदेशक के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

- क. आवेदकों के उत्पादन और क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है।
- ख. भारत में समूची मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता के बावजूद भारतीय उद्योग काफी कम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है।
- ग. आवेदकों की घरेलू बिक्रियां और उत्पादन जांच अवधि के दौरान समान स्तर पर रहा है। यद्यपि मांग में वृद्धि हुई है फिर भी आवेदक उसी दर पर अपनी घरेलू बिक्रियों में वृद्धि करने में समर्थ रहे हैं।
- घ. अक्टूबर, 21 से मार्च 22 की अवधि के दौरान संगत अवधि की तुलना में मांग में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, संपूर्ण बढ़ी हुई मांग पर घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद कोरियाई आयातों ने कब्जा कर लिया है। आयातों ने भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा छीन लिया है।
- ड. आवेदकों और भारतीय उद्योग ने कोरिया गणराज्य से बढ़े हुए आयातों के कारण अपने बाजार हिस्से में गिरावट का सामना किया है।
- च. बिलकुल हाल की अवधि में आवेदकों का अंशदान जांच अवधि की दृष्टि से न्यूनतम रहा है।
- छ. उद्योग के लिए क्षति का प्राथमिक क्षेत्र मात्रात्मक मापदंड हैं। तथापि, उन्हें लाभप्रदता में गिरावट झेलनी पड़ी है।
- ज. कोरिया गणराज्य से आयात उनकी कमतर कीमतों के कारण हुए हैं।

114. विभिन्न मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को कोरियाई आयातों को प्रदत्त शुल्क रियायतों की वजह से गंभीर क्षति उठानी पड़ी है जिससे कम कीमतों पर कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के भारी आयात हुए हैं।

झ. कारणात्मक संबंध

115. घरेलू उद्योग निष्पादन के यहां उपर्युक्त व्यापक मूल्यांकन से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। अतः इस बात की जांच की गई है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति मुख्यतः शुल्क में रियायतों और परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि के कारण हुई है। इस बात की जांच की गई थी कि क्या कोरियाई आयातों में वृद्धि से इतर किसी कारक की वजह से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। तथापि, यह स्पष्ट रूप से समझा गया है कि कोरियाई आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक मात्र कारण नहीं हो सकते हैं। उद्योग अन्य कारकों की वजह से क्षति उठा सकता है और उनका अर्थ कोरियाई आयातों से क्षति का अभाव नहीं है।

i. अन्य देशों से आयात

116. उपर्युक्त जांच के अनुसार अन्य देशों से आयात भारतीय उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते हैं।

ii. उत्पाद के लिए मांग

117. संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार मांग में ऐसी कोई कमी नहीं आई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

iii. प्रौद्योगिकी में विकास

118. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा खास बदलाव हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए ये कारक जिम्मेदार नहीं होते हैं।
- iv. प्रतिस्पर्धा की स्थिति एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं
119. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं मौजूद हैं। अतः घरेलू उद्योग को क्षति के लिए ये कारक जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं।
- v. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन
120. उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं और इसलिए घरेलू उद्योग को इस वजह से क्षति नहीं हुई है।
- vi. निर्यात निष्पादन
121. महानिदेशक ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए अलग आंकड़ों पर विचार किया है और इसलिए निर्यात प्रचालनों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- vii. घरेलू उत्पादक के अन्य उत्पादों का निष्पादन
122. वर्तमान आवेदन में प्रदत्त आंकड़े केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित हैं। अतः अन्य उत्पादित उत्पादों तथा घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पादों का निष्पादन क्षति का कारण नहीं है।
- viii. उत्पादकता
123. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के रूझान का अनुसरण किया है और उत्पादकता में गिरावट के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
124. उक्त की जांच के आधार पर महानिदेशक का निष्कर्ष है कि आवेदकों को किसी अन्य कारक की वजह से क्षति नहीं हुई है। निम्नलिखित कारक घरेलू उद्योग को क्षति और कोरिया गणराज्य से बड़े हुए आयातों के बीच कारणात्मक संबंध दर्शाते हैं।
- क. टैरिफ रियायतों में वृद्धि के साथ कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि समग्र रूप से तथा भारतीय उत्पादन के संबंध में हुई है।
- ख. बड़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग तथा समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा किया है।
- ग. बाजार हिस्से में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों में गिरावट का सामना किया है और परिणामस्वरूप अपना उत्पादन कम किया है।
- घ. कोरिया गणराज्य से आयात टैरिफ रियायत का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए कमतर कीमत पर उपलब्ध हैं।
- ड. घरेलू उद्योग को कम कीमतों पर आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को मुनाफे में गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- च. अतः महानिदेशक का निष्कर्ष है कि बड़े हुए आयातों और आवेदकों को परिणामी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं।
- अ समायोजन योजना**
125. यह दलील दी गई है कि आवेदकों ने आवेदन के साथ समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है। महानिदेशक नोट करते हैं कि आवेदकों ने अपने आवेदन में निम्नलिखित प्रस्तुत किया था:-

“उद्योग अपनी लागत कम करने के लिए विभिन्न लागत कमी उपायों पर कार्य कर रहा है। लागत कटौती उपाय कच्ची सामग्री की लागत और परिवर्तन लागतों में कटौती की दिशा में किए गए हैं। याचिकाकर्ता प्रस्तावित जांच प्रक्रिया के दौरान इसकी पूरक सामग्री प्रदान करेंगे”।

126. शुरुआत के चरण में यह प्रदान किया गया था कि आवेदक लागत कम करने के उद्देश्य से प्रयास करेंगे। इसलिए, यह तर्क कि कोई समायोजन योजना प्रदान नहीं की गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदन में समायोजन योजना की आवश्यकता दीक्षा की आवश्यकता पर निर्णय लेने की दृष्टि से नहीं है। शुरुआत के चरण में केवल ऐसी सूचना पर विचार किया जाना अपेक्षित है जो शुरुआत के लिए प्रासंगिक है। समायोजन योजना अंतिम निर्धारण के समय शुल्क की अवधि के लिए प्रासंगिक है, जैसा कि नियम 10 के तहत प्रदान किया गया है, न कि शुरुआत के स्तर पर। घरेलू उद्योग ने किसी भी मामले में जांच शुरू करने के बाद आवेदन में निहित समायोजन योजना सूचना का अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है और उस पर महानिदेशक द्वारा विचार किया गया है।
127. आवेदकों ने उपायों को लागू किए जाने पर किए जाने वाले प्रस्तावित समायोजन योजना का विवरण प्रदान किया है। समायोजन योजना ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करने पर केंद्रित है। यह कहा गया है कि वर्तमान में बहुत सीमित ग्राहक दीर्घावधि अनुबंध के आधार पर उत्पाद खरीदते हैं। आयात की मात्रा में कमी से उद्योग को ऐसे और अधिक अनुबंध करने की अनुमति मिलेगी जो उद्योग को अपनी घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और कच्चे माल से जुड़े अंतिम उत्पाद के सूत्र-आधारित मूल्य निर्धारण का पालन करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, समायोजन योजना कच्चे माल की सूत्र-आधारित खरीद, अपशिष्ट वसूली में वृद्धि, नई मशीनों की स्थापना आदि पर भी ध्यान केंद्रित करती है। महानिदेशक नोट करते हैं कि आवेदकों ने एक समायोजन योजना तैयार की है जो इसे आयात के लिए प्रतिस्पर्धी बनने की अनुमति देगी।

ट. जनहित

ट.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

128. जनहित के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-
- क. इस्पात उद्योग में 30-40 प्रतिशत का मूल्यवर्धन होता है जबकि आवेदकों के पास केवल 5-10 प्रतिशत का मूल्यवर्धन है। द्विपक्षीय उपायों को लगाने से इस्पात उद्योग प्रभावित होगा।
 - ख. यदि द्विपक्षीय उपाय लागू होते हैं तो इससे विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति में रुकावट आएगी जिससे इस्पात उद्योग प्रभावित होगा।
 - ग. आवेदकों द्वारा यथासूचित डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर प्रभाव को साक्ष्यांकित नहीं किया गया है।
 - घ. प्रयोक्ता उद्योग की तकनीकी और धातु कर्म संबंधी जरूरतों को भारतीय उत्पादकों द्वारा सही ढंग से पूरा नहीं किया जाता है।
 - ङ. भारतीय इस्पात निर्माता मोली डेनम की एकरूपता, डिलीवरी समय, आपूर्ति की स्थिरता और बिक्री पश्चात सेवा के कारण कोरियाई आयातों को पसंद करते हैं।
 - च. विचाराधीन उत्पाद का मूल्य लगभग 20,00,000 रुपये प्रति एमटी है और 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क का अर्थ भी 100,000 रुपये प्रति एमटी का प्रभाव होगा। इसका प्रभाव डाउनस्ट्रीम इस्पात उत्पादक प्रयोक्ता उद्योग पर काफी अधिक होगा।
 - छ. चीन की एक नीति है जो 13 प्रतिशत वेट की वापसी नहीं करते फेमो के निर्यातों पर जुर्माना लगाती है। ऐसी नीतियों की मौजूदगी के साथ कोरियाई आयात भारत में प्रयोक्ता उद्योग को विश्वसनीय स्रोत और निरंतर आपूर्ति प्रदान करेंगे।
 - ज. निर्यातक उचित कीमत पर भारतीय बाजार के लिए गुणवत्तायुक्त उत्पाद प्रदान करने वाले एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में केवल भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- झ. अनेक अलाय इस्पात उत्पादक भी लघु एवं मध्यम उत्पादक हैं। अतः यह दलील की कि संबद्ध वस्तु के सभी उपभोक्ता बड़े उद्योग हैं, सही नहीं है।

ट.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

129. जनहित के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. भारतीय उद्योग के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता है और इसलिए आयात अनावश्यक हैं।
- ख. द्विपक्षीय उपायों से केवल टैरिफ रियायतें हटाई जाएंगी। उद्योग आयातों के विरुद्ध किसी अतिरिक्त टैरिफ की मांग नहीं कर रहा है।
- ग. जनहित केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है और उसमें विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उद्योग भी शामिल है।
- घ. यह उपभोक्ता के हित में है कि उचित कीमत के आयातों के मुकाबले उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग भी होना चाहिए।
- ड. विचाराधीन उत्पाद डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागत का एक मामूली हिस्सा है और टैरिफ रियायतें हटाने से उन पर बिल्कुल मामूली प्रभाव पड़ेगा।
- च. विचाराधीन उत्पाद की कीमत में 100 रूपए की वृद्धि के प्रभाव से डाउनस्ट्रीम के उत्पाद की कीमत में 1 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं होती है।
- छ. अंतिम उत्पादों के तैयार उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की मात्रा नगण्य है जिसका अर्थ है कि विचाराधीन उत्पाद डाउनस्ट्रीम उत्पादों का मामूली हिस्सा है।
- ज. घरेलू उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र के हैं और लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं। मूल सीमा शुल्क बहाल करने से छोटे उत्पादकों को नकारात्मक अंशदान के बिना उनके व्यवसाय बनाये रखने के लिए समय मिल जाएगा।
- झ. भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद की अपनी समस्त जरूरत को केवल भारतीय उद्योग से खरीद रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय उद्योग वांछित मात्राओं में सामग्री उपलब्ध कराता है।
- ञ. पूर्व में भारतीय उद्योग द्वारा पूरी की गई मांग की उच्च मात्रा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थ है।

ट.3 महानिदेशक द्वारा जांच

130. सीईपीए करार या नियमावली के अंतर्गत जनहित विश्लेषण करने की कोई स्पष्ट अपेक्षा नहीं है। तथापि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

“कोई सदस्य उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा केवल किसी जांच के अनुपालन में किसी रक्षोपाय को पहले से स्थापित प्रक्रिया के अनुपालन में और जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद X के अनुरूप लागू कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को तर्कसंगत सार्वजनिक सूचना और जन सुनवाई या अन्य समुचित साधन शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य तथा अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे तथा इसमें अन्य पक्षकारों के अनुरोधों के उत्तर देने तथा अन्य बातों के साथ-साथ अपने विचारों की क्या रक्षोपाय लागू करना जनहित में होगा अथवा नहीं, शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी अपने जांच परिणाम तथा तथ्य और कानून के सभी संगत मुद्दों पर निकाले गए अपने तर्कसंगत निष्कर्षों को सामने रखते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।”

131. महानिदेशक ने इस बात की जांच की है कि क्या रक्षोपाय लगाना व्यापक जनहित में होगा। यद्यपि अनुच्छेद 3.1 में मूल्यांकन के तरीके संबंधी कोई मार्गदर्शन नहीं है। तथापि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा है कि

विभिन्न हितधारकों पर रक्षोपाय के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए और विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों के विरोधी हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित विचार अपनाया जाए।

132. महानिदेशक ने आवेदकों, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और हितवद्ध पक्षकारों सहित सभी हितवद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। महानिदेशक ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति उत्पाद की आयातों से प्रतिस्थापनीयता, प्रयोक्ताओं द्वारा स्रोत बदलने की क्षमता और रियायतों को हटाने पर प्रयोक्ताओं पर प्रस्तावित उपायों के प्रभाव संबंधी सूचना मंगाई थी।
133. महानिदेशक नोट करते हैं कि वर्तमान उपाय कोई अतिरिक्त शुल्क लागू करने के बजाय केवल पहले से दी गई रियायतों को वापस लेने और वह भी केवल कोरिया के आयातों के संबंध में, की ओर निर्देशित हैं। सभी अन्य स्रोतों से आयात प्रस्तावित उपायों द्वारा पूर्णतः अप्रभावित हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपाय कोरियाई आयातों को अन्य देशों से आयातों के समतुल्य बना देंगे।
134. महानिदेशक ने एक प्रयोक्ता प्रश्नावली विहित की है जिसमें प्रयोक्ता को अंतिम उत्पाद तथा उपभोक्ता के अंतिम उत्पाद की कीमत में विचाराधीन उत्पाद की लागत संबंधी सूचना देना अपेक्षित है। प्रयोक्ताओं और आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना पर प्रस्तावित उपायों के प्रभाव का पता लगाने के लिए विचार किया गया है।
135. इस तर्क के संबंध में कि द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू होने से विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होगी और डाउनस्ट्रीम उद्योग प्रभावित होंगे, महानिदेशक मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर दी गई रियायतों को हटाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, महानिदेशक ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर फेमो की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव पर विचार किया है और यह पाया है कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद और उद्योग के समग्र प्रचालन पर इसका प्रभाव बिल्कुल मामूली होगा।
136. भागीदार प्रयोक्ता के लिए डाउनस्ट्रीम उत्पादों के कारोबार में विचाराधीन उत्पाद की लागत का हिस्सा नीचे दिया गया है। यह देखा गया है कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद के कुल कारोबार में विचाराधीन उत्पाद की लागत मामूली है। अतः इसका अर्थ है कि विचाराधीन उत्पाद डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत का एक नगण्य हिस्सा है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	खपत किए गए उत्पादों का कारोबार (रु./लाख)	खपत किए गए पीयूसी की लागत (रु./लाख)	हिस्सा
1	जेएसडब्ल्यू लि० – सलेम	***	***	0-5%
2	जेएसडब्ल्यू लि० – विजय नगर	***	***	0-5%
3	जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लि०	***	***	0-5%
4	जिंदल स्टेनलेस लि०	***	***	0-5%
5	सारलोहा एडवांस्ड मैटेरियल्स प्रा० लि०	***	***	5-10%
6	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कं. लि.	***	प्रदान नहीं किए गए	

प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत ईक्यूआर के अनुसार सूचना लाख रुपये में।

137. महानिदेशक ने इसके अलावा, डाउनस्ट्रीम की उत्पाद की कीमत पर प्रस्तावित उपायों की जांच की है। वर्तमान जांच एक द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच है और उपायों की प्रकृति को देखते हुए महानिदेशक ने 5 प्रतिशत तक उत्पाद की कीमत में वृद्धि पर विचार करते हुए डाउनस्ट्रीम उत्पाद के प्रभाव पर विचार किया है। यह देखा गया है कि अधिकांश मामले में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव 1 प्रतिशत से कम है। अतः डाउनस्ट्रीम उद्योग के आकार पर विचार करते हुए और डाउनस्ट्रीम उत्पाद की अंतिम लागत में विचाराधीन उत्पाद के हिस्से पर विचार करते हुए यह देखा गया है कि रक्षोपाय लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

138. यह देखा गया है कि भारत में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। देश में 10,000 एमटी की अनुमानित मांग के मुकाबले भारतीय उद्योग के पास लगभग 20,000 एमटी की क्षमता है। अतः रियायतें हटाने से देश में उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी।
139. कोरिया गणराज्य से उत्पाद के आयात में अन्य आयातों को बाहर कर दिया है और द्विपक्षीय उपायों को लगाने से विभिन्न स्रोतों से आयात समतुल्य हो जाएंगे और इस प्रकार अन्य देशों से आयात प्रोत्साहित होंगे। महानिदेशक यह भी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के अनेक उत्पादक हैं जिनके न केवल एक दूसरे से बल्कि भारत में समान वस्तु के आयात से भी प्रतिस्पर्धा करने की संभावना है। अतः घरेलू उत्पादकों और आयातों के बीच भारतीय बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

140. द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाने के संबंध में भारत – कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली 2017 के नियम 10 में निम्नानुसार उल्लेख हैं:

10. अंतिम जांच परिणाम –

- (1) महानिदेशक जांच की शुरुआत की तारीख से आठ महीने के भीतर या किसी बढाई गई अवधि जो जांच शुरुआत की तारीख से एक वर्ष से अधिक न हो के भीतर जैसा केंद्र सरकार अनुमति दे, यह निर्धारित करेंगे कि क्या, - (क) जांच के अधीन उद्गम वस्तु के बढे हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या उसका खतरा है; और (ख) व्यापार करार के अंतर्गत सीमा शुल्क में कटौती या समाप्ति के कारण उद्गम वस्तु के बढे हुए आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद हैं।
- (2) महानिदेशक ऐसे द्विपक्षीय रक्षोपाय के संबंध में अपनी सिफारिश भी देंगे जो गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने और समायोजन को सुकर मनाने के लिए पर्याप्त होगा।
- (3) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपाय की समयावधि के संबंध में अपनी सिफारिश भी करेंगे। वशर्ते कि जहां सिफारिश की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, वहां महानिदेशक आवेदन की अवधि के दौरान समायोजन को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त नियमित अंतरालों पर द्विपक्षीय रक्षोपाय के उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश भी कर सकते हैं।

141. उपर्युक्त की जांच के बाद महानिदेशक निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क. आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और कोरिया गणराज्य से आयातित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक आयातित उत्पाद के समान वस्तु की आपूर्ति करते हैं।
- ख. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि कोरियाई उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद भारतीय उद्योग की तुलना में शुद्धता या गुणवत्ता में बेहतर है।
- ग. आवेदन कुल उत्पादन में 40 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले उत्पादकों द्वारा दायर किया गया है। इसके अलावा, समर्थकों के पास भारतीय उत्पादन 20 प्रतिशत हिस्सा है।
- घ. आवेदक नियमावली के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
- ड. पर्याप्त लंबी अवधि पर विचार करने से यह सुनिश्चित हुआ है कि आयातों की रियायत पूर्व, रियायत के दौरान और रियायत अवधि के बाद तुलना की गई है।
- च. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से तथा भारतीय उत्पादन और कुल आयातों की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- छ. फेमो के आयात में शुल्क हटाये जाने के समय वृद्धि हुई है। आयातों में बिल्कुल हाल की अवधि और बिल्कुल हाल की अवधि के बाद पुनः वृद्धि हुई है।
- ज. फेमो के आयात में टैरिफ रियायतों के कारण वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि को उचित ठहराने के लिए हितबद्ध पक्षकारों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है।

- झ. कोरिया गणराज्य से उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है और नियमावली तथा कोरिया – भारत सीईपीए के अर्थ के भीतर आयातों में वृद्धि हुई है।
- ञ. भारतीय उद्योग के पास देश में समूची मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। तथापि, वह कम क्षमता उपयोग का प्रचालन कर रहा है।
- ट. आवेदक मांग में वृद्धि की तर्ज पर अपनी घरेलू बिक्रियों में वृद्धि करने में असमर्थ हैं।
- ठ. आयातों में वृद्धि हुई है और उसने आवेदकों का बाजार हिस्सा छीन लिया है।
- ड. आवेदकों ने बाजार हिस्से और बिक्रियों के रूप में मात्रात्मक मापदंडों में गिरावट देखी है। इसलिए उन्हें अपना उत्पादन घटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।
- ढ. अक्टूबर, 21 से मार्च, 22 की अवधि के दौरान संगत अवधि की तुलना में मांग में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, संपूर्ण बढ़ी हुई मांग को कोरियाई आयातों ने पूरा किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता मौजूद है।
- ण. आवेदकों की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- त. आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति का कोई अन्य कारण सिद्ध नहीं किया गया है।
- द. बढ़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं।
- ध. विचाराधीन उत्पाद डाउनस्ट्रीम उद्योग के प्रचालन का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है। अतः डाउनस्ट्रीम उद्योग पर द्विपक्षीय रक्षोपायों का बहुत मामूली प्रभाव पड़ेगा।
142. अतः भारत – कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के नियम 10 के अनुसार द्विपक्षीय रक्षोपाय की सिफारिश करना उचित माना जाता है। तदनुसार, महानिदेशक कोरिया गणराज्य के मूल की संबद्ध वस्तु के आयातों पर निम्नांकित में से कमतर के बराबर सीमा शुल्क की दर में वृद्धि करने की सिफारिश करते हैं:
- क. द्विपक्षीय रक्षोपाय के आवेदन की तारीख के अनुसार संबद्ध वस्तु पर सीमा शुल्क की परम मित्र राष्ट्र हेतु लागू दर या
- ख. भारत – कोरिया सीईपीए के प्रभावी होने की तारीख से तत्काल पहले के दिन के अनुसार संबद्ध वस्तु पर सीमा शुल्क की परम मित्र राष्ट्र हेतु लागू दर।
143. इस उपाय को इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे तालिका के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए लागू करने की सिफारिश की जाती है।

वर्ष	द्विपक्षीय रक्षोपाय
वर्ष 1	सीमा शुल्क की दर में परम मित्र राष्ट्र हेतु लागू सीमा शुल्क की दर के स्तर पर 100 प्रतिशत की दर से
वर्ष 2	सीमा शुल्क की दर में परम मित्र राष्ट्र हेतु लागू सीमा शुल्क की दर के स्तर पर 75 प्रतिशत की दर से

अनंत स्वरूप, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2023

FINAL FINDINGS**Case No. (SG) - 03/2022**

Subject: Bilateral safeguard investigation concerning imports of Ferro Molybdenum from the Republic of Korea under India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. **F. No.22/03/2022-DGTR.**—Having regard to the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 and Article 2.22 of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CEPA) between the Government of India and the Government of the Republic of Korea, The Indian Ferro Alloy Producers' Association, Premier Alloys & Chemicals Private Limited, Boon Metal & Alloy Corporation and Team Ferro Alloys Private Limited filed an application before the Director General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the "Director General" or "Authority") in accordance with CEPA and Bilateral Safeguard Rules for initiation of a bilateral safeguard investigation and recommendation for suspension of tariff concessions concerning increased imports of Ferro Molybdenum (hereinafter referred to as the "the product under consideration" or "PUC" or "subject goods") from the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Korea RP" or "subject country").
2. Based on *prima facie* evidence, the Director General initiated the investigation under Rule 4 to examine whether imports of Ferro Molybdenum constitute "increased imports", whether the same has caused injury to the domestic industry, and whether bilateral safeguard measures are required to be invoked (and if so, duration thereof). The notification initiating the investigation was issued vide Notification No. 03/2022 dated 30th September 2022 published in the Gazette of India.
3. The Director General has since completed the investigation and is recording the present findings for consideration by the Central Government.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation-
 - a. The Director General issued a public notice of initiation of investigation and the same was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 30th September 2022.
 - b. The Director General sent a copy of the initiation notification dated 30th September 2022, to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, the Government of the Republic of Korea through the embassy of the Republic of Korea in India, the known producers and exporters in the subject country and known importers & consumers in India, and interested parties as mentioned in the application, in accordance with Rule 5(2) of the said Rules.
 - c. Copy of the non-confidential version of the application filed by the applicants was sent to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, the Government of the Republic of Korea through the embassy of the Republic of Korea in India and the known producers and exporters in the subject country in accordance with Rule 5(3) of the Rules. A copy of the application was made available to interested parties, on request.
 - d. The Director General forwarded a copy of the public notice initiating bilateral safeguard investigation to the following known producers/ exporters in Korea RP and provided them with an opportunity to provide relevant information by filing response to the questionnaire in the form and manner prescribed and making their views known in writing within thirty days in accordance with the Rules 5(4) of the Rules:
 - i. SeAH M&S
 - ii. Korvan Co. Limited
 - iii. Enertec Co. Limited

- iv. Hwasung Metal Co. Limited
- e. In response to the questionnaire issued, SeAH M&S has filed the exporter's questionnaire response. The same has been considered for the purpose of the present final findings, to the extent considered relevant and necessary.
- f. The Director General sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in the form and manner prescribed and make their views known in writing within thirty days in accordance with Rule 5(5) of the Rules:
 - i. Advent Foundry & Allied Supplies Private Limited
 - ii. Asia Metals And Ferro Alloys
 - iii. Avtar Steel Limited
 - iv. Calcutta Metal Depot Private Limited
 - v. Chandan Steel Limited
 - vi. D.S Alloys Private Limited
 - vii. Dalini Metals and Alloys Private Limited
 - viii. ISMT Limited
 - ix. J Poonamchand and Sons Private Limited
 - x. JSW Steel Limited
 - xi. Kalyani Steels Limited
 - xii. Kothari Metals Limited
 - xiii. KR Metals LLP
 - xiv. Laxcon Steels Limited
 - xv. M M Ceramics and Ferro Alloys
 - xvi. Metal Alloys (India)
 - xvii. Metallic Ferro Alloys LLP
 - xviii. Namoh Alloys Private Limited
 - xix. Oswal Minerals Limited
 - xx. Phoolchand Bhagat Singh LLP
 - xxi. Rajputana Stainless Limited
 - xxii. RSM Super Metals LLP
 - xxiii. Saarloha Advanced Materials Private Limited
 - xxiv. Sanjay Commercial Company
 - xxv. Singhania International Limited
 - xxvi. SRC Chemicals Private Limited
 - xxvii. Sunflag Iron and Steel Company Limited
 - xxviii. Synergy Steels Limited
 - xxix. Tata Steel Limited
 - xxx. Team Remedies LLP
 - xxxi. Viraj Profiles Limited
- g. In response to the questionnaire issued, the following importers/consumers have filed questionnaire responses:
 - i. Jindal Stainless Limited ('JSL')

- ii. Jindal Stainless (Hisar) Limited ('JSHL')
 - iii. Saarloha Advanced Materials Private Limited
 - iv. JSW Steel Limited
 - v. Sunflag Iron and Steel Co.
- h. The Director General sent a questionnaire to the other known Indian producers of the product under consideration calling for necessary information in the form and manner prescribed and seeking their views in writing within thirty days. No other Indian producer has provided response to the questionnaire sent by the Director General. The applicants have filed their questionnaire response.
- i. The following parties have filed submissions during the course of the investigation. The same has been considered for the purpose of the present final findings, to the extent considered relevant and necessary: -
- i. Government of the Republic of Korea
 - ii. Seah M&S
 - iii. Alloy Steel Producers Association of India ('ASPA')
 - iv. Jindal Stainless Limited
 - v. Jindal Stainless (Hisar) Limited
 - vi. JSW Steel Limited
 - vii. Saarloha Advanced Materials Private Limited
 - viii. Sunflag Iron and Steel Company Limited
- j. The Director General has considered 1st October 2021 – 31st March 2022 as the most recent period and 1st April 2018 – 31st March 2022 as the period of investigation.
- k. An oral hearing was held on 4th January 2023, in terms of Rule 5(6) of the Rules, where an opportunity was provided to all interested parties and the applicants to present their views. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- l. A list of interested parties was published on the DGTR website. The interested parties were advised to exchange the non-confidential version of their submissions with each other through email.
- m. Request was made to DGCI&S to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods. The Director General has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- n. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Director General in this final findings.
- o. The Director General, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the applicants and the interested parties, which forms the basis of these final findings, to the extent possible and considered relevant & necessary.
- p. Wherever an interested party or the applicants have refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Director General has considered such party as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the facts available.
- q. "****" in the non-confidential version of the present findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Director General under the Rules.
- r. The Director General has used the following abbreviations in this final finding: -

SN	Abbreviation	Full description
1	FeMo	Ferro Molybdenum
2	Moly	Moly oxide
3	Applicants	Boon Metal & Alloy Corporation, Premier Alloys & Chemicals Private

		Limited and Team Ferro Alloys Private Limited
4	Applicant association	The Indian Ferro Alloy Producers' Association
5	Interested parties	All interested parties except the applicant and applicant association.
6	Indian industry	Applicants, supporters and other producers of FeMo
7	POI	Period of investigation – April 2018 to March 2022
8	Most recent period	October 2021 to March 2022
9	Rules	India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017
10	CEPA	Comprehensive Economic Cooperation Agreement between the Government of India and the Government of Korea
11	DGCI&S	Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics

C. SOURCE OF INFORMATION

- The period considered for the purposes of the present investigation, as notified in the notice of initiation is from 1st April 2018 to 31st March 2022 with the period 1st October 2021 to 31st March 2022 considered as the most recent period. Further, since the interested parties have raised concerns on whether imports have increased because of concessions, the Director General has also considered the import data from the period 2008-09 which is the period before the commencement of tariff concessions.
- Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide details of imports of the subject goods. The Director General has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume and value of imports for the period April 2008 to December 2022. It is seen that the product is transacted in different purities of Molybdenum. Therefore, the volume of imports has been determined on the basis of one equivalent Molybdenum content as examined below.
- The rate of custom duty on the imports of FeMo after considering the concessions under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is as follows. It is seen that the MFN rate on the product was lower than the tariff rate considered in the CEPA till the period 2012. The effect of tariff concession however started from 2014. The product is having a full tariff concession since 2017. For the purpose of the present findings, the period between 2009-10 and 2013-14 has been considered as “pre concession period”, the period between 2013-14 to 2015-16 as the “during the concession period” and the period from 2017-18 as the “post concession period”. The MFN duty and the rate of duty as per the Agreement and the relevant customs notification are as below.

SN	Year	MFN Rates	Korea RP	Custom notification no.
1	2009	5%	8.75%	152/2009 – Customs
2	2010	5%	7.50%	137/2010 – Customs
3	2011	5%	6.25%	123/2011 – Customs
4	2012	5%	5%	66/2012 – Customs
5	2013	5%	3.75%	54/2013 – Customs
6	2014	5%	2.50%	35/2014 – Customs
7	2015	5%	1.25%	60/2015 – Customs
8	2016	5%	0%	66/2016 – Customs

D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

D.1 Submissions made by the interested parties

8. The submissions made by the interested parties in respect of the product under consideration are as follows-
 - a. Indian industry is unable to maintain a uniform molybdenum content and provide a stable supply and after sale service in the market.
 - b. Indian industry is unable to meet the technical and metallurgical requirements of the user industry.
 - c. Product imported from Korea RP has higher ratio of roasted molybdenum which the Indian producers are not able to produce.
 - d. There is a difference in product manufactured by Indian industry and the imported product from the subject country because of different manufacturing process.
 - e. The product supplied by the domestic producers has high share of silicon, phosphorus or nitrogen content. For steel manufacturers, these should be lower.
 - f. Korean exporters are recognized for their high quality, reliability and consistency of supply with respect to the requisite molybdenum content of the product under consideration.
 - g. Various users in the present investigation have confirmed that Indian users have a preference for Korean products due to their high quality.

D.2 Submissions made by the applicants.

9. The submissions made by the applicants in respect of the product under consideration are as follows -
 - a. FeMo is an alloy which is formed by combining iron and Moly. It is a hardening agent and is found in many alloy steels that are heat treatable.
 - b. FeMo comes in many grades, although predominantly it is produced in just two grades (which are defined in terms of purities), where the content of pure Moly is between 60% and 75%.
 - c. Largest applications of FeMo are in ferrous alloys. Depending on the Moly content range, it is suited for machine tools and equipment, military hardware, refinery tubing, load-bearing parts and rotary drills.
 - d. The steel industry is the largest user of FeMo accounting for approximately 80% of FeMo mined in the world.
 - e. The Indian industry has supplied all the grades imported from Korea and there is no merit in the contention that technical and metallurgical requirements of the user industry are not met by Indian producers.
 - f. The domestic industry has provided Moly content as required by the user industry. Biggest consumer in India, Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited are procuring their entire requirement from India and it shows that there is no issue with respect to quality supplied.
 - g. The product produced by the Indian industry is a like article to the imported product.

D.3 Examination by the Director General

10. The product under consideration in the present investigation is “Ferro Molybdenum” also described as FeMO in this notification, falling under the HS code 72027000 of the Customs Tariff Act, 1975.
11. FeMo is an alloy which is formed by combining iron and Molybdenum. FeMo is a hardening agent and is found in many alloy steels that are heat treatable. FeMo prevents corrosion in stainless steel, and when mixed with iron, it also strengthens and hardens into austenite. FeMo comes in many grades, although predominantly it is produced in just two grades (which are defined in terms of purities), where the content of pure Moly is between 60% and 75%.
12. The largest applications of FeMo are its use in ferrous alloys, and depending on the molybdenum content range, it is suited for machine tools and equipment, military hardware, refinery tubing, load-bearing parts and rotary drills. FeMo is also used in cars, trucks, locomotives and ships. In addition, FeMo is used in stainless and heat-resisting steel that are employed by synthetic fuel and chemical plants, heat exchangers, power generators, oil-refining equipment, pumps, turbine tubing, ship propellers, plastics and inside acid storage containers, tool steels, with a high percentage range of FeMo, are used in high-speed machining parts, cold work tools, drill bits, screwdrivers, dies, chisels, heavy castings, ball and rolling mills, rolls, cylinder blocks, piston rings and large drill bits.

13. The interested parties have submitted that the Indian industry suffers because of its inability to maintain uniform molybdenum content, supply stability after sale service and silicon, phosphorus or nitrogen content. The Director General notes that no evidence has been provided by these interested parties in support of their contention. It is seen that the Indian industry was earlier having 89% share in demand in the past (in 2015-16) and imports from Korea were extremely limited. It, therefore, does not appear that the present increase in imports is due to the inability of the domestic industry to supply the subject goods as per the requirement of the downstream industry. Even in the present injury period, the market share of the Indian industry was 79% in 2019-20. It is also seen that one of the biggest consumers of the product in India, Jindal Stainless has sourced its complete requirements from the domestic market and has not resorted to imports. The Director General considered that it is not established that the surge in imports was due to the Indian industry's inability to provide the material required by the consumers.
14. It has been contended that the Korean producers supply product with more than 60% Moly content and the Indian industry cannot supply the same. No evidence has been provided by the interested parties to support their contention. The applicants have submitted evidence that they have produced and sold FeMo with both above and below 60% Moly content. Therefore, the contention of the interested parties cannot be accepted.
15. Like article has not been defined in the Bilateral Safeguard Rules. However, Rule 2 (2) of the Bilateral Safeguard Rules provides as follows:

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.
16. Therefore, the Director General has relied on the definition of the like article as per the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duties) Rules which defines the like article as follows: -

(e) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation;
17. On the basis of the information and evidence on record, the Director General holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and imported from Republic of Korea. The goods supplied by the domestic industry are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The goods produced by the domestic industry are also technically and commercially comparable to the product being imported from Republic of Korea. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Director General holds that the product manufactured by the applicants constitutes the like article to the subject goods.

E. THE DOMESTIC INDUSTRY

E.1 Submissions made by the interested parties

18. The submissions made by the interested parties in respect of the scope of the domestic industry are as follows –
 - a. There is a mismatch between the production data filed by the association and relied on by the applicants in the application.
 - b. The applicants should be asked to provide capacity of each domestic producer in India.
 - c. The reason for non-participation of other producers should be examined.
 - d. There are a total of 15 producers of the product under consideration out of which only 3 participated in the investigation.
 - e. The three applicant producers constitute 39-42% of the total production which is less than a major proportion.
 - f. A list of all the producers in India has not been given by the applicants.
 - g. Additional participation by 1 or 2 more producers would have made it a clear major proportion of more than 50% Indian production.
 - h. Reason of non-participation of the remaining 12 domestic producers should be examined.
 - i. Difference between capacity of the applicant domestic producers with that of other domestic producers show they are not representative of the domestic industry.

- j. Capacity of each domestic producer in India or estimates should be provided for the respondent to further comment on standing.
- k. Despite the support letters filed, performance of remaining 40% of the Indian production remains unaccounted for.
- l. WTO in case of US – Hot-Rolled Steel held that investigating authorities should either undertake examination of the industry as a whole or provide a satisfactory explanation as to why it is not necessary to examine the other parts of the domestic industry.
- m. Rule 4 does not provide for support by the Indian industry. The share of supporters in total domestic production should not be included while determining the standing of the domestic industry.
- n. Out of five producers who supported the application, only two are members of the association.

E.2 Submissions made by the applicants.

19. The submissions made by the applicants in respect of the scope of the domestic industry are as follows –
 - a. The application has been filed by The Indian Ferro Alloy Producers' Association which is the apex association for the product under consideration. Around 10 producers of the product are members of the association.
 - b. The applicants have ascertained the total production based on the estimates of the association from the data collected from its members.
 - c. Share of Premier Alloys & Chemicals Private Limited, Boon Metal & Alloy Corporation and Team Ferro Alloys Private Limited is 42% of the total Indian production.
 - d. The application is supported by Lalwani Ferro Alloys Private Limited, Nortech Ferro Alloys Private Limited, Essel Mining & Industries Limited, Amar traders Limited and Rama Ferro Alloys & Finance Private Limited.
 - e. The supporters and the applicants constitute a 60% in the Indian demand.
 - f. Rule 2(f) of the Rules defines "serious injury" as 'a significant overall impairment in the position of a domestic industry'. What is essential for the purpose of the present investigation is an examination of the economic position of the domestic industry. There is no legal requirement to examine the performance of the other Indian producers.
 - g. Annual Report of other domestic producers cannot be relied on to assess their performance with respect to the like article since they are all multi-product companies.
 - h. As regards the requirement of major proportion, reference is drawn to the Panel Report in case of India – Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products wherein it was held that besides quantitative elements, the quality of information provided by the industry is also required to be seen.
 - i. It has not been shown by the interested parties how the data provided by the domestic industry shows a different situation of the Indian industry than the one claimed by the applicants.

E.3 Examination by the Director General

20. Rule 2(b) of Bilateral Safeguard Measures Rules, 2017 states as follows:

"the domestic industry" means the producers -

(i) as a whole of the like or directly competitive goods operating in the territory of India; or

(ii) whose collective output of the like or directly competitive goods constitutes a major proportion of the total domestic production of those goods;
21. The application for initiation of the investigation was filed by The Indian Ferro Alloy Producers' Association along with the following producers: -
 - a. Boon Metal & Alloy Corporation.
 - b. Premier Alloys & Chemicals Private Limited.
 - c. Team Ferro Alloys Private Limited.
22. Pursuant to the initiation of the investigation, the following other producers have supported the application. Further, these producers have provided information relating to their capacity, production and sales: -

- a. Amar Traders Limited.
 - b. Essel Mining & Industries Limited.
 - c. Lalwani Ferro Alloys Private Limited.
 - d. Nortech Ferro Alloys Private Limited.
 - e. Rama Ferro Alloys & Finance Private Limited.
23. The applicants submitted that considering the nature of the industry, there is no published information regarding the gross domestic production of the subject goods in India. None of the interested parties has submitted any evidence to dispute the claim of the domestic industry regarding the gross domestic production. It has been submitted by the other interested parties that the information provided by the association is different from the information considered in the standing table. The association has clarified that it does not maintain any production or sale record of its members and had given this information purely based on estimates and based on the experience of the key functionaries in the association. The association has estimated that the production of these producers is around 6000 MT. In order to examine if the applicants meet the requirement of standing, the Director General has considered the Indian production provided by the applicants as well as the association.
24. It is seen that 3 producers filed the application and 5 producers have provided data as supporters to the application.
25. It has been stated by the interested parties that only 3 producers out of 15 producers cannot be representative of the Indian industry. The Director General has examined the support letter filed by the other producers and it is seen that the capacities with the Indian producers range from as low as 250 MT to as high as 2000 MT. It is seen that the applicant companies are the largest producers in India. While the collective production of 3 applicants constitutes 40% of the Indian production, the collective production of 5 supporting producers constitutes 20%, while the collective production of the remaining non-participating producers constitutes 40%. Six other producers have also filed support letter with the Director General. However, the support letters were received post filing of rejoinder submissions and at a very belated stage. These support letters have not been considered for this determination. It is also noted that the domestic producers in the present product are MSME companies.
26. The production estimated by the applicants has been considered for the purpose of ascertaining total Indian production. Director General has considered production reported by individual companies. Production of those domestic producers who are not before the Director General has been considered based on production assessed by the association. The company-wise production is as below: -

SN	Particulars	2018-19	2019-20	2020-21	Apr to Sep 21	Oct 21 to Mar 22
A	Applicants	2,572	2,183	2,376	1,397	1,107
1	Team Ferro Alloys Private Limited	***	***	***	***	***
2	Premier Alloys & Chemicals Private Limited.	***	***	***	***	***
3	Boon Metal & Alloy Corporation.	***	***	***	***	***
B	Supporters	1898	1266	1180	682	572
4	Lalwani Ferro Alloys Private Limited.	***	***	***	***	***
5	Nortech Ferro Alloys Private Limited.	***	***	***	***	***
6	Essel Mining & Industries Limited.	***	***	***	***	***
7	Amar Traders Limited.	***	***	***	***	***
8	Rama Ferro Alloys & Finance	***	***	***	***	***

	Private Limited					
C	Other producers	1,719	2,344	2,383	1,112	1,119
D	Indian production	6,189	5,793	5,939	3,191	2,798
E	Share of applicants	42%	38%	40%	44%	40%
F	Share of supporters	31%	22%	20%	21%	20%

27. The share of the applicants in the Indian production in the period 2021-22 is 40%, whereas that of the supporters is 20%.

28. Several WTO decisions have been brought forward by the applicants and interested parties wherein the meaning of “major proportion” has been examined in anti-dumping measures. Article 4 of the Anti-dumping agreement provides as follows:

4.1 For the purposes of this Agreement, the term "the domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that.....:

29. The Director General notes that both the anti-dumping agreement and the bilateral safeguard rules define the domestic industry through the word “a major proportion”. Further, there are no WTO decisions which deal with the meaning of “major proportion” for fragmented industries in case of safeguard investigations. Therefore, the Director General has drawn reference to the WTO decisions in the case of anti-dumping measures to examine how the issue of “major proportion” has been dealt with by WTO.

30. WTO in the case of Argentina – Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil held as follows: -

7.341 In considering these different dictionary definitions, we note that the word “major” is also defined as “important, serious, or significant”. Accordingly, an interpretation that defines the domestic industry in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion of total domestic production is permissible. Indeed, this approach is entirely consistent with the Spanish version of Article 4.1, which refers to producers representing “una proporción importante” of domestic production. Furthermore, Article 4.1 does not define the “the domestic industry” in terms of producers of the major proportion of total domestic production. Instead, Article 4.1 refers to producers of a major proportion of total domestic production. If Article 4.1 had referred to the major proportion, the requirement would clearly have been to define the “the domestic industry” as producers constituting 50+ per cent of total domestic production. However, the reference to a major proportion suggests that there may be more than one “major proportion” for the purpose of defining “the domestic industry”. In the event of multiple “major proportions”, it is inconceivable that each individual “major proportion” could – or must – exceed 50 per cent. This therefore supports our finding that it is permissible to define the “the domestic industry” in terms of domestic producers of an important, serious or significant proportion of total domestic production. For these reasons, we find that Article 4.1 of the AD Agreement does not require Members to define the “the domestic industry” in terms of domestic producers representing the majority, or 50+ per cent, of total domestic production.

7.342 There is nothing on the record to suggest that, in the circumstances of this case, 46 per cent of total domestic production is not an important, serious or significant proportion of total domestic production. Accordingly, we reject Brazil's claim that Argentina violated Article 4.1 of the AD Agreement by defining “the domestic industry” in terms of domestic producers representing 46 per cent of total domestic production.

31. WTO in the case of European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China held as follows: -

415. We recognize that obtaining information regarding domestic producers may be difficult, particularly in special market situations, such as a fragmented industry with numerous producers. In such special cases, the use of “a major proportion” within the meaning of Article 4.1 provides an investigating authority with some flexibility to define the domestic industry in the light of what is reasonable and practically possible. The practical constraint on an authority's ability to obtain information regarding the domestic producers may also mean that, in such special cases, what

constitutes "a major proportion of the total domestic production" may be lower than what is ordinarily permissible in a less fragmented market.

417. Finally, we turn to examine the interpretation advanced by the European Union that Article 5.4 of the Anti-Dumping Agreement provides important contextual guidance concerning the interpretation of the term "a major proportion" in Article 4.1 of that Agreement. Article 5.4, which contains the standing requirement for the initiation of an investigation, provides certain numerical benchmarks for evaluating whether a complaint to initiate an anti-dumping investigation has sufficient support by domestic producers. Specifically, Article 5.4 states that an investigation "shall not be initiated" unless the application "has been made by or on behalf of the domestic industry". It then provides that "[t]he application shall be considered to have been made 'by or on behalf of the domestic industry' if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support or opposition to the application." Furthermore, "no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry."

32. WTO decision in the case of India – Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products held as follows: -

7.167. We note the cautionary words of the Appellate Body that, when the domestic industry is defined as the **domestic producers whose output constitutes a major proportion of total domestic production, if the proportion is not sufficiently high, then a qualitative element becomes crucial in establishing whether the domestic industry has been appropriately defined.** This situation may arise, for example, in the case of a fragmented industry with numerous producers, when there are practical constraints on an Director General 's ability to obtain information and therefore a "major proportion" may be lower than what would be ordinarily permissible in a less fragmented industry. This is not the situation in the present case. As noted above, the Indian competent Authority included in the definition of the domestic industry a proportion of the domestic producers' output that was high enough that it can constitute a substantial reflection of the total domestic production. Accordingly, the definition of the domestic industry would very likely satisfy both the quantitative and the qualitative elements of the definition in Article 4.1(c) of the Agreement on Safeguards. Japan has failed to demonstrate that, despite such high proportion, the domestic production as defined by the Indian competent Authority was not representative of the total domestic production in India.

33. The Director General also notes that whereas the anti-dumping rules lay down a minimum requirement of 25%, no such requirement has been laid down in the case of bilateral safeguard rules. Based on the WTO decisions and the Rules, a 25% share in total Indian production can be considered a "major proportion" in the case of a fragmented industry. However, the WTO decision additionally purposes a requirement on the Director General to ensure that the data provided by the participating producers does not reflect a distorted picture. Therefore, the performance of the applicants has been compared with the performance of the supporters and other producers.

SN	Particulars	2018-19	2019-20	2020-21	Apr to Sep 21	Oct to Mar 22
1	Capacity					
	Applicants	6,216	6,216	6,216	3,108	3,108
	Supporters	3514	3514	3514	1757	1757
2	Production					
	Applicants	2,572	2,183	2,376	1,397	1,107
	Supporters	1,898	1,266	1,180	682	572
3	Capacity utilisation					
	Applicants	41%	35%	38%	45%	35%
	Supporters	54%	36%	34%	39%	33%
4	Sales					

Applicants	2,516	2,304	2,354	1,404	1,255
Supporters	1,917	1,281	1,154	692	569

34. It has been contended that as per the annual reports of the other producers, their performance show improvement. The Director General notes that it has examined the annual reports of the other producers, and it is seen that they are multi-product companies and the annual reports reflect the performance of the company as a whole and the figures are not specific to the product under consideration and therefore, the contention cannot be relied upon.
35. Rule 2(b) of the rules defines the domestic industry as domestic producers as a whole or those domestic producers whose collective output constitutes a major proportion of the gross domestic production. The rules have not prescribed any mathematical figure with regard to the term major proportion. The Director General has therefore considered that any share in Indian production that is significant should be considered a major proportion. The production of participating applicant companies accounts for 40% of the Indian production. Further, the production of the supporting producers accounts for 20% of production in India. The applicant companies and the supporters together account for 60% of the production in India.
36. Having regard to the Rules, facts of the case and evidence on record, the Director General holds that the application satisfies the requirements of standing under the Rules and that the applicant companies constitute the domestic industry.

F. MISCELLANEOUS

F.1 Submissions made by the interested parties

37. Miscellaneous submissions made by the interested parties are as follows-
- The applicants have claimed the entire adjustment plan as confidential.
 - Despite being a mandatory requirement, the adjustment plan was absent in the application filed.
 - Though the adjustment plan focusses on reduction of cost, there is limited scope for cost reduction due to low value addition in the product. The adjustment plan is unrealistic.
 - The import data as per the application does not reconcile with Ministry of Commerce database.
 - The applicants have not provided a complete list of the producers in India.
 - Basic requirements of the CEPA have not been met as the applicants failed to demonstrate link between reduction of duty and increase in imports.
 - The initiation notification does not even mention *prima facie* view on reduction of duties causing increased imports and such increase causing serious injury to the domestic industry.
 - The duties were eliminated in 2017 and the applicants has been filed at such a belated stage.
 - There is no legal or factual justification to choose a particular six-month period from the period of investigation.
 - Safeguard measure is not warranted for 2 years due to insignificant nature of injury and unrealistic adjustment plan.
 - The applicants have simply presented import volumes and prices without any consideration of the content of molybdenum therein.
 - The information provided by the applicants does not take into account the possibility of increased imports due to change of import mix with the larger sales volume of products with low molybdenum content being imported now.
 - Bilateral safeguard measures are extraordinary in nature and cannot be utilized as a shield of the industry.
 - The contention of the applicants that the export price to India is lower as compared to export price to the rest of the world is incorrect as exports to India are of around 59-61% Moly content whereas the exports to other countries are of 65-67% Moly content.
 - If the applicants are aggrieved by the pricing of Korean exports between India and other countries, bilateral safeguard measure is not the appropriate remedy to address issues relating to pricing.

- p. The applicants have requested that the import price and volume may be considered after due adjustments for Moly content. The applicants have not made any such adjustments in the application and has raised this issue at a belated stage.
- q. Hanwha Solutions Corporation referenced by the applicants as a producer of the subject goods is not a producer.
- r. Proposed adjustment plan of the applicants is impractical and lacks short-term plan for a 2-year period or less that is needed to make the domestic industry competitive.
- s. Formula based pricing of end product and formula-based purchase of raw material may be possible over a long-term period.
- t. The applicants have submitted that they will install new machineries and crushers to increase efficiencies, but they could have taken these steps in the last 10 years when the imports from Korea RP increased gradually.
- u. The applicants have not provided any evidence in support of their submission on exports from Korea RP.
- v. Request for safeguard measure for four years is unprecedented because they can be imposed for a period of 2 years only.

F.2 Submissions made by the applicants.

38. Miscellaneous submissions made by the applicants are as follows-

- a. The adjustment plan of the domestic industry is a highly confidential document as it charts down the business strategy that would be followed by the industry to make them competitive against the subject imports.
- b. Basic raw material required for production of the product under consideration is Moly Oxide (also known as roasted molybdenum ore & concentrate) which is a relatively scarce resource. India and Republic of Korea do not have any resources of molybdenum and are wholly dependent on imports of roasted molybdenum ore & concentrate.
- c. Import of raw material attract basic customs duty of 2.5%. Current raw material price is more than Rs 2000 per KG and the incidence of customs duty of 2.5% comes to more than Rs 50,000 per tonne.
- d. Concessional customs duty applies in case of raw material imports from Chile and Thailand. Indian Industry is importing around 62% of its requirement from Chile and Thailand, whereas 38% requirement is still being met by the rest of the world. However, since Chile and Thailand are not the world's largest producers and suppliers of this product, and the producers therein have limited volumes, the Indian industry is not able to reap the benefit of customs duty concessions available to them in respect of Chile and Thailand.
- e. Korean Government has granted full duty concessions to the raw materials. This is not a natural advantage available to the Korean producers, but an artificial unfair disadvantage being faced by the Indian industry, leading to surge in Korean imports.
- f. The product under consideration is a high-priced product (selling in the range of Rs. 15 lakhs to Rs 20 lakhs per MT). The value addition from the raw material to the product under consideration is reasonable enough in absolute terms though low in percentage terms. The present customs duty difference between the Korean and Indian producers has created unfair advantage in favour of Korean producers and has led to surge in imports causing injury to the Indian industry.
- g. There are only two known producers of product in Korea, holding capacities far in excess to combined capacities of Indian industry. Capacity with SeAH M&S is 20,000 MT per annum which is more than that the total capacity of the Indian industry. Further, despite existing surplus capacities, as stated by the Korean Government, the Korean producers have further enhanced capacities. It is evident that these capacity enhancements have been done considering the Indian and global market opportunity, and at the cost of Indian industry. The Indian industry, which is already MSME, would become extinct.
- h. Import description shows gross and net weight of FeMo and Moly content. While certain transactions have been reported with the gross weight, other transactions have been reported with net weight of FeMo. Thus, importers have resorted to inconsistent way of reporting the import volumes. The DGCI&S has however consolidated the volume as reported by the importers. Such being the case, it was imperative to bring entire import volumes to one consistent level. Therefore, wherever gross weights have been

reported, the applicants have considered the same. However, where net weight has been reported, applicants have converted it into gross weight, using Moly content mentioned in the import description.

- i. The contention of the interested parties that the initiation notification does not mention the *prima facie* view of the Director General on increased imports and injury is incorrect as the paras 5,6 and 7 clearly mention the *prima facie* view.

F.3 Examination by the Director General

39. The present investigation was initiated by the Director General based on the data and information provided by the applicants, after reaching a *prima facie* satisfaction that there was sufficient evidence of increased imports causing serious injury to the domestic industry. Further, subsequent to the initiation, information has been sought from all the parties to the extent deemed necessary.

40. Rule 6 of the Rules deals with the confidentiality of information. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Director General has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide the sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Director General made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties to all interested parties.

41. It has been contended that the duties were eliminated in 2017 and the application has been filed at a very belated stage. Article 2.21 of CEPA provides as follows: -

*“..... Transition period means a period for a good from the date of entry into force of this Agreement until **ten years** from the **date of completion of tariff elimination** or completion of tariff reduction, as the case may be for each good....”*

42. Further, Article 2.22 of CEPA provides as follows.

“During the transition period only, if as a result of the reduction or elimination of a customs duty under this Agreement, an originating good of the other Party is being imported into the territory of a Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions that the imports of such good from the other Party alone constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to the domestic industry producing a like or directly competitive good, the Party may:

3 The passage of a period of time between the commencement or termination of such reduction or elimination and the increase in imports shall not by itself preclude the determination referred to in this footnote. If the increase in imports is demonstrably unrelated to such reduction or elimination, the determination referred to in this footnote shall not be made.”

43. It is thus seen that the mere gap of time between the present surge in imports and the grant of concession per se cannot prevent an applicant from seeking redressal under the Rules and CEPA. The very purpose of providing transition period is defeated if it considers that the action can be invoked only in respect of surge in imports occurring immediately after grant of concession. Further, the CEPA specifically recognises that passage of time shall not prevent an applicant from seeking remedy against surge in imports. It is also seen that the imports of the product in fact started surging as soon as concession started, and the custom duty was completely eliminated. Further, while the first increase in imports occurred during the period 2017-18, the imports further increased in 2020-21 and thereafter in most recent period. The imports increased significantly after the most recent period. It is therefore considered that the application has been filed in conformity with the provisions of CEPA and the Indian rules.

44. The interested parties have contended that there is no justification to choose a particular six-month period from the period of investigation to examine the imports and injury. The Director General notes that only the six-month period of Oct-21 to Mar 22 has not been considered for arriving at the final conclusion. The volume of imports has also been considered since the pre concession period, during concession, post concession and the most recent period to examine the trend of imports. Further, even the examination of the economic parameters has been conducted for four years since 2018-19.

45. As regards the submissions relating to difference in the import data between the data reported in the application and DGCI&S published data, the applicants had in its written submission stated that the weight reported as per DGCI&S published data cannot be relied upon, as certain import data shows gross weight of FeMo whereas other transactions report net weight. No interested party has provided any comments on the methodology

provided by the applicants. Further, since any other interested party has not provided any methodology in this regard, the Director General has examined the transaction wise data procured and has arrived at the present determination based on the same. Analysis of the import data indeed shows different approach adopted by different importers in reporting the import volumes.

46. Some illustrative examples of imports from Korea for the month of September 2021 are given below which show how the volumes have not been reported at gross level. The Director General has considered the revised volume for the present investigation.

BE No	Description	Quantity Reported in MT	Value Reported	Price as per reported volume	Quantity considered in MT	Price as per revised volume
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***

47. It is thus seen that it is the importers who have used inconsistent methodology for reporting the import volumes. While some transactions report the gross weight of the Molybdenum content, others report the net weight of Moly content. The domestic industry had converted various transactions into equivalent Molybdenum weight in order to ensure uniformity. The Director General has adopted the following methodology for the purpose of ascertainment of the volume of imports: -

- Wherever gross weight has been reported, the same has been considered as it is and adopted as the weight of material imported.
- Where the net weight has been reported as the import volume, the Director General has converted it into gross weight, by dividing the volume by the Molybdenum percentage. The same has been treated as the gross weight of the material imported.

48. As regards the contention that the comparison between exports price to India and the rest of the world is incorrect, the Director General notes that no evidence has been brought forward by the interested parties in support of the argument that the exports to India and the rest of the world are of different Moly content. However, since the present investigation is a safeguard investigation, the comparison between the export prices to India and the rest of the world is not relevant for the final determination.

G. INCREASED IMPORTS FROM KOREA RP

G.1 Submissions made by the interested parties

49. The submissions made by the interested parties in respect of the increased imports are as follows: -
- Basic requirements of the CEPA have not been met as the applicants have failed to demonstrate link between reduction of duty and increase in imports.
 - There is no sudden and recent surge in Korean imports. WTO had in case of Argentina Footwear and US – Steel Safeguards held that the increase in imports must be recent, sudden, sharp and significant.
 - It is not sufficient to compare level of imports at the beginning and at the end of the investigation period. More weightages should be given to the most recent period.
 - There is no causal link between tariff reduction and increase in imports.
 - Recent increase in imports is not due to reduction in customs duties from 2010 to 2017.
 - Import data in a single quarter cannot be relied on for increase in imports as held in the WTO Panel Report in India – Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products.
 - The increase in imports in Q3 of 2021-22 was due to deferred imports due to covid. There is no increase in imports in 2021-22 compared to 2020-21.
 - Q4 of 2021-22 shows a decline in imports in absolute terms and relative to domestic production. Increase in import in one quarter (Q3 of 2021-22) is insufficient.

- i. Director General should examine existence of link between surge in imports and reduction/ elimination of tariffs. There is no correlation between the reduction in tariffs and import volumes.
- j. Director General should exclude the imports made by the applicants while evaluating imports. The petition does not disclose whether any such imports were made.
- k. Fluctuation in import volumes makes it clear that increase in imports is neither “sudden” nor “recent”. Imports have fallen in the last quarter and increase in a single quarter is insufficient.
- l. Appellate Body in the Argentina – Footwear held that an increase in imports does not automatically show that the product is being imported in such increased quantities to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.
- m. The applicants’ claim of surge in imports in Q3 and Q4 of 2021-22 is not supported by latest quarterly data. Imports have infact decline in quarter 4.
- n. The increase in imports in Q3 of 2021-22 was due to deferred imports due to covid. There is no increase in imports in 2021-22 compared to 2020-21.
- o. Despite the reduction of duties every year starting from 2010, the import volumes did not increase from 2010 to 2017.
- p. The increased imports are because of the increasing demand of steel in India and not due to any tariff concession.
- q. The steel plants in India were either non-operational or partially operating in quarter 1 of 2021-22. The imports of FeMo were deferred during this quarter and there was an increase in imports in the quarter 3 of 2021-22.
- r. Import tariff became 0% in 2016-17 but there was no corresponding increase in import volumes from the Republic of Korea.
- s. Import volumes have remained consistently below the domestic sales which shows that the increase in imports is not sudden, sharp and significant.
- t. No evidence has been provided by the applicants in support of their claim of increased imports in the post period of investigation.
- u. Share of exports from the Republic of Korea RP to India and the rest of the world is inconsequential for the purpose of present finding.
- v. Increase in imports over a period of eleven years should be considered as normal and gradual increase. Demand of the subject goods has increased during this period because the production of alloy steel in India has increased.
- w. “Increased imports” do not mean ‘any increase in imports,’ rather it should be the “recent past” based on the following report of the Appellate Body in Argentina – Footwear (EC).
- x. Despite Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited procuring entire requirement from the Indian industry, they are opposing measures. This shows that purchasing decisions of consumers are not impacted by tariff concessions.
- y. Concessions cannot be a cause of injury as during the period from 2010 to 2017 despite the continuous reduction in the custom duties, volume of imports has been constant.
- z. There is a non-linear movement in the import volumes which shows that showcases that the increase in imports is not on account of tariff concessions under the Korea-India CEPA but due to other non-price factors.
- aa. Imports have increased because of capacity expansion by steel producers.

G.2 Submissions made by the applicants.

50. The submissions made by the applicants in respect of increased imports are as follows-

- a. The Director General may examine increased imports before and after tariff concession in order to ascertain whether there is increased imports and whether such increased imports are due to tariff concessions.

- b. Imports were negligible in quantity when tariff concessions were first granted. As concessions increased, imports from the subject country increased.
- c. Imports first increased in 2017-18 when custom duties were reduced to nil and thereafter in the most recent period. Imports have surged again in the current year, after the present period of investigation.
- d. Despite more than sufficient capacities for the product in India, the product is being imported from Korea RP to the extent of almost 1/3rd of the demand for the product in the country.
- e. Share has increased from almost zero percent in pre-concession period. Market share of Korean imports was 16% when duties were reduced to zero% and they now hold 36% share in the demand. Market share of the Korean imports has increased by more than 50% in the last 4 years.
- f. Imports from Korea RP were only 16% in relation to Indian production when the concessions were granted but now are more than 60%.
- g. Before concessions were given, 98% of import requirement in Indian market was met by countries other than Korea. Korea now commands 94% of India's imports thus practically eliminating all other countries.
- h. Korea is not the largest exporter of the subject goods globally. With no significant consumption in the Republic of Korea, it is not even the largest producer of the subject goods. Korea holds no natural advantage in this product.
- i. Global exports from Korea RP have increased by only 13 times over the period, from 1,797 in 2009-10 to 23,287 in the year 2021-22. By contrast, Korea's exports to India have increased by almost 180 times.
- j. Article 2.22 of the India-Korea CEPA provides for imposition of bilateral safeguard measure in the event of imports in "increased" quantities. The requirement under the rules is not a consistent and continuous increase in imports. It is imports in "increased quantities".
- k. WTO in case of United States – Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea held that it may not necessarily be the case that most recent trends are most significant trends and the word "recent" need not require that imports be increasing right up to the date of the determination.
- l. While the interested parties have argued that the increase in imports is not due to reduction in custom duty, they have brought forward no material to show other reasons for increased imports. Further, Article 2.22 of the CEPA Agreement makes it clear that the reduction of custom duty need not be the sole reason for increased imports.
- m. Out of the three participating companies, only one of the companies has imported insignificant volumes. While there is no such requirement under the law to exclude such imports, even if these imports are excluded, the data shall still show "increased imports" within the meaning of the Rules. The increased imports are not because of imports by one of the domestic producers.

G.3 Examination by the Director General

51. The CEPA provides for an increase in imports as a basic prerequisite for the application of a bilateral safeguard measure. Further, to determine whether the imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for the purpose of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in the imports, in absolute terms or in relation to domestic production. Article 2.22 of CEPA provides as follows: -

*"During the transition period only, if as a result of the reduction or elimination of a customs duty under this Agreement, an originating good of the other Party is being imported into the territory of a Party **in such increased quantities**, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions that the imports of such good from the other Party alone constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to the domestic industry producing a like or directly competitive good, the Party may*

- (a) *suspend further reduction of any rate of customs duty on the good provided for under this Agreement; or*
- (b) *increase the rate of customs duty on the good to a level not to exceed the lesser of:*
 - (i) *the MFN applied rate of customs duty on the good in effect at the time the measure is taken; and*
 - (ii) *the MFN applied rate of customs duty on the good in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of this Agreement."*

52. Rule 2 (c) of the Rules defines increased imports as follows: -

(c) “increased imports” includes increase in imports from the Republic of Korea whether in absolute terms or relative to domestic production

53. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC), in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract therefrom is as follows:

“[W]e recall Article 4.2(a)'s requirement that 'the rate and amount of the increase in imports' be evaluated. In our view this constitutes a requirement that the intervening trends of imports over the period of investigation be analysed. We note that the term 'rate' connotes both speed and direction, and thus intervening trends (up or down) must be fully taken into consideration. Where these trends are mixed over a period of investigation, this may be decisive in determining whether an increase in imports in the sense of Article 2.1 has occurred. In practical terms, we consider that the best way to assess the significance of any such mixed trends in imports is by evaluating whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer-term change.

131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'.”

54. The Panel on US — Wheat Gluten, interpreted the phrase “in such increased quantities” as follows:

“8.31 [A]rticle XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards (“SA”)] do not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”

55. In US — Line Pipe, the Panel found, in a statement not reviewed by the Appellate Body, that “there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have ‘increased’ in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination”:

“[T]here remains the question of whether the finding of increased imports can be maintained in light of the decline in absolute imports from the first semester of 1998 to the first semester of 1999. In order to answer this question we recall our discussion regarding the meaning of ‘recent’, and our finding that ‘recent’ does not imply an analysis of the present. We are also of the view that the fact that the increase in imports must be ‘recent’ does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating Director General’s determination, nor up to the very end of the period of investigation. We find support for our view in Article 2.1, which provides ‘that such product is being imported ... in such increased quantities’. The Agreement uses the adjective ‘increased’, as opposed to ‘increasing’. The use of the word ‘increased’ indicates to us that there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have ‘increased’ in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product ‘is being imported’ at such increased quantities at the end of the period of investigation, the requirements of Article 2.1 are met.”

56. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in light of the above-mentioned rules and WTO jurisprudence.
57. The Director General considers that the rules do not prescribe that there should be a consistent continuous increase in import up to the most recent period. The WTO panel in the US — Line Pipe found that there was

no requirement of a determination that imports are continuously increasing. The only requirement is that the imports should have increased in the recent past.

58. The interested parties have contended that the volume of imports has not increased with an increase in tariff concession. The Director General has therefore examined the imports of the product under consideration before tariff concession, during the period of tariff concession and post-elimination of tariff.
59. As regards the contention that the imports made by the applicants should be excluded while ascertaining the import volume into India, the table below shows the volume of imports made by the applicants: -

SN	Year	Boon Metal & Alloy Corporation	Premier Alloys & Chemicals	Team Ferro Alloys	Imports from Korea in MT
1	***	***	***	***	2,361
2	***	***	***	***	2,967
3	***	***	***	***	2,919

60. It is seen that the volume of imports made by the applicants is insignificant considering gross imports from Korea and Indian demand for the product. The rules do not provide for exclusion of either a domestic producer who is importing the product, or the volume of imports made by such domestic producer. No reason has been adduced by the interested parties to justify the exclusion of the domestic producer or the volumes of imports made by such domestic producer. The Director General has neither excluded the domestic producer from the scope of the domestic industry, nor the volume of such imports made by the domestic producer.
61. The Director General considered imports from Republic of Korea and other countries over the relevant period. In view of the arguments of the interested parties that the Director General should examine whether imports have surged as a result of tariff concession, the Director General examined the volume of imports before the start of the concession, and from 2009-10. The Director General also notes that the interested parties have not submitted any evidence to show any other reason for increase in subject imports. Further, since the interested parties contended that the surge in imports was only in one quarter, the Director General examined the volume of imports after March 2022 and for the period up to December 2022. Relevant information regarding the volume of imports over the years is given below.
- a. Imports in absolute terms
62. The information regarding imports in absolute terms over the years is given below.

SN	Year	Imports into India in MT			Customs duty
		Korea RP	Other countries	Total Imports	Korea
1	2008-09	93	838	931	5%
2	2009-10	30	1,296	1,326	5%
3	2010-11	473	605	1078	5%
4	2011-12	551	768	1319	5%
5	2012-13	474	314	788	5%
6	2013-14	732	183	915	4.69%
7	2014-15	657	678	1335	3.44%
8	2015-16	728	123	851	2.19%
9	2016-17	716	89	805	0.94%
10	2017-18	1,598	83	1681	0%
11	2018-19	1,957	402	2359	0%

12	2019-20	2,361	310	2671	0%
13	2020-21	2,967	190	3157	0%
14	Apr 21 – Sep 21 (A)	1,872	280	2152	0%
15	Oct 21 – Mar 22 (A)	3,966	404	4370	0%
16	Apr 22 – Dec 22 (A)	4,279	1,330	5,609	0%

63. It is seen that: -

- Before the concessions started, the import volumes in 2009 were only 26 MT. However, during the period when the custom duties were in force, the volume of imports was in the range of 400-500 MT.
- The imports doubled in 2017-18 when the custom duties were reduced to nil.
- The imports have further increased to more than 3500 MT in the most recent period of October 2021 to March 2022.
- The Director General has additionally analysed the imports from April to December 2022 (the period after the most recent period) and it is seen that the imports have continued to increase.

64. The Director General notes that consideration of imports over the longer period covering the pre-concession, during concession, post-concession, most recent period and the period after the most recent period shows a significant surge in imports.

b. Imports from Korea RP in relative terms.

65. The information regarding imports in relative terms over the years is given below. The Director General examined the subject imports in relation to gross imports in India, in relation to Indian production and consumption.

SN	Particulars	Imports from Korea in MT	Imports in relation to		
			Indian Demand	Indian Production	Total Imports
1	2018-19	1,957	23%	32%	83%
2	2019-20	2,361	28%	41%	88%
3	2020-21	2,967	33%	50%	94%
4	Apr 21 – Sep 21 (A)	1,872	22%	29%	87%
5	Oct 21 – Mar 22 (A)	3,966	39%	71%	91%

66. It is seen that: -

- Imports in relation to Indian demand have increased from 23% in 2018-19 to 39% in the most recent period.
- Imports in relation to Indian production have increased from 32% to 71% in the most recent period.
- The imports in relation to total imports have increased to 91% in the most recent period.
- With the elimination of custom duties, the Korean imports have replaced the other imports in the market.
- The applicants have contended that when considered over a longer period, the imports from Korea RP had a market share of only 1% to 10% when there were no concessions, but the market share has increased to around 40% in the most recent period.
- Further the applicants have contended that the imports in relation to Indian demand and production have increased significantly when considered over the pre-concession, during concession, post-concession period. The table below shows the contention of the applicant.

SN	Year	Subject imports in relation to		
		Total Imports	Indian Demand	Indian Production
1	2008-09	10%	3%	5%
2	2009-10	2%	1%	1%
3	2010-11	44%	11%	15%
4	2011-12	42%	11%	14%
5	2012-13	60%	9%	10%
6	2013-14	80%	14%	17%
7	2014-15	49%	9%	11%
8	2015-16	86%	11%	13%
9	2016-17	89%	10%	11%
10	2017-18	95%	20%	24%
11	2018-19	83%	23%	32%
12	2019-20	88%	28%	41%
13	2020-21	94%	34%	50%
14	Apr 21 – Sep 21 (A)	87%	22%	29%
15	Oct 21 – Mar 22 (A)	91%	39%	71%

67. As regards the contention that the increase in imports in the most recent period is due to the arrival of material against orders deferred earlier due to Covid, the Director General notes that the imports have increased not only in the present recent period, but also after the start of concession and even after the present surge period. In fact, the volume of imports after the most recent period is materially higher than the volume of imports in the most recent period. Considering imports over the pre-concession, during concession and post-concession period shows a continuous increase in imports. In view of the above, the argument of the interested parties cannot be accepted.
68. It has been contended that the imports declined in quarter 4 of 2021-22. It is however seen that the imports have increased significantly after Q4, 2021-22. Further, a lot of interested parties have contended that imports declined in some quarters and increased in others. The Director General notes that requirement under the Rules is not “increasing imports” but “increased imports”.
69. It has been contended that the increase in imports is because of the capacity expansion by the steel producers. The Director General notes that imports have been examined for the pre-concession, during concession and post-concession periods. It is seen that the demand of the product under consideration has increased sharply in the period October 2021 to March 2022. However, the entire increase in demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry. Further, no material has been brought forward to show that the users faced any quality issues with the product supplied by the Indian industry. The increase in imports in absolute volume and increase in market share in demand over the long period establishes that the increase in imports has no nexus with the factors listed by the interested parties.
70. The interested parties have contended that the Director General should examine the intervening trends as well and should not restrict examination to a mere comparison between the beginning and at the end of the period. The Director General has examined the volume of the imports over a period of more than 10 years which addresses the concerns raised by the interested parties.
71. As regards the contention that increased imports are because of increasing demand, Director General notes that it has examined the trend of imports over a substantially long period to examine imports in absolute and relative terms and it is seen that the market share of imports has also increased. It is also seen that when the applicants had sufficient capacity to cater for the entire demand in the country, it cannot be accepted that the imports increased only because of the increasing demand in the country.

72. It has been submitted that the imports declined in some quarters and increased in others. The Director General notes that the rules do not require that there must be a continuous increase in imports. The consideration over a long period has ensured that the intervening trend of increase in some quarters and decline in some quarters is addressed.
73. The Director General concludes considering imports in pre concession, during concession, post concession and the most recent period, that imports from Korea RP have increased in absolute terms. The imports have also increased in relation to Indian production and consumption and total imports in the period April 2018 to March 2022. With the total elimination of tariff, Korean imports have started commanding majority share in imports of the subject goods into India. The increase in the imports with the rising tariff concession over the period shows the presence of co-relation between the custom duty elimination and increased imports. Further, no material has been brought forward by the interested parties to show any other reason for increase in subject imports. The increase in imports constitute increased imports as per the CEPA and the Rules. Therefore, the Director General concludes that the imports from Korea RP have increased.

H. INJURY TO THE INDIAN INDUSTRY

H.1 Submissions made by the interested parties.

74. The submissions made by the interested parties in respect of injury to the domestic industry are summarised below -
- a. There is no significant change in capacity, production, capacity utilisation, domestic sales volume and value, and market share over the years.
 - b. The domestic producers cannot operate at optimum capacity and cannot improve profitability due to high fixed cost owing to surplus capacity.
 - c. Price undercutting is either negative or insignificant over the period of investigation.
 - d. Rise in price of Korean imports along with raw material prices cannot be seen as injury to the domestic industry.
 - e. There is no price suppression on the domestic industry prices due to Korean imports.
 - f. Losses in the last six months of 2021-22 is inconsequential.
 - g. Profitability of the Indian industry has improved substantially.
 - h. In quarter 2 of 2021-22, sales volume and profits of the domestic industry increased despite reduced gap between raw material price and price of Korean imports compared to quarter 1.
 - i. Sales of the product happens through bidding process and no information is available to competitors for undercutting.
 - j. The Director General should assess competition within the Indian industry in assessing whether injury is caused to industry.
 - k. The tariff concessions could not have caused the change in prices and the fluctuation in the prices is because of other factors,
 - l. The low-priced Chinese imports have also caused injury to the Indian industry.
 - m. Other factors such as increase in raw material costs in 2021-22, high basic custom duty on import of raw material, depreciation of INR making raw materials costly have also caused injury.
 - n. The Director General should also examine the impact of molybdenum shortage on the domestic industry.
 - o. Domestic producers cannot operate at optimum capacity and cannot improve their profitability because of high fixed cost owing to significant surplus capacity with them.
 - p. Decline in landed price was commensurate to the decline in cost of sales of the domestic industry till 2020-21. Rate of increase in landed price in 2021-22 was higher as compared increase in cost of sales.
 - q. Rise in prices of imports is in accordance with the rise in raw material prices.
 - r. PBIT of the domestic industry has increased by 19 times in 2019-20 to 2020-21. The applicants have shifted from deficit to surplus in cash profits.
 - s. Foreign producers have achieved good economies of scale, and their efficient manufacturing and controlled processes are cost efficient which gives them advantage over the Indian producers.

- t. Korean producers book bulk order of Moly which provides them edge over the Indian producers.
- u. Indian FeMo producers are producing FeMo at small scales and do not have established process of producing quality products with consistence supplies.
- v. Submission of the applicants clearly show existence of an inverted duty structure, scarcity of raw materials, raw material price fluctuations, an inability to scale operations, etc are the reasons of the injury.
- w. The domestic industry is unable to reach optimal capacity utilization because of its excessive capacities and is evidently burdened by overhead costs.
- x. The applicants have admitted that the raw material is a scare resource and import attracts basic customs duty of 2.5% and the burden of these import duty is very high.
- y. Korean exporters have achieved higher integration and more cost-efficient processes of production as they utilize unroasted molybdenum as their primary raw material as opposed to the Indian industry which utilizes roasted molybdenum.
- z. There have been significant fluctuations in the raw material prices during the period of investigation due to short supply of the molybdenum globally.
- aa. There is no suppressing impact on the prices of the applicants as domestic selling price has declined commensurately with the decline in cost of sales till 2020-21 and when the cost of sales increased in 2021-22, the domestic industry was able to commensurately increase the selling price.
- bb. It will be misleading to conduct an analysis of injury based on the data of half year. If data from both halves of 2021-2022 is combined, it will show that that there is no injury to the applicants.
- cc. There is a clear improvement in the production and sales of the applicants in the year 2021-22.
- dd. There is a difference in the profitability information submitted in the application and written submission.
- ee. The applicants performed better in quarter 3 when the imports were high but the performance worsened during quarter 4 when the imports declined.
- ff. Korean producers were able to adjust their prices in accordance with raw material price changes, the Indian industry is plagued by a series of systemic factors owing to which it has been unable to adjust to changes in raw material prices.
- gg. The applicants have not established how increase in freight cost could have impacted their performance.
- hh. Substantial cause of injury to the applicants is due to customs duty of 2.5% on import of raw material.
- ii. Injury caused by the price of the imported product is not a relevant consideration in the evaluation of bilateral safeguard measures. Price of products originating from Korea RP is irrelevant for the purpose of determining the need for bilateral safeguard measure.
- jj. The applicants' ability to increase price commensurate with the increase in cost of sales shows that imports from Korea RP are not causing any adverse price effects to the domestic industry.
- kk. Producers in Korea RP have much higher capacity and can get the benefit of economies of scale and control their fixed costs. The benefit of economies of scale available to producers/exporters from Korea RP cannot be overcome by imposition of bilateral safeguard measures.
- ll. There is no co-relation between the increased imports and the performance of the domestic industry. When imports increased, the performance of the domestic industry improved and when imports declined, the performance of the domestic industry also declined.
- mm. Capacity of the Indian industry has increased from 15,000 MT to 19,800 MT and the market share has also remained at 68% or above during this period. This shows that the industry has not suffered injury.
- nn. The applicants have misguided by citing "annualized" data divided in half.
- oo. The applicants have not presented source of most of the data cited.
- pp. The applicants undertake a 10% value addition and that 90% of their production cost consists of its raw material cost for which they are entirely dependent on imports to procure its raw material. Hence, they cannot adjust to import competition as raw material cost optimization cannot be controlled by them.
- qq. The applicants were in profits even in 2020-21 when the import volumes of the PUC from Korea were at its highest.

- rr. Market share of the entire Indian industry is still at a robust 68% in 2021-22.
- ss. The requirement is to show that the imports of the subject good from Korea are the sole cause of the injury to the domestic industry considering the nature of bilateral safeguards, which is the exception to the core principle of non-discrimination grounded in Global Safeguard Measures.
- tt. WTO in case of Wheat Gluten has also held that to satisfy the requirement that increased imports “alone” cause serious injury, the Authority must exclude the effects caused by other factors in its analysis.
- uu. The applicants have requested for only 5% custom duty. The entire scheme of formula based pricing of the applicants will become futile if the price of the raw material increase by more than 5%.
- vv. The applicants have misinterpreted the actual meaning or intent behind Article 2.22 of the Agreement by stating that “injury caused by the increased imports need not be equal to or more than any other cause of injury.”
- ww. Export price from the Republic of Korea to India and the rest of the world are on account of multiple factors like economies of scale, difference in molybdenum content, difference in timing of supply, power of the local currency, etc. An analysis of export price from Republic of Korea to India and rest of the world would not objectively determine that Korean imports specifically target the Indian market at low prices.
- xx. Injury due to export performance should also be examined.
- yy. The depreciation cost of the applicants have increased despite there being no capacity expansion.
- zz. The applicants recorded profits in the previous years even when the imports increased. This shows that there is absence of correlation between increased imports and decline in profitability.
- aaa. The annual reports of the other producers show that they have seen an increase in earnings before interest tax and depreciation.
- bbb. The injury to the Indian industry can also be on account of *interse* competition.

H.2 Submissions made by the applicants.

- 75. The submissions made by the applicants in respect of injury are as follows-
 - a. Korean producers have been selectively targeting Indian market. The FOB prices of exports to India have been typically lower than the average export price to third countries.
 - b. In the most recent period, the selling price of the domestic industry are suppressed.
 - c. The production and capacity utilization of the domestic industry has declined with the increased imports from the subject country.
 - d. The increased imports have eroded the market share of the domestic industry resulting in decline in domestic sales.
 - e. The capacity utilisation of the domestic industry fell steeply and was at lowest levels in the most recent period.
 - f. The domestic industry had suffered losses in the base year itself when the second surge in imports happened. Losses increased in the subsequent year when the domestic industry tried to increase its market share by selling at prices in competition with the import price.
 - g. The year 2020-21 saw an improvement in profitability as the domestic industry sacrificed its market share. The performance further improved in the H1 of 2021-22 as the imports declined sharply. However, the domestic industry has suffered losses again in the most recent period with the increased imports and decline in market share.
 - h. Unlike a large-scale producer, a MSME producer cannot continuously suffer losses. Effect of import competition comes largely on the sales, and therefore can be found in volume parameters.
 - i. If losses continue for a long period, producer will stop production. The producers would normally take any order only if there is some financial viability. Otherwise, they would curtail production rather than suffering financial losses.
 - j. While the legal requirement is for Director General to examine injury to the domestic industry and not the Indian industry as a whole, even the data of the Indian industry shows that production increased till 2018-

19 but has declined thereafter and domestic sales increased until there was a surge in imports but has declined thereafter.

- k. The contribution earned by the domestic industry is negative in the most recent period. The domestic industry is unable to recover what it is incurring as direct cost to produce the goods, leave aside recovery of the fixed expenses.
- l. The reason why the data shows negative price undercutting is solely because of significant changes in the price of the raw material and the product in this period.
- m. Even when the price of the product might have fluctuated due to changes in raw material prices, the fact is that imports surged, and the domestic industry suffered injury.
- n. The serious injury suffered by the domestic industry is due to tariff concession on finished product, and not due to customs duty on raw materials. The inverted duty structure has been caused by the present duty concession. If the duty concession is withdrawn, the Indian industry is competitive.
- o. The fact that the sales happen through bidding process itself shows that the consumers buy from the suppliers which offers lowest prices.
- p. Whenever the industry has tried to maintain its profits, it has lost market share, and, whenever the industry has tried to capture market, it has suffered losses.
- q. Footnote to Article 2.22 of the India – Korea Comprehensive Partnership Agreement states that the reduction in custom duty need not be the sole cause of the injury to the domestic industry.
- r. The only requirement is that the imports should be a substantial cause of injury. Reference is also drawn to the finding in Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of Phthalic Anhydride wherein Director General took a similar opinion.
- s. Price fluctuations in raw material prices is equally impacting Korean producers as they import raw material. If there have been no increased imports from Korea, the domestic industry could have increased its prices with the increase in the raw material cost.
- t. As regards increased freight a cause of injury, the same impacted Korean producers also as they import raw material and export subject goods to India.
- u. Imports from other countries have been substituted by imports from Korea. Increase in imports from China is in low volumes and cannot cause injury. Share of Chinese imports to total demand has always remained 3% or less.
- v. Volume of exports by the domestic industry is negligible and therefore, export performance cannot be a cause of injury.

H.3 Examination by the Director General

76. The information made available by the interested parties in their submissions, and imports information called by the Director General have been considered for the purpose of the present determination. The Director General notes that different interested parties have advanced similar arguments, albeit in different manner and language. The Director General has examined and addressed the submissions in the present findings. The examination herein below in respect of serious injury and causal link *ipso facto* deals with the submission of applicants and interested parties.
77. Serious Injury is defined under the Rules as follows:

(f.) *serious injury means a significant overall impairment in the position of a the domestic industry; and*

(g) *"threat of serious injury" means serious injury that, on the basis of facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility, is clearly imminent.*

78. Rule 7 of the Rules further provides as follows:

The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely: -

(a) the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the originating good in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken

by increased imports of the originating good, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and

(b) the determination under this rule shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the originating good and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports of the originating good are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports of the originating goods.

79. The following provisions of the CEPA are also relevant for analysis and examination of injury to the domestic industry and for evaluating the contentions raised by interested parties.

“During the transition period only, if as a result of the reduction or elimination of a customs duty³ under this Agreement, an originating good of the other Party is being imported into the territory of a Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic production, and under such conditions that the imports of such good from the other Party alone⁴ constitute a substantial cause of serious injury or threat thereof to the domestic industry producing a like or directly competitive good, the Party may:

³A determination that an originating good is being imported as a result of the reduction or elimination of a customs duty provided for under this Agreement shall be made only if such reduction or elimination is a cause which contributes significantly to the increase in imports, but need not be equal to or greater than any other cause. The passage of a period of time between the commencement or termination of such reduction or elimination and the increase in imports shall not by itself preclude the determination referred to in this footnote. If the increase in imports is demonstrably unrelated to such reduction or elimination, the determination referred to in this footnote shall not be made.

⁴ For the purposes of certainty, the Parties understand that a Party is not prevented from initiating a bilateral safeguard investigation in the event of a surge of imports from the territory of non-Parties. For further certainty, the Parties understand that bilateral safeguard measures can only be imposed on the good of the other Party when the increase in the import of such goods from that other Party alone constitute a substantial cause of serious injury or threat of serious injury, to the domestic industry producing a like or directly competitive good.

80. The Director General considers that evaluation of various injury parameters needs to be undertaken having regard to the peculiarities of different industries and situations. The Director General has examined the presence of serious injury to the domestic industry, having regard to the facts of the present case and the situation of the present industry.
81. The Director General has noted that the Indian industry in the present case comprises of producers in MSME segment. While the value addition in absolute terms is quite significant, it is low in relation to the price of the input raw materials. The price of FeMo is normally fixed considering the prevailing prices of Moly.
82. It has also been contended by the interested parties that the sale of the product happens through the bidding process. The domestic industry has also accepted the contention of the interested parties. The Director General notes that the fact that the sale of the product happens through a bidding process shows that the preference of the users to buy the product from the supplier which quotes the lowest price. Further, no other justification has been brought forward by the interested parties on why the imports from Korea RP have increased. Therefore, it flows that the increase in the imports from Korea RP is because of the price advantage with the Korean producers. The rate of increase in imports from Korea RP, the decline in imports from other countries and market share of the Indian industry show that the Korean producers have outpriced the other suppliers in the market.
83. As regards the contention that the applicants' performance has been impacted because of the increase in the raw material cost due to depreciation of the Indian Rupee. The Director General notes that had the industry suffered due to the contended factor, the same would have applied to imports of all products from all countries and also on the product under consideration. Further, the depreciation in the currency is equally applicable for the Korean produces. Therefore, the contention cannot be accepted.
84. It has also been contended by the applicants that more than 90% cost of sales is variable cost and the producers are not burdened with high fixed costs. Therefore, the producers would normally take any order only if there is some financial viability i.e, if the quoted order is above the cost of production. If there is no financial viability, the producers would normally curtail production rather than suffering financial losses. Being MSME in nature, the producers cannot continue to inject funds in the business. Therefore, effect of import competition comes

largely on the sales and production volume. The applicants have contended that the primary form of injury to the Indian industry can be found in volume parameters.

85. As regards the contention that the Indian producers are inherently less competitive because of the custom duty on raw material, the Director General notes that the Government of India has granted tariff concessions to Moly when imported from Chile and Thailand and it has been submitted by the domestic industry that around 70% of the imports happen through these sources. Therefore, it cannot be said that the Indian industry is less competitive because of custom duty. The Korean producers do not have any natural advantage of raw material. The scope of the present investigation is whether imports of FeMo have increased and whether the same has caused injury to the Indian industry, and if so, whether safeguard measures should be invoked.
86. As regards the argument that the performance of other producers in India shows improvement, the Director General has considered the information of other producers on the record. It is seen from the annual report of other companies that these producers are multi product companies and therefore reference to annual reports cannot be relied upon. Further, the information filed by five producers contains information on production, sales and capacity utilisation which show that they have also suffered on volume parameters.
87. As regards the contention that the price fluctuations are due to some other factors and not just imports, the Director General notes that the prices of molybdenum have fluctuated significantly during the recent period and the landed price of imports and the cost of sales of the domestic industry have both moved in the same direction.

SN	Particulars	2018-19	2019-20	2020-21	Apr to Sep 21	Oct to Mar 22
1	Landed price	1,228	1,136	955	1,783	2,079
2	Cost of sales	***	***	***	***	***
3	Selling Price	***	***	***	***	***
	Indexed					
5	Landed price	100	93	78	145	169
6	Cost of sales	100	88	91	135	165
7	Selling Price	100	96	91	137	166

UOM – Rs/KG

88. It has been contended that the Korean producers are more integrated as they use unroasted molybdenum and therefore are more efficient as compared to the Indian producers. The Director General notes that the domestic industry could earn profits in the previous years shows that it can compete with the imports. Further, no information has been provided to the Director General to show the difference in cost on account of roasted or unroasted Moly. Therefore, the contention cannot be accepted.
89. The interested parties have argued that the applicants are suffering due to high capacities. The Director General considers that in a situation of sufficient or even high capacities, it is evident that any surge in imports shall cause serious injury. Even the Korean producers are holding capacities far in excess of their country's domestic demand. If the Indian industry has suffered while holding excessive capacities, it is due to the surge in imports despite such excessive capacities. The Director General has examined the difference between the selling price and the variable cost which is shown below: -

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	Apr to Sep 21	Oct to Mar 22
1	Selling price	Rs/Kg	100	96	91	137	166
2	Variable cost	Rs/Kg	***	***	***	***	***
3	Contribution	Rs/Kg	100	226	112	147	63

90. As regards the contention that the Indian producers are burdened with fixed costs, the Director General has examined the data of the applicants. It is seen that the share of fixed costs in the total cost of the applicants is insignificant. Further, the contribution (difference between selling price and variable cost) of the applicants in the most recent period is lower than the contribution earned in the base year as well as immediately preceding period. However, the applicants have submitted that the relevant form of injury considering the present nature of the industry is volume injury.
91. It has been contended that the imports from other countries (particularly from China) have caused injury to the domestic industry. The Director General has examined the volume of imports from China over the entire relevant period. The table below shows the imports of FeMo over the period of investigation: -

SN	Countries	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	Apr to Sept 21 (A)	Oct 21 to Mar 22 (A)
1	Korea Rp	MT	1,957	2,361	2,967	1,872	3,966
2	China P Rp	MT	20	20	-	-	320
3	U Arab Emts	MT	140	40	80	40	2
4	Switzerland	MT	-	79	100	240	80
5	Hong Kong	MT	140	90	-	-	-
6	U S A	MT	40	-	-	-	-
7	Singapore	MT	40	20	-	-	-
8	Germany	MT	15	20	5	-	-
9	Brazil	MT	7	21	-	-	-
10	South Africa	MT	-	20	-	-	-
11	Canada	MT	-	-	5	-	-
12	Sweden	MT	-	-	-	-	3
13	Malaysia	MT	1	-	-	-	-
14	Total	MT	2,359	2,670	3,157	2,152	4,370

92. It is seen that in past, there were imports happening from the European Union, the United States of America and the United Kingdom as well. However, those imports have completely dried up now. It is seen that the imports from China were extremely low in volume almost throughout the period, barring the most recent period. In so far as the current period is considered, it is seen that whereas Korean imports were 3,562 MT, Chinese imports were only 320 MT (on annualised basis). The Director General has also examined the trend of imports over the period of investigation and found that there is no consistency in the imports from China. Over the entire period, imports from China have happened in only 8 months and are only 280 MT in total. Therefore, the volume of imports from China and other countries was insignificant in the most recent period to have caused injury to the domestic industry. In any case, the Director General has considered a sufficiently long period which shows that the imports from other countries are insignificant in volume.
93. It has also been submitted by the interested parties that the injury caused can be due to the *interse* competition. The Director General notes that it has examined the performance trend of the applicants and the supporters. When the production and domestic sales of both the applicants and supporters have declined with an increase in imports, it cannot be contended that the decline in these parameters is due to *interse* competition only.
94. It has been contended that the depreciation cost of the applicants has increased despite no increase in the capacity. Director General has examined the records maintained by the applicants and it is seen that the same is as per the allocation methodology in the books of accounts. However, the Director General has not accepted the depreciation cost claimed and has considered the revised information.
95. It has also been submitted by other interested parties that the return on capital of the applicants has increased significantly over the period of investigation. The Director General notes that return on capital employed is not a relevant factor of examining injury to the Indian industry in the present investigation due to the nature of the

product, the high value of the product and the low capital employed. In any case, the applicants have stated that the primary form of injury is the volume injury.

96. In analysing serious injury, all factors mentioned in the Rules as well as other factors which have been brought to the notice of the Director General and which are considered relevant for determination of serious injury, have been considered. The determination of serious injury thus is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.
- a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.
97. Facts regarding capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry are given below.

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	Apr to Sept 21 A	Oct to Mar 22 A
1	Capacity	MT	6,216	6,216	6,216	6,216	6,216
2	Production	MT	2,572	2,183	2,376	2,794	2,214
3	Capacity Utilisation	%	41%	35%	38%	45%	35%
4	Domestic sales	MT	2,516	2,304	2,354	2,809	2,509
5	Demand	MT	8,695	8,448	8,762	8,509	10,250
6	Imports	MT	1,957	2,361	2,967	1,872	3,966
7	Market share in demand	%	29%	27%	27%	33%	24%

98. It is seen that: -

- Capacity of the applicant companies has remained constant throughout the period of investigation. Capacity of the Indian industry is sufficient to cater to the entire demand in the country.
- Production and capacity utilisation declined in 2019-20 as the demand declined. The production and capacity utilisation increased in the year 2020-21 as the demand increased and imports declined. However, the increase in production was significantly low considering the increase in the demand.
- Production and capacity utilisation increased in April to September 2021 despite decline in demand as the imports also declined. With the increase in imports in October 21 to March 22, production and capacity utilisation have declined in the most recent period.
- The domestic sales of the industry declined in 2019-20 but increased thereafter in 2020-21. However, while the domestic sales increased, the market share did not increase as the imports also increased in this period. The domestic sales increased in Apr 21 to Sep 21 as the imports declined. The domestic sales have however declined in October to March 2022.
- The demand has increased considerably during the period from October '21 to March '22 as compared to the corresponding periods. However, the entire increased demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry. The domestic sales of the industry have not increased due to the increase in demand.
- The demand of the subject goods in October 2021 to March 2022 (most recent period) has increased by 871 MT (actual basis) and 1,741 MT (annualised basis) as compared to April 2021 to September 2021. During this period, the imports increased by 1,047 MT (actual basis) and 2,094 MT (annualised basis). The rate of increase in imports is more than the increase in the demand and as a result, the domestic sales of the applicants have declined.

99. The applicants have contended that the Indian industry had a market share of 87% when the tariff concessions first started. The domestic industry market share remained in a similar range as the tariff concessions increased and reached full levels in 2016-17. The market share of the Indian industry however started declining thereafter as the Korean imports surged. Thus, the tariff concessions have led to significant decline in the market share of the Indian industry. It is seen that while the demand has grown, the market share of the domestic industry has declined.

b. Market share of the domestic industry

100. Information regarding the market share of the domestic industry is given below:-

SN	Market share of	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	Apr 21 – Sep 21	Oct 21 – Mar 22
1	Applicants	%	29%	27%	27%	33%	24%
2	Other producers	%	44%	41%	37%	42%	33%
3	Indian industry	%	73%	68%	64%	75%	57%
3	Korean imports	%	23%	28%	34%	22%	39%
4	Other countries	%	5%	4%	2%	3%	4%

101. It is seen that: -

- Market share of the applicants declined in 2019-20 and remained at almost the same level in 2020-21. The market share of the applicants increased in April to September 2021 when the imports declined, but has declined again in the most recent period.
- The market share of the applicants has declined in the most recent period as compared to the base year and the preceding period. The market share of the applicants in the most recent period is the lowest over the entire period of investigation.
- The market share of the Indian industry has followed the similar trend to that of the applicants. The market share declined in 2019-20, then further declined in the year 2020-21. The market share of the Indian industry increased in April to September 2021 but has declined again in the most recent period.
- The market share of imports increased in 2019-20 as compared to 2018-19. The market share of imports increased again in 2020-21. The market share declined in April to September 2021 but has increased again in the most recent period. The market share of the imports from the subject countries has increased over the period of investigation.

c. Inventory

102. Information regarding the market share of the domestic industry is given below: -

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	Apr 21 – Sep 21	Oct 21 – Mar 22
1	Opening	MT	***	***	***	***	***
2	Closing	MT	***	***	***	***	***
3	Average	MT	29	77	107	110	92
4	Domestic sales	MT	2,516	2,304	2,354	2,809	2,509

103. It is seen that the closing inventory of the applicants increased in 2019-20 as the domestic sales declined. The closing inventory remained at almost same level in 2020-21 and Apr 21 to Sep 21 but has declined in October 21 to March 22. The average inventory of the domestic industry increased till September 2021. Even when inventories declined thereafter with curtailment of production, the level of inventories was nevertheless high.

d. Profit/loss

104. The facts with regard to profits, profit before interest, and cash profits are as follows: -

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	Apr 21 – Sep 21	Oct 21 – Mar 22
1	Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***	***

	Trend	Indexed	100	85	91	135	166
2	Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	91	137	166
3	Profit/(Loss)	₹/Kg	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	480	116	244	160
4	PBIT	₹/Kg	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	344	108	174	118
5	Cash Profit	₹/Kg	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	465	123	240	159

105. It is seen that the: -

- The applicants' profitability improved till 2019-20. The profit per unit declined in 2020-21 as the imports increased. However, the profit per unit improved in the period April to September 2021 as the imports declined.
- With the increase in imports in October 2021 to March 2022, the profit per unit of the applicants has declined again.
- The cash profits and profit before interest and tax have also followed the same trend. Cash profit and profit before interest and tax improved with the decrease in imports but have declined in the most recent period.
- It has however been contended that the considering the MSME nature and the value of the product under consideration, the real injury suffered in the form of volume injury.

e. Employment and productivity

106. Facts regarding employment and productivity is given below: -

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	Apr 21 – Sep 21	Oct 21 – Mar 22
1	No. of Employees	Nos	129	130	150	141	141
2	Productivity per Employee	MT/ Nos	20	17	16	20	16
3	Productivity per Day	MT/ Days	8	7	7	8	7

107. It is seen: -

- The number of employees increased till the year 2020-21 but has declined thereafter.
- The productivity per employee declined till 2020-21 but increased in April to September 2021 as the production increased. The productivity per employee has declined again in the most recent period.
- The productivity per day declined in 2019-20 but has increased thereafter in 2020-21 and April to September 2021. The productivity per day has declined in the period October 2021 to March 2022.
- The applicants have not claimed injury in these parameters.

f. Price undercutting

108. Information regarding price undercutting is given below: -

SN	Particulars	UOM	Oct 21 – Mar 22
1	Selling Price	₹/Kg	***
2	Landed price	₹/Kg	2,079
3	Price undercutting	₹/Kg	***
4	Price undercutting	%	***
5	Price undercutting	Trend	(0-5) %

109. It is seen that the price undercutting on weighted average basis is negative. It has been contended that there is significant volatility in the prices of the product under consideration; and therefore, average price undercutting may not be a relevant parameter. The table below shows the price movement in a particular month: -

Rs/KG

SN	Month	Average price	Maximum price	Minimum price
1	April – 21	1,314	1,399	1,256
2	May – 21	1,419	2,037	1,176
3	June – 21	1,629	2,070	1,242
4	July – 21	1,707	2,392	1,231
5	August – 21	2,070	2,468	1,647
6	September – 21	2,019	2,441	1,262
7	October – 21	2,048	2,317	1,663
8	November – 21	2,050	2,285	1,874
9	December – 21	2,081	2,172	1,976
10	January - 22	2,038	2,127	1,899
11	February – 22	2,131	2,282	2,037
12	March - 22	2,139	2,510	2,016

110. It is seen that the prices of the product under consideration have fluctuated significantly even in a particular month and therefore consideration of price undercutting on average basis may not be relevant.
111. The Director General also notes that the responding exporter have stated that the sale of the product happens through the bidding process which has been admitted by the applicants. The fact that the sale of product happens through bidding and no material has been brought forward to show any other reason in increase in imports, it has been contended that the imports from Korea happen because they are of low price.
112. It is noted that the considering the deteriorating performance of the applicants in terms of decline in domestic sales and production, and reduced market share due to the increased imports it is a *res ipsa loquitur* of the fact that price injury is eminent due to increased imports in view of tariff concession.

E. 6 Conclusion

113. Based on above, the Director General concludes as follows: -

- The production and the capacity utilisation of the applicants have declined significantly.
- Despite having sufficient capacity to cater the entire demand in India, the Indian industry is operating at significantly low-capacity utilisation.
- The domestic sales and production of the applicants have remained at the same level over the period of investigation. While the demand has increased, the applicants have not been able to increase their domestic sales at the same rate.

- d. The demand has ~~been~~ increased considerably during the period from October '21 to March'22 as compared to the corresponding periods. However, the entire increased demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry. The imports have taken away the market share of the Indian industry.
 - e. The applicants and the Indian industry have faced a decline in their market share because of the increased imports from Korea RP.
 - f. The contribution of the applicants in the most recent period is lowest when seen over the period of investigation.
 - g. While the primary area of injury to the industry is in volume parameters, they have suffered a decline in profitability.
 - h. The imports from Korea PR are happening because they are priced lower.
114. Considering the performance of the domestic producers in respect of various parameters, it is concluded that the domestic industry has suffered serious injury as a result of duty concessions granted to Korean imports leading to increased imports of the product under consideration from the Republic of Korea at low prices.

I. CAUSAL LINK

115. A comprehensive evaluation of the performance of the domestic industry, as brought out hereinabove, demonstrates that the domestic industry has suffered serious injury. It is therefore examined whether the injury to the domestic industry is largely due to duty concessions and consequent increase in imports from Republic of Korea. It was examined if any factor other than increased Korean imports could have caused serious injury to the domestic industry. It is however expressly understood that the Korean imports need not be the sole cause of injury to the domestic industry. Industry might have been suffering injury due to other factors also and the same does not imply absence of injury to Korean imports.
- i. Imports from other countries
116. As examined above, the imports from the other countries cannot be a cause of injury to the Indian industry.
- ii. Demand for the product
117. Demand for the subject goods has increased over the period. Thus, there is no contraction of demand, which could have caused injury to the domestic industry.
- iii. Developments in technology
118. No evidence has been brought forward to show that technology for production of the subject goods has undergone any significant change which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, injury to the domestic industry cannot be attributed to these factors.
- iv. Conditions of competition and trade restrictive practices
119. No evidence has been brought forward to show that there are conditions of competition or trade restrictive practices. Therefore, injury to the domestic industry cannot be attributed to these factors.
- v. Changes in pattern of consumption
120. There has been no change in the pattern of consumption for the product, and thus, the domestic industry has not caused injury on this account.
- vi. Export performance
121. The Director General has considered the segregated data only for domestic operations and therefore, performance in the export operations cannot be a cause of injury. the domestic industry.
- vii. Performance of other products of the domestic producer
122. The data provided in the present application relates only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products those are being produced and sold by the domestic industry are not a cause of injury.
- viii. Productivity
123. The productivity of the domestic industry has followed the trend of production, and any injury caused is not on account of decline in productivity.

124. Based on the examination of the above, the Director General concludes that the applicants have not suffered injury due to any other factor. The following factors show causal link between the injury to the domestic industry and increased imports from Korea RP.
- With the increase in tariff concessions, imports from Korea RP have increased. The imports have increased in absolute terms and in relation to Indian production.
 - The increased imports have taken up the market share of the domestic industry and the Indian industry as a whole.
 - Due to the decline in the market share, the domestic industry has been seen a decline in their domestic sales and resultantly reduced its production.
 - The imports from Korea RP enjoy tariff concessions and are therefore available at lower prices.
 - The domestic industry has been forced to compete with the imports at low prices which has resulted in the domestic industry suffering decline in profits.
 - The Director General thus concludes that there exists a causal link between the increased imports and the consequent injury to the applicants.

J. ADJUSTMENT PLAN

125. It has been contended that the applicants did not file adjustment plan along with the application. The Director General notes that the applicants had provided the following in its application: -

“The industry is working on various cost reduction measures to reduce its costs. Cost reduction measures are directed towards reduction in raw materials costs, and conversion costs. The petitioners would supplement the same during the course of the proposed investigations.”

126. It was provided at the stage of initiation that the applicants will undertake efforts aimed at reducing cost. Therefore, the contention that no adjustment plan was provided cannot be accepted. It is also noted that the requirement of adjustment plan in the application is not with a view to decide on the need for initiation. At the stage of initiation only such information as is relevant for initiation is required to be considered. The adjustment plan is relevant for duration of duty at the time of final determination as provided under Rule 10, and not at the stage of initiation. The domestic industry in any case has given more elaborate explanation of the adjustment plan information contained in the application, after initiation of investigation and the same has been considered by the Director General.
127. The applicants have provided details of the adjustment plan proposed to be undertaken if the measures are imposed. The adjustment plan is focused on entering into long term contracts with the customers. It has been stated that at present, very limited customers buy the product under long term contract basis. Reduction in import volume will allow the industry to enter into such more contracts which will allow industry to increase its domestic sales and market share and follow formulae-based pricing of the final product linked to raw material. In addition, the adjustment plan also focuses on formulae-based purchase of raw material, increase in waste recovery, setting up of new machines etc. The Director General notes that the applicants have drawn an adjustment plan which will allow it to become competitive to imports.

K. PUBLIC INTEREST

K.1 Submissions made by the interested parties

128. The submissions made by the interested parties in respect of public interest are as follows-
- The steel industry has a value addition of 30-40% whereas the applicants have a value addition of only 5-10%. The imposition of bilateral measures will impact the steel industry.
 - If bilateral measures are imposed, it will lead to disruption in supply of the product under consideration which will impact the steel industry.
 - The impact on downstream products as quantified by the applicants is not substantiated.
 - Technical and metallurgical requirements of the user industry are not accurately met by Indian producers.
 - Indian steelmakers prefer Korean imports due to their uniformity of molybdenum, delivery time, supply stability, and after sale service.

- f. Value of the product under consideration is around ₹20,00,000 per MT and even 5% customs duty would imply impact of ₹100,000 per MT. The impact of this would be very high on the downstream steel producing user industry.
- g. China has a policy which penalizes exports of FeMo by not refunding VAT of 13%. With such policies in place, Korean imports provide a reliable source and consistent supply to the user industry in India.
- h. The exporters are only committed to meeting needs of Indian customers as a reliable supply chain partner providing quality products to the Indian market at a fair price.
- i. Several alloy steel producers are also small and medium scale producers therefore the contention that all consumers of subject goods are large scale industries is not correct.

K.2 Submissions made by the applicants.

129. The submissions made by the applicants in respect of public interest are as follows-

- a. Indian industry has a capacity to cater to the entire demand in the country and therefore, the imports are unnecessary.
- b. Bilateral measures will only remove tariff concessions. The industry is not seeking any additional tariff against imports.
- c. Public interest is not confined to consumer industry alone and covers in its ambit the domestic industry of the product under consideration as well.
- d. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports.
- e. The product under consideration forms insignificant part of the cost of downstream industry and removal of tariff concession would have insignificant impact on them.
- f. The impact of Rs 100 increase in price of the product under consideration does not have even 1% increase in the price of the downstream product.
- g. Content of the product under consideration in the final product of the end products is negligible which implies that the product under consideration forms insignificant part of the downstream products.
- h. Domestic producers belong to MSME sector and provides direct and indirect employment to around 5000 people. Restoration of basic custom duties will allow the small producers to get time to sustain their business without negative contribution.
- i. Jindal Stainless Limited and Jindal Stainless (Hisar) Limited, biggest consumers in India, are procuring their entire requirement of the product under consideration from the Indian industry alone. This shows that the Indian industry provides material in desired quantities.
- j. Given the high volume of demand met by Indian industry in past, it cannot be said that the domestic industry was unable to provide the material required by the consumers.

K.3 Examination by the Director General

130. There is no explicit requirement under the CEPA Agreement or the Rules to undertake public interest analysis. However, the Article 3.1 of the Agreement on Safeguards provides as below:

"A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."

131. The Director General examined whether imposition of safeguard measures shall be in the larger public interest. Though Article 3.1 does not provide any guidance on the manner of evaluation, the same, however, requires, inter alia, evaluation of impact of the safeguard measures on various stakeholders, and taking a balanced view keeping in view competing interests of different interested parties.

132. The Director General issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including applicants, exporters, importers, users and interested parties. The Director General sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by the Indian industry with the imports, ability of the users to switch sources and impact of the proposed measures on the users caused by removal of concessions.
133. The Director General notes that the present measures are not directed towards imposing any additional duty but only towards withdrawal of concession given earlier, that too in respect of imports from Korea alone. Imports from all other sources are totally unaffected by the proposed measures. Further, proposed measure would bring Korean imports at par with imports from other countries.
134. The Director General prescribed a user questionnaire in which the users are required to give information on cost on account of the product under consideration in the final cost and price of consumer's end products. The information provided by the users and by the applicants has been considered for the purpose of ascertain the impact of proposed measures.
135. As regards the argument that the imposition of the bilateral safeguard will lead to increase in the prices of the product under consideration and will impact the downstream industry, the Director General recognizes that the removal of concessions given to the product under consideration might affect the price levels of the product in India. However, the Director General has considered the impact of the increase in the prices of FeMo on the downstream product and it has been found that the impact will be insignificant on the downstream product and overall operations of the industry.
136. The share of the cost of the product under consideration in the turnover of the downstream products for the participating users is given below. It is seen that the cost of the product under consideration in the total turnover of the downstream product is insignificant. Therefore, it implies that the product under consideration forms a negligible part of the cost of the downstream product.

SN	Name of the company	Turnover of the products consumed (Rs./Lakhs)	Cost of PUC consumed (Rs./Lakhs)	Share
1	JSW Limited - Salem	***	***	0-5%
2	JSW Limited - Vijay Nagar	***	***	0-5%
3	Jindal Stainless (Hisar) Ltd.	***	***	0-5%
4	Jindal Stainless Ltd.	***	***	0-5%
5	Saarloha Advanced Materials Private Limited	***	***	5-10%
6	Sunflag Iron and Steel Co. Ltd.	***	Not provided	

Information in Rs Lacs as per the EQR filed by the users.

137. The Director General has additionally examined the impact of the proposed measures on the price of the downstream product. The present investigation is a bilateral safeguard investigation and considering the nature of measures, the Director General has considered the impact on the downstream product by taking into consideration an increase in the price of the product by 5%. It is seen that in majority of the case, the impact of the proposed measures on the prices of the downstream products, the impact is less than 1%. Therefore, considering the size of the downstream industry and the share of the product under consideration in the final cost of the downstream products, it is seen that the imposition of bilateral safeguard will immaterial impact on the downstream industry.
138. It is seen that there is no demand and supply gap in India. Against an estimated demand of 10,000 MT in the country, the Indian industry has the capacity of around 20,000 MT. Therefore, the removal of concessions will not lead to any shortage in the product in the country.
139. The imports of product from Korea RP have driven out the other imports, and imposition of bilateral measures will bring imports from various sources at par, thus encouraging imports from other countries. Director General also notes that there are a number of producers of subject goods in India which are likely to compete not just with each other but also with imports of like article in India. Therefore, a healthy competition between the domestic producers and imports will prevail in the Indian market.

L. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

140. Regarding imposition of bilateral safeguard measures, Rule 10 of India - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 states as follows:

10. Final findings -

(1) The Director General shall, within eight months from the date of initiation of the investigation, or within an extended period not exceeding one year from the date of initiation of the investigation, as the Central Government may allow, determine whether, – (a) the increased imports of the originating good under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry; and (b) a causal link exists between the increased imports of the originating good due to the reduction or elimination of a custom duty under the Trade Agreement and serious injury or threat of serious injury.

(2) The Director General shall also give his recommendation regarding bilateral safeguard measure which would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

(3) The Director General shall also make his recommendations regarding the duration of the bilateral safeguard measure: Provided that where the period recommended is more than one year, the Director General may also recommend progressive liberalisation of the bilateral safeguard measure at regular intervals during the period of application, adequate to facilitate adjustment.

141. After examining the above, the Director General notes as follows: -

- a. There is no known difference in the subject goods produced by the applicants and imported from Republic of Korea. The applicants supply like article to the imported product.
- b. No evidence has been brought forward by the interested parties to substantiate that the product supplied by the Korean producers is of superior purity or quality as compared to the Indian industry.
- c. The application has been filed by the producers constituting 40% share in total production. Further, the supporters account of 20% share in the Indian production.
- d. The applicants satisfy the requirements of standing in terms of the Rules.
- e. Consideration of a substantial long period has ensured that the imports have been compared in the pre concession, during concession and post concession period.
- f. The imports of the product under consideration have increased in absolute terms and in relation to Indian production and total imports.
- g. The imports of FeMo increased when the duties were eliminated. The imports increased again in the most recent period and the period post the most recent period.
- h. The imports of FeMo have increased because of the tariff concessions. No reason has been brought forward by the interested parties to justify the increased imports.
- i. Imports of the product from Republic of Korea have increased and constitute increased imports within the meaning of the Rules and Korea-India CEPA.
- j. The Indian industry has sufficient capacity to cater the entire demand in the country. However, it continues to operate at low-capacity utilisation.
- k. The applicants have been unable to increase their domestic sales in line with the increase in the demand.
- l. The imports have increased and taken away the market share of the applicants.
- m. The applicants have seen a decline in the volume parameters such as market share and sales. Therefore, they have been forced to reduce their production.
- n. The demand has increased considerably during the period from October '21 to March '22 as compared to the corresponding period. However, the entire increased demand has been met through Korean import even though there is a substantial surplus capacity available with the domestic industry.
- o. The applicants have suffered a decline in profitability.
- p. The increased imports have caused serious injury to the domestic industry.
- q. No other factor as a cause of injury has been established by the interested parties.
- r. There exists a causal link between the increased imports and serious injury to the domestic industry.

- s. The product under consideration does not form a significant part of the operations of the downstream industry. Therefore, the impact of the bilateral safeguard measures on the downstream industry will be insignificant.
142. It is thus considered appropriate to recommend bilateral safeguard measure in terms of Rule 10 of India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017. Accordingly, the Director General recommends increasing the rate of customs duty on imports of subject goods originating in Korea RP to the lower of below:
- a. Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods as on the date of application of Bilateral safeguard measure or
- b. Most Favoured Nation applied rate of customs duty on the subject goods as on the day immediately preceding the date of entry into force of India-Korea CEPA.
143. The measure is recommended for a period of two years as per table below from the date of issue of the notification to be issued by the Ministry of Finance in this regard.

Year	Bilateral safeguard measure
Year 1	Increase the rate of customs duty @ 100% to the level of Most Favoured Nation applied rate of customs duty
Year 2	Increase the rate of customs duty @ 75% to the level of Most Favoured Nation applied rate of customs duty

ANANT SWARUP, Director General